

विश्व जल दिवस विशेषांक

31 मार्च, 2021

40 रुपए



इंडिया टुडे



बूंद-बूंद प्रयास

60 करोड़ भारतीयों के सामने भीषण जल संकट है. चौखट पर खड़ी त्रासदी को दालने के लिए भारी सरकारी खर्च और अभिनव प्रयोगों की दरकार

जलपान
गुजरात में सुरेंद्रनगर
जिले के राजसीतापुर
गांव की 21 वर्षीया पिकू
बेन चेक डैम के पास
लोटे से पानी पीते हुए

VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM



CLICK TO WATCH THE FILM



**सच्ची खबर
अभी ज़िंदा है**



प्रधान संपादक की कलम से

पानी जिंदगी है। मानव शरीर को इसकी जरूरत है और हम जो खाना खाते हैं उसे उगाने के लिए भी पानी की जरूरत है। आधुनिक जीवन के कई दूसरे प्रयोजनों, मसलन साफ-सफाई, के लिए भी इसकी जरूरत है।

प्राचीन काल में मानव आबादियां पानी के सुरक्षित स्रोतों के इर्दगिर्द बसी थीं। इसकी आपूर्ति तयशुदा मान ली जाती है मानो यह अंतहीन हो। यह खामोश संकट है जो दुनिया के कई हिस्सों में घुमड़ रहा है। आज जब हम अपनी स्वतंत्रता की 75वीं सालगिरह की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने ज्यादातर नागरिकों को पीने के साफ पानी की आपूर्ति नहीं कर पाना भारतीय राज्य व्यवस्था की सबसे बड़ी नाकामियों में से एक है। ग्रामीण अखबार *गांव कनेक्शन* के 2019 के एक सर्वे ने बताया कि हालात कितने खराब हैं। इस अध्ययन से पता चला कि 39.1 फीसद भारतीय महिलाओं को पानी भरकर लाने के लिए घरों से बाहर निकलना पड़ता है। सर्वे में शामिल 19 राज्यों की साठ फीसद महिलाओं ने कहा कि वे पानी लाने के लिए दिन में दो बार एक से पांच किलोमीटर पैदल चलती हैं। कल्पना कीजिए कि कितने घंटे ये लाखों महिलाएं उस एक चीज के लिए रोज व्यतीत करती होंगी जिसे हम शहरों के लोग बस एक नॉब घुमाकर हासिल कर लेते हैं। सोचिए कि इसकी कीमत उन्हें कितने अवसरों से हाथ धोकर चुकानी पड़ती है—यह समय वे शिक्षा, रोजगार या अपने परिवार की देखभाल पर लाभदायक ढंग से बिता सकती थीं। 70 फीसद के करीब भारतीयों को पीने के लिए नल का जल नसीब नहीं है। वितरण समस्या का महज एक हिस्सा है। भारत तेजी से पानी के खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है। देश का भविष्य अंधकारमय नजर आता है, वह भी तब जब धरती की 18 फीसद आबादी यहां रहती है जिसे केवल 4 फीसद मीठा पानी उपलब्ध है। आबादी बढ़ रही है और सतह जल नाकाफी है, ऐसे में संकट के और तीव्र होने की ही आशंका है। भारत में पानी की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 50 साल पहले 5,000 घन मीटर थी जो आज घटकर 1,500 घन मीटर रह गई है। जैसा कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हमारे साथ एक इंटरव्यू में कहा, समस्या “वाकई, वाकई बहुत बड़ी” है।

वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का 2020 का एक अध्ययन कहता है कि 2050 तक 30 भारतीय शहर ‘पानी का गंभीर संकट’ झेल रहे होंगे। वजहें खोजने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे शहर दुनिया के सबसे घने बसे शहरों में हैं और पेयजल सहित बुनियादी सिविक इन्फ्रास्ट्रक्चर मुहैया करवाने की प्राधिकारियों की क्षमता से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं।

इस सबसे कीमती प्राकृतिक संसाधन तक पहुंचने के लिए कई भारतीयों को गैरमामूली चरम रास्ते अपनाने पड़े हैं। जल शक्ति मंत्रालय का अनुमान है कि भारत हर साल 253 अरब घन मीटर भूमिगत पानी उलीचता है, जो 250 डल झीलों को खाली कर देने के बराबर है। भारत दुनिया का एक चौथाई भूमिगत पानी निकालता है, जिसने देश के कई हिस्सों को तीव्र संकट की तरफ धकेल दिया है। फिर भी यह कभी पूरा नहीं पड़ता। भारत की पानी की कहानी भीषण कुप्रबंध, प्रचुर बारिश के पानी को रोकने और जमा करने या किफायत से उसका इस्तेमाल करने की नाकाबिलियत की कहानी है। देश के कई हिस्से बाढ़ से त्रस्त हैं तो कई दूसरे एकदम सूखे। तीस फीसद भारत पानी के तीव्र संकट वाले इलाकों में रहता है। दोहरी तकलीफ यह कि करीब 89 फीसद भूमिगत जल कृषि के लिए उलीचा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने अब भी ड्रिप इरिगेशन सरीखे सूक्ष्म सिंचाई के तरीके नहीं अपनाए और हमारी कृषि उत्पादकता दर दुनिया की बदतरीन दरों में से एक है।

संकट की गंभीरता को पहचानकर इस सरकार ने जल जीवन मिशन के ‘हर घर नल से जल’ कार्यक्रम के तहत सालाना 3 करोड़ नए घरों में



मुक्त प्रवाह ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर राज चेंगप्पा और ग्रुप फोटो एडिटर बंदीप सिंह गुजरात में ढांकी के नर्मदा पम्पहाउस के पास

नल का जल पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। मोदी सरकार ने इस काम के लिए 3.6 लाख करोड़ रुपये रखे हैं और इसकी प्रगति की निगरानी के लिए उन्नत टेक्नोलॉजी काम में लाई जा रही है। ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर (पब्लिशिंग) राज चेंगप्पा ने इस विषय पर विशेष अंक का तानाबाना बुना है, जिसके लिए संवाददाताओं ने देश भर के दौरे किए और मिशन की प्रगति का जायजा लिया। हमें यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि समुदाय जल योद्धाओं में बदल गए हैं और अपनी जिंदगी के इस बेहद अहम मसले के नए-नवेले समाधान निकाल रहे हैं।

हमारी टीम ने अहमदाबाद के नजदीक नटवरगढ़ गांव का दौरा किया। यह पानी के संकट से ग्रस्त गांव था, जिसे हमने 2003 में अपनी पत्रिका के आवरण पर पेश किया था। यह गांव अब पानी से लबालब है, उस नर्मदा नहर की बदौलत जो 2018 में यहां पानी लेकर आई। दूसरे नवोन्मेषी समाधान पानी की निगरानी के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। एक और अहम बदलाव पानी के वितरण की परियोजनाओं में सामुदायिक भागीदारी है। चेंगप्पा ने गुजरात की एक पानी समिति का दौरा किया जहां महिलाएं समूचा जल वितरण नेटवर्क चलाती हैं। ड्रिप इरिगेशन सरीखी सूक्ष्म सिंचाई योजनाएं हैं और कम खर्च वाली टेक्नोलॉजी—पुश्ते बांधना—या बड़ी परियोजनाएं भी, मसलन गुजरात की एक वह परियोजना जिसमें राज्य सरकार अपने सूखे इलाकों में नहरों के जरिए नर्मदा का पानी और खुशहाली लेकर आई। केंद्र का जल जीवन मिशन 2024 तक 12.7 करोड़ ग्रामीण घरों को नल से पेयजल देने का वायदा करता है। इस एक योजना की बदलावकारी संभावनाएं हैरान कर देने वाली हैं।

अलबत्ता इन तमाम पहलों की कुंजी उनका टिकाऊ होना है। संयुक्त राष्ट्र का 2020 का एक अध्ययन बताता है कि पानी और जलवायु परिवर्तन आपस में गहराई से जुड़े हैं। रिपोर्ट कहती है कि दक्षिण एशिया को 2030 तक बाढ़ों की कीमत हर साल 215 अरब डॉलर (15.6 लाख करोड़ रुपये) से चुकानी पड़ सकती है; दूषित जल स्रोत जल बिंदुओं और साफ-सफाई की सुविधाओं को नष्ट कर रहे हैं। हमारे सामने कहीं ज्यादा बड़ी चुनौती खपत से है—अनुमान सुझाते हैं कि अगर हम मौजूदा रफतार से पानी की खपत जारी रखते हैं तो भारत के पास 2030 तक अपनी जरूरत का महज आधा पानी होगा। बड़ा संकट बस नौ साल दूर है। अगर हम सही विकल्प नहीं चुनते, तो तय मानिए पानी को लेकर विवाद, विरोध, अशांति, लड़ाई-झगड़े और यहां तक कि युद्ध भी भड़क सकते हैं। यह नया तेल होगा बशर्ते यह पहले ही न हो गया हो।

अरुण पुरी
(अरुण पुरी)

चेयरमैन और प्रधान संपादक: अरुण पुरी
वाइस चेयरपर्सन: कली पुरी
ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर: दिनेश भाटिया
ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर: राज चेंगप्पा
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर: मनोज शर्मा
एडिटर: अंशुमान तिवारी
सीनियर एडिटर: मोहम्मद वकास
एसोसिएट एडिटर: शिवकेश मिश्र, शुभम शंखधर
असिस्टेंट एडिटर: मनीष दीक्षित, सुजीत ठाकुर
राज्य ब्यूरो: आशीष मिश्र (लखनऊ), अमिताभ श्रीवास्तव (पटना),
रोहित पारेहार (जयपुर), एम.जी. अरुण (मुंबई), राहुल नरोन्हा
(भोपाल), अमरनाथ के. मेनन (हैदराबाद)
ग्रुप क्रिएटिव एडिटर: नीलांजन दास
एसोसिएट आर्ट डायरेक्टर: चंद्रमोहन ज्योति
चीफ डिजाइनर: असित राय
ग्रुप फोटो एडिटर: बंदिप सिंह
फोटो डिपार्टमेंट: यासिर इकबाल, राजवंत रावत,
चंद्रदीप कुमार, मंदार सुरेश देवधर (मुंबई)
चीफ फोटो रिसर्चर: प्रभाकर तिवारी
प्रिंसिपल फोटो रिसर्चर: सलोनी वैद
प्रोडक्शन चीफ: अभिनव पुगला
एसोसिएट पब्लिशर: अनिल फर्नांडीस
इंपेक्ट टीम
सीनियर जनरल मैनेजर: जीतेंद्र लाड (वेस्ट)
जनरल मैनेजर: मयूर रस्तोगी (नॉर्थ),
उषेंद्र सिंह (बेंगलुरु)
डिप्टी जनरल मैनेजर: इंदनील चटर्जी (ईस्ट)
ग्रुप चीफ मार्केटिंग ऑफिसर: विवेक मल्होत्रा
सेल्स एवं ऑपरेशन
सीनियर जनरल मैनेजर: दीपक भट्ट (नेशनल सेल्स)
जनरल मैनेजर: विपिन बग्गा (ऑपरेशंस)
डिप्टी जनरल मैनेजर: राजीव गांधी (नॉर्थ)
रीजनल सेल्स मैनेजर: सैयद आसिफ सलीम (वेस्ट)
डिप्टी रीजनल सेल्स मैनेजर: एस. परमशिवम (साउथ)
सीनियर सेल्स मैनेजर: पीयूष रंजन दास (ईस्ट)



वर्क: 35; अंक: 18; 25-31 मार्च, 2021; प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित

- संपादकीय कॉर्पोरेट कार्यालय: लिफ्टिंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, इंडिया टुडे ग्रुप मीडियाप्लेक्स, एफसी-8, सेक्टर 16-ए, फिल्म सिटी, नोएडा-201301, फोन: 0120-4807100;
- ग्राहकी चंदा भेजें: इंडिया टुडे (हिंदी), पो. बॉक्स 114, नई दिल्ली-110001
- ग्राहक सेवा: कस्टमर केयर, इंडिया टुडे ग्रुप, सी-9, सेक्टर-10, नोएडा (उत्तर प्रदेश)-201301, टोल फ्री फोन नं. 1800 1800 100 (बीएसएनएल/एमटीएनएल लाइनों से) फोन: दिल्ली, फरीदाबाद से (95120) 2479900; शेष भारत से (0120) 2479900. (सोम से शुक्र-सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक), फैक्स: (0120) 4078080. ई-मेल: wecare@intoday.com
- सर्कुलेशन कार्यालय: लिफ्टिंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, सी-9, सेक्टर-10, नोएडा (उत्तर प्रदेश)-201301
- इंपेक्ट कार्यालय: 1201, 12वां तल, टावर 2ए, वन इंडियाबुल्स सेंटर, (जुपिटर मिल्स) एस.बी. मार्ग, लोअर फरेल (पश्चिम)-मुंबई-400013. फोन: 022-66063355 फैक्स: 022-66063226
- क्षेत्रीय विज्ञापन कार्यालय: ए1-ए2, एनके सेंटर, विनूज्य निकुंज, उद्योग विहार, फेज-5, गुडगांव, हरियाणा, फोन: 0124-4948400;
- 201-204 रिचमंड टावर्स, द्वितीय मंजिल, 12 रिचमंड रोड, बंगलुरु-560 025 फोन: 2212448, 226233, टेलेक्स: 0845-2217 INTO IN. फैक्स: 080-2218335.
- रजिस्टर्ड कार्यालय: एफ-26, फर्स्ट फ्लोर, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001
- लिफ्टिंग मीडिया इंडिया लि. विश्व भर में सर्वाधिकार सुरक्षित. किसी भी रूप में सामग्री की नकल प्रतिबंधित. इंडिया टुडे अनिमित्तित प्रकाशन सामग्री को लौटाने की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता.
- सभी विवादों का निवारण दिल्ली/नई दिल्ली की सीमा में आने वाली सक्षम अदालतों और फोरमों में किया जाएगा.
- लिफ्टिंग मीडिया इंडिया लि. के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक मनोज शर्मा द्वारा एफ-26, फर्स्ट फ्लोर, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और यॉमसोन प्रेस इंडिया लि., 18-35, माइलस्टोन, दिल्ली-मथुरा रोड, फरीदाबाद-121 007 (हरियाणा) में मुद्रित. संपादक: राज चेंगप्पा



14

आवरण क्या

प्यासा भारत

देश के आसन्न भीषण जल संकट से निपटने के लिए अभिनव विचार और भारी खर्च की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी

बंदिप सिंह

ग्रामीण पेयजल

20 प्यास है कि बुझती ही नहीं

शहरी आपूर्ति

28 मंडराती मुश्किल

संरक्षण

36 चाहेंगे तो बचाएंगे

सिंचाई

44 बूंद-बूंद से खेती

भूजल

50 गहरा होता पानी

नममि गंगे

56 धार को चाहिए रफ्तार



64

कॉन्वलेव

दक्षिण की तान

चुनाव की दहलीज पर खड़े दक्षिण भारत के तीन राज्यों के नेताओं, अभिनेताओं व हस्तियों ने अनेक नाजुक मुद्दों का धारदार विश्लेषण किया

आवरण फोटो: बंदिप सिंह

पाठकों के लिए सूचना: कभी-कभी आपको इंडिया टुडे पत्रिका में 'इम्पैक्ट फीचर' या 'एडवर्टोरियल' या 'फोकस' के पन्ने नजर आएंगे. ये विज्ञापन होंगे और इन्हें बनाने में पत्रिका के संपादकीय स्टाफ शामिल नहीं होते.



पाठकों को सलाह दी जाती है कि पत्रिका में प्रकाशित किसी भी वस्तु, सेवा या व्यक्ति के विज्ञापन और प्रचार से संबंधित सामग्री से वचनबद्धता कायम करने, पैसा भेजने या खर्च करने से पहले उचित जांच-पड़ताल कर लें. विज्ञापनदाताओं के किसी भी दावे का उत्तरदायित्व इंडिया टुडे ग्रुप का नहीं है. ऐसे किसी भी तरह के दावों को विज्ञापनदाता अगर नहीं पूरा करता है तो इंडिया टुडे ग्रुप के प्रकाशकों के मुद्रक, प्रकाशक, एडिटर-इन-चीफ और एडिटर इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे.

INDIA
TODAY

BREAKING NEWS

JUST A TAP AWAY



DOWNLOAD THE APP NOW

AVAILABLE ON



सुर्खियां

सहानुभूति बोट

व्हीलचेयर पर बैठकर एक
जनसभा को संबोधित करतीं
ममता बनर्जी



बंगाल
की जंग

देबज्योति चक्रवर्ती

नंदीग्राम का संग्राम

रोमिता दत्ता

को

लकाता से
लगभग 75
किलोमीटर
दक्षिण-पश्चिम
में नंदकुमार

क्रॉसिंग पर, चार दिशाओं में बंटने से पहले हाइवे एक शानदार लूप लेता है। वैसे, कौन-सा मोड़ नंदीग्राम लेकर जाएगा इसे बताने वाले साइनबोर्ड तो गिने-चुने हैं, पर सियासी संदेश वाले साइनबोर्ड्स की भरमार हैं। इनमें से दो होर्डिंग्स अन्य पर हावी हैं। एक तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) का जिस पर 'बांग्ला निजेर मेये केई चाये (बंगाल को अपनी बेटी चाहिए)' लिखा है और दूसरा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का है जिस पर मोटे-मोटे अक्षरों में 'नंदीग्राम भूमिपुत्र सुवेंदु' (नंदीग्राम की मिट्टी का लाल, सुवेंदु)

अंकित है। हाइवे पर लगे ये होर्डिंग्स 2021 के विधानसभा चुनाव के सबसे दिलचस्प मुकाबले, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके पूर्व मंत्री सुवेंदु अधिकारी के बीच नंदीग्राम की लड़ाई—की दिशा बताते हैं।

नंदीग्राम में, कई अंडरकरंट—जैसे सत्ता-विरोधी रुझान—भी हैं जो स्थानीय लोगों के साथ बातचीत में उभरकर आता है। नंदीग्राम के रेयापारा के रहने वाले अमर बाग कहते हैं, "पिछले तीन साल में सत्ता में बदलाव की मांग तेज हुई है। टीएमसी ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए लाभार्थी सूचियों का राजनीतिकरण कर दिया है और अपने पार्टी सदस्यों को जॉब कार्ड दिए हैं। मेरे साथ बदसलूकी की गई, मेरा चाय का खोखा तोड़ दिया गया और मेरा जॉब कार्ड रद्द कर दिया गया क्योंकि मैंने पार्टी के विरुद्ध बयान दिया

था।" अन्य स्थानीय लोग भी कई तरह की जबरन सियासी वसूली के आरोप लगाते हैं।

सरकार के प्रति लोगों के मन में दबा गुस्सा पिछले कुछ समय से वोटों के रूप में बाहर निकलते देखा गया है। 2016 में तामलुक लोकसभा सीट, जिसमें नंदीग्राम आता है, के उपचुनाव में भाजपा को करीब 1,96,000 वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में, यह आंकड़ा बढ़कर करीब 5,34,000 हो गया तथा इसने भाजपा और टीएमसी के वोटों के अंतर को नाटकीय रूप से पाट दिया। टीएमसी को करीब 7,34,000 वोट मिले थे। अब टीएमसी के कद्दावर नेता सुवेंदु अधिकारी भाजपा में चले आए हैं तो इससे उसकी पकड़ और मजबूत हुई है।

सुवेंदु अपनी नई पार्टी में सहज हो चुके हैं और एक नए अंडरकरंट—धार्मिक

अपील—का भरपूर लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं. 'जय श्री राम' के नारे के उपयोग के अलावा, वे धार्मिक ध्रुवीकरण को भी आगे बढ़ा रहे हैं. वे भाजपा की चिरपरिचित शैली में अपने क्षेत्र की हिंदू और अनुसूचित जाति की आबादी को यह कह रहे हैं कि टीएमसी अगर सत्ता में लौटी तो उनके लिए अपने धर्म का पालन मुश्किल हो जाएगा.

सुवेंदु ने यह भी तर्क दिया है कि ममता ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्हें 'नंदीग्राम से प्रेम' है, बल्कि इसलिए कि इस निर्वाचन क्षेत्र में भारी मुस्लिम आबादी—करीब 25 से 30 फीसद—को देखते हुए वे इसे अपने लिए सुरक्षित सीट मान रही हैं. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी आरोप लगाए कि ममता अपने लिए सीट चुनने में भी 'मुस्लिम तुष्टिकरण के हथकंडे' का इस्तेमाल कर रही हैं. वैसे सुवेंदु यह भी कहते हैं कि वे '30 फीसद'—नंदीग्राम के मुस्लिम वोटों के संदर्भ में—से चिंतित नहीं हैं और उन्हें भरोसा है कि '70 फीसद' मतदाता सही फैसला लेंगे.

नंदीग्राम की हिंदू आबादी को अपनी अपील में, ममता भी धार्मिक भावनाओं को भुनाने की कोशिश में हैं. 9 मार्च को यहां अपनी पहली सार्वजनिक रैली में उन्होंने भाजपा नेताओं को चुनौती दी कि वे हिंदू कार्ड खेलना बंद करें. ममता ने कहा, "मैं एक हिंदू ब्राह्मण परिवार की बेटी हूँ. मैं चंडी श्लोक (दुर्गा स्तुति) करने के बाद ही घर से निकलती हूँ." उन्होंने अपनी दो दिवसीय यात्रा का बड़ा हिस्सा नंदीग्राम के मंदिरों में दर्शन-पूजन में बिताया और 19 मंदिरों में हाजिरी लगाई. स्थानीय निवासी जयंती जना का मानना है कि भाजपा यह प्रचारित करने की कोशिश कर रही है कि ममता 'हिंदू नहीं' हैं. वे कहती हैं, "चाहे कितना भी दुष्प्रचार किया जाए, ममता हिंदू ही रहेंगी."

नंदीग्राम में कई लोग धार्मिक ध्रुवीकरण और धर्म के आधार पर किसी के सियासी झुकाव के अनुमान से असहज हैं. शेरखान चौक के मोहम्मद अजीज कहते हैं, "हम मुसलमान अपना मुंह खोलने से डरते हैं. भाजपा हमें संदेह के साथ देखती है क्योंकि उन्हें लगता है कि हम दीदी के (ममता के) समर्थक हैं." पर कुछ किलोमीटर दूर चौरंगी बाजार में माहौल अलग है जहां ममता के भरोसेमंद सहयोगी अबू ताहिर समर्थकों को जमा कर रहे हैं. उसके तुरंत बाद, एक विरोध मार्च शुरू होता है. टायर जलाए गए, 'मीर जाफ़र' और 'गद्दार' के नारे लगाते हुए मोर्चा



धार्मिक मोड़

नंदीग्राम में प्रचार करते सुवेंदु अधिकारी

नंदीग्राम में कई लोग धार्मिक ध्रुवीकरण और धर्म के आधार पर किसी के सियासी झुकाव के अनुमान से असहज हैं

आगे बढ़ता है. टीएमसी छोड़ने के बाद सुवेंदु को गद्दार के रूप में दर्शाने की कोशिश हो रही है. ताहिर कहते हैं, "एक मंत्री के रूप में इतने लंबे वक्त तक सभी फायदों का आनंद लेने और लाभ के पदों पर अपने परिवार के सदस्यों को नियुक्त करने के बाद, उन्होंने टीएमसी छोड़ दी और ममता पर वंशवादी राजनीति का आरोप लगा रहे हैं. उनकी बात पर कोई यकीन नहीं करने वाला."

ताहिर और टीएमसी के एक अन्य नेता शेख सूफियन का कहना है कि नंदीग्राम में मुकाबला कांटे का होगा, पर पलड़ा ममता के पक्ष में झुका है. ताहिर पूछते हैं, "अगर दीदी यहां व्हीलचेयर पर आती हैं, तो क्या नंदीग्राम इसे नजरअंदाज करेगा? इसके अलावा, ये हम (वह और सूफियन) ही थे जो सुवेंदु के लिए बूथ स्तर पर चुनाव प्रबंधन का जिम्मा संभालते थे और हम बखूबी जानते हैं कि मुकाबले को कैसे अपने पक्ष में मोड़ना है."

जादवपुर विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर इमान कल्याण लाहिड़ी कहते हैं कि नंदीग्राम आंदोलन के दो प्रमुख चेहरों—ममता और सुवेंदु—का अब एक-दूसरे के खिलाफ होना दुखद है. वे कहते हैं, "लोग अपने-अपने चहेते नेताओं के पीछे खड़े हो रहे हैं और उनमें स्पष्ट विभाजन है. पर भाजपा को जो फायदा मिल रहा है उसके पीछे असली वजह, उपेक्षा और विकास के धरातल पर न पहुंचने का लंबा इतिहास है. वंचितों और भेदभाव के शिकार लोगों के लिए धर्म एक तात्कालिक कारण के रूप में उभरकर आया है." ■

बाहर जाएँ तो
सिर्फ खुशियाँ लाएँ,
बीमारियाँ नहीं.
करें स्वामला से शुरुआत.



स्वामला से
शुरुआत

रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाए

पाचन सुधारे

शारीरिक क्षमता सुधारे

एकाग्रता और केन्द्रित होने में सुधार करे

यौवन अवस्था बरकरार रखे

स्वास्थ्य की पुनर्स्थापना में सहायता करे

हर मौसम में संपूर्ण स्वास्थ्यवर्धक

वयस्कों के लिए
1 बड़ा चम्मच (15 ग्राम) दिन में दो बार

बच्चों के लिए (12+ वर्ष)
1 छोटा चम्मच (5 ग्राम) दिन में दो बार



“मैंने तो नए निर्णय लोगों के पक्ष में लिए”

उत्तराखंड सरकार में नेतृत्व त्रिवेन्द्र सिंह रावत की बजाए तीरथ सिंह रावत को क्या मिला कार्यकर्ताओं का हुजूम जो अब तक मुख्यमंत्री आवास से दूरी बनाए हुए था, नए मुख्यमंत्री के घर और दफ्तर में उमड़ता दिख रहा है। राज्य के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में 10 मार्च को शपथ लेने के बाद तीरथ ताबड़तोड़ फैसले लेकर अपनी ही सरकार के पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र के फैसलों को पलटने में गुरेज नहीं कर रहे। उनके इसी अंदाज ने उनकी लोकप्रियता को अचानक बढ़ाकर उनके पक्ष में माहौल बना दिया है। हरिद्वार के नाराज चल रहे संत जहां उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, वहीं चारधाम देवस्थानम बोर्ड से नाराज चारधाम से जुड़े पुरोहित उनके मुख्यमंत्री बनने पर आतिशबाजी करते दिखे। तीरथ ने चार नए मंत्री बनाकर नाराज माने जा रहे वरिष्ठ विधायकों को भी सरकार में भागीदारी का मौका दिया है। नए मंत्रियों में डीडोहाट से बिशन सिंह चुफाल, कालाढूंगी से बंशीधर भगत, मसूरी से गणेश जोशी को कैबिनेट मंत्री और हरिद्वार ग्रामीण से यतीश्वरानंद को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के बतौर शपथ दिलाई गई है।

प्रदेश के पौड़ी जिले को मंत्रिमंडल में इस बार भी खासी तरजीह मिली है जबकि उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग जिलों से कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। त्रिवेन्द्र मंत्रिमंडल में कद्दावर मंत्री रहे मदन कौशिक को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाते हुए उसमें शामिल रहे अन्य सभी छह मंत्रियों को बरकरार रखा गया है। जातीय संतुलन को देखें तो नए मंत्रिमंडल में चार ब्राह्मण, पांच राजपूत और दो अनुसूचित जाति और एक गुर्जर समाज के मंत्री शामिल हैं। मुख्यमंत्री खुद भी राजपूत हैं। क्षेत्रीय संतुलन के अनुसार, कुमाऊं मंडल से पांच और गढ़वाल से छह मंत्री बनाए गए, जबकि मुख्यमंत्री भी गढ़वाल से ही हैं। तीरथ जैसे लो प्रोफाइल रहने वाले नेता के उभार से पार्टी कार्यकर्ताओं में एक सकारात्मक संदेश गया है। वहीं, विपक्ष भी इस अचानक सामने आए चेहरे के खिलाफ कुछ खास करने की स्थिति में नहीं है। हालांकि उसकी एक ही रट है कि चार साल के बाद नए मुख्यमंत्री को लाना सरकार की विफलता को स्वीकारना है।

भाजपा सरकार के चार साल पूरे होने पर 18 मार्च को त्रिवेन्द्र सरकार के प्रस्तावित जश्न को भी टाल दिया गया है। तीरथ सरकार के जो फैसले चर्चा में हैं उनके कोविड-19 के नियम तोड़ने वालों के मुकदमे वापस लेना, चार साल के विकास कार्यों के लिए विधानसभा स्तर पर किए जाने वाले कार्यक्रम को स्थगित करना, घाट नंदप्रयाग सड़क चौड़ीकरण मामले में आंदोलनकारियों से मुकदमे वापस लेना और उनकी मांग को पूरा करना, गैरसैंण कमिशनरी और देवस्थानम बोर्ड से जुड़े फैसले पर पुनर्विचार करना, हरिद्वार कुंभ को भव्य बनाने के साथ ही उसमें श्रद्धालुओं के आने पर लगी रोक को हटाने जैसे फैसले शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र तीरथ के फैसलों से असहज नजर आए। उन्होंने हरिद्वार में कहा कि देश में कोविड मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है, कुंभ राज्य का नहीं बल्कि देश-दुनिया का पर्व है इसलिए जोखिम नहीं लेना चाहिए।

तीरथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद सल्ट विधानसभा का चुनाव 17 अप्रैल को होना है। उनके मुख्यमंत्रित्व काल में यह पहला चुनाव होगा, साथ ही उनकी पहली परीक्षा भी। इसके बाद उन्हें पौड़ी लोकसभा से इस्तीफा देने के बाद खुद भी चुनकर विधानसभा पहुंचना है। उनके लिए कौन सीट छोड़ेगा, वे कहां से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, यह अभी तय नहीं है। हालांकि बद्रीनाथ विधानसभा से विधायक महेंद्र भट्ट उनके लिए सीट छोड़ने का ऑफर दे चुके हैं। कोटद्वार से विधायक और मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत भी उनकी लोकसभा सीट से लड़ने की इच्छा के साथ उनके लिए अपनी कोटद्वार विधानसभा सीट त्यागने को इच्छुक बताए जा रहे हैं।

भगत सिंह कोशियारी, नारायण दत्त तिवारी और हरीश रावत के बाद लगता है कि तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के चौथे ऐसे मुख्यमंत्री (सीएम) हैं जिनके आसपास भारी भीड़ जुट रही है। सुबह से रात बारह बजे तक वे कार्यकर्ताओं, अधिकारियों और आम जनता से घिरे दिख रहे हैं। लोगों को उनसे काफी अपेक्षाएं हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से बातचीत करके अखिलेश पांडे ने भविष्य की उनकी योजनाओं के बारे में जानने की कोशिश की। बातचीत के मुख्य अंश:

सवाल: अचानक मुख्यमंत्री कैसे बन गए आप, दौड़ में तो कुछ और ही नाम थे ?

सीएम: न तो मैं दौड़ में था, न मैंने इस पद की कभी कल्पना की थी। मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता यहां तक पहुंचेगा, सोच भी नहीं सकता था। मैं शुरू से आरएसएस से जरूर जुड़ा था, विद्यार्थी परिषद का काम लगातार संगठन मंत्री के बतौर करते हुए यूपी में युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष रहा, उत्तराखंड बनते वक्त एमएलसी था, तो उत्तराखंड बनने पर शिक्षा मंत्री बनकर काम किया। उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष भी रहा। जो भी जिम्मेदारी पार्टी ने दी निभाता गया। जब कहा चुनाव नहीं लड़ना तो चुनाव लड़वाने में लग गया। जब कहा कि संसद का चुनाव लड़ना है, वह भी लड़ा। आज अचानक प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा जी ने तय किया तो मुख्यमंत्री भी बन गया।

● क्या आपको कोई भनक थी कि हाइकमान आपके बारे में सोच रहा है ? कोई कल्पना ही नहीं थी, केवल यह कहा



सभी फोटो: रामेश्वर गौड़

गया था कि विधानमंडल दल की बैठक में सांसदों को भी जाना है। इसी कारण मैं भी वहां आया, अचानक विधानमंडल दल में हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र जी ने प्रस्ताव रख दिया। पर्यवेक्षक के रूप में आए रमन सिंह जी ने इसकी घोषणा कर दी। मेरे बारे में तो कोई संभावना थी ही नहीं। संभावित लोगों की सूची में मेरा नाम भी नहीं था। न अखबार में, न चैनल में। अगर कहीं था तो केंद्रीय नेतृत्व के विश्वास में रहा होगा, जो उन्होंने मुझ पर विश्वास कर यह जिम्मेदारी दी।

● **ऐसे सीमित समय में जब चुनाव को एक साल भी नहीं बचा, बतौर मुख्यमंत्री आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी?**
चार साल में भाजपा सरकार ने प्रदेश में एक से बढ़कर एक काम किए, और केंद्र ने योजनाएं यहां के लिए शुरू की, मसलन चारधाम आलवेदर रोड, भारतमाला परियोजना, पहाड़ के लिए रेल का काम हो फिर एक रुपए में पानी

का कनेक्शन हर घर तक देने की योजना हो, इस तरह के बहुत सारे काम हुए। इनके साथ-साथ पर्यटन, तीर्थटन और स्वास्थ्य के लिए हुए काम को लोकोपयोगी बनाने की ओर मेरा फोकस रहेगा।

● **मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री के फैसलों को आपने बदलना शुरू किया है, क्या आपको भी लगता है कि पूर्व में फैसले जनहित की बजाए सनक में लिए गए?**

जब मैंने 10 मार्च को 4 बजे मुख्यमंत्री की शपथ ली तो उसके बाद मैंने अधिकारियों की बैठक ली। सारे सचिवों के सामने दो विषय रखे, पहला मेरे सामने यह था कि कोविड के चलते लॉकडाउन के समय में बहुत सारे लोगों ने सेवा की, इनमें पुलिसवाले, स्वास्थ्यकर्मी सफाईकर्मी और विभिन्न सरकारी लोग थे। दूसरी तरफ समाज सेवा में लगे लोग थे जो कहीं खाना दे रहे थे, किसी को रजाई-गद्दे दे

रहे थे, तो उन लोगों पर भी तब मुकदमे लग गए, ऐसे साढ़े चार हजार से भी अधिक केस राज्य में दर्ज थे। मैंने अधिकारियों से कहा कि इन्होंने कोई डाका तो डाला नहीं, सेवा ही की इसलिए मुकदमे वापस लिए जाएं।

दूसरा विषय कुंभ का था। अगले दिन ही पहला शाही स्नान था। कुंभ केवल राज्य का तो है नहीं, देश-दुनिया की नजरें इस पर होती हैं। वर्षों से लोग इसके लिए प्लान बनाते हैं। कुंभ में हमें अपने परिवार के लोगों को स्नान कराने ले जाना है, यह भावना का भी मामला है, उपासना का भी। इसलिए इसमें व्यवधान नहीं आने देना है। ये निर्देश मैंने अधिकारियों, पुलिस-प्रशासन को दिए। मैंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की जो एसओपी है उसका पालन भी करवाना जरूरी है, इसलिए लोग मास्क पहनें, हाथ धोएं या सैनिटाइज करें।

मैं खुद भी अखाड़ों के शाही स्नान में पहुंचा। मैंने साधुओं के बीच जाकर उनको आश्वस्त किया कि दिव्य और भव्य कुंभ

होगा. उन पर फूल बरसवाकर संदेश दिया कि सबके लिए कुंभ खुला है, और 32 लाख से अधिक लोग स्नान को पहुंचे.

● पूर्व मुख्यमंत्री के फैसलों को पलटने से कहीं गुटबाजी तो नहीं बढ़ेगी?

मैंने जो भी निर्णय लिए वे किसी पुराने निर्णय को पलट करके नहीं लिए, मैंने तो नए निर्णय लोगों के पक्ष में लिए, शपथ के बाद हुई पहली कैबिनेट में मैंने विकास प्राधिकरणों को ग्रामीण क्षेत्रों से हटाने के लिए एक कमेटी बनाकर इसको वापस लिया. चारधाम यात्रा के मद्देनजर, वनों में लगने वाले आग को काबू करने के लिए वन प्रहरी रखने का मैंने निर्णय लिया, तो मैंने किसी को पलटा कहा? नए निर्णय तो ले ही सकते हैं.

● लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री ने तो कुंभ में बेरोकटोक आवाजाही के आपके फैसले को जोखिम भरा कहा है?

देखिए, किसी भी काम में जोखिम होता है. मेरा कहना है कि हमें कोविड के गाइडलाइन का पालन कर लोगों को आने देना चाहिए.

● चारधाम देवस्थानम बोर्ड पर भी आपका रवैया पूर्व सरकार से भिन्न है?

मैंने इस पर विचार करने की बात कही है, सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाकर विचार करेंगे. वहां का पंडा समाज, वहां के तीर्थपुरोहित या पूजा-पाठी वाले लोग हैं, उनको साथ लेकर बैठक करूंगा. उनके हक बने रहेंगे, यह बात उनको बताई. हम उनका विरोध करने के लिए नहीं हैं, जनता के लिए हम आए हैं, जनता चाहती क्या है वह हमें करना है. जनता जनार्दन है जनता जो कहती है उसको मानेंगे.

● पार्टी में जिस तरह की खेमेबाजी पिछले दिनों उभरी है उससे निजात पाने का क्या उपाय देखते हैं?

पार्टी में कोई गुट या खेमा नहीं है. मुझे मुख्यमंत्री के रूप में चुनने का प्रस्ताव तो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने ही रखा. अगर कोई गुट होता तो वे क्यों रखते. उनके प्रस्ताव को सारे संसद सदस्यों, विधायकों ने एकमत से समर्थन दिया. ऐसे में कहां कोई गुट या खेमा दिखा.

● प्रदेश में नेतृत्व का चेहरा बदलने के बाद से अधिकारियों, अफसरों और पार्टी नेताओं में यह बेचैनी दिख रही है कि क्या उन्हें उनकी मौजूदा पदों से हटाया जाएगा या बरकरार रखा जाएगा. क्या

रास्ता है इस बैचैनी से उबरने का?

इसको तो पार्टी संगठन और सरकार विचार करने के बाद तय करेगी. हमारे यहां तो निर्णय सामूहिक रूप में लिए जाते हैं. इसको लेकर जब बैठक होगी तभी कुछ तय होगा.

● गांव, गंगा, गाय को तवज्जो देने वाली भाजपा सरकार में, हरिद्वार में गंगा के संरक्षण को लेकर मातृ सदन के एक साधु अनशन पर हैं. कुछ ने बलिदान भी दिया है. आपके राज में क्या यह उम्मीद की जाए कि गंगा संरक्षण की मांग के आंदोलन का आप समाधान निकालने का प्रयास करेंगे?

मैंने अनशनरत साधु के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उनको अस्पताल भिजवाया है. मैंने प्रशासन को पता लगाने को कहा है कि लगातार वे क्यों बैठते हैं अनशन पर. हम तो गंगा के स्वच्छ और निर्मलता के हामी रहे हैं.

● जब आप मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो अब किस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे?

चुनाव लड़ना तो है ही, इस पर जब समय आएगा विचार करेंगे. अभी यह नहीं तय किया कि कहां से चुनाव लड़ें, आग्रह कई जगह से

“पार्टी में कोई गुट या खेमा नहीं है. मुझे मुख्यमंत्री के रूप में चुनने का प्रस्ताव तो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने ही रखा. अगर कोई गुट होता तो वे क्यों ऐसा करते. उनके प्रस्ताव को से संसद सदस्यों, विधायकों ने एकमत से समर्थन दिया”



लोग करते हैं लेकिन जब इस बारे में बैठेंगे तभी यह तय होगा.

● लगातार यह कहा जा रहा कि राज्य में अफसरशाही बेलगाम हो गई है, जनप्रतिनिधियों तक की कोई परवाह नहीं करता. इस स्थिति से कैसे प्रदेश को बाहर निकालेंगे?

अगर मैं सच कहूं तो चार साल की हमारी पार्टी की सरकार में काम कम नहीं हुए हैं, बहुत काम हुए. इससे भी आगे बढ़ना है तो सबको साथ लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा. मैंने कहा है कि अधिकारियों का जनप्रतिनिधियों के साथ लगातार संवाद रहना चाहिए. जनता से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाए, जिनसे लोगों को सीधा लाभ मिले. मैं सभी जिलों के अधिकारियों से संपर्क में हूं. मैंने काम में तेजी लाने को कहा है ताकि जनता को राहत मिले.

● आपने अपने मंत्रिमंडल में पुरानी टीम को ही रिपीट कर चार जिन नए लोगों को मौका दिया है उनमें से एक विवादित शख्सियत हैं, जिन पर राज्य पुलिस के चोड़े की टांग तोड़ने का आरोप था. क्या यह निर्णय सही था?

उस समय उनके खिलाफ साजिश न यह मामला बनाया गया था. अगर इसमें सच्चाई होती तो कार्रवाई तो होती. यह राजनैतिक मुद्दा बनाने के लिए उन पर आरोप लगाकर उनके खिलाफ साजिश की गई. वे निर्दोष थे.

● राज्य में पलायन और बेरोजगारी बढ़ा मुद्दा है, इसके समाधान का कोई तरीका है आपके पास?

पलायन के मामले पर स्वरोजगार की ओर बढ़ना पड़ेगा. कृषि पर ध्यान देकर छोटे-छोटे उद्योग लगाने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने की जरूरत है. केंद्र की विभिन्न योजनाएं हैं जिनमें 80 से 90 फीसद तक की वित्तीय मदद मिलती है. ब्याज रहित ऋण राज्य सरकार भी युवा उद्यमियों को दे रही है. ■



सबसे भरोसेमंद स्रोतों से, सबसे सटीक जानकारी

सब्सक्राइब करें और पाएं 25% तक की छूट

देशव्यापी छाहरी सर्वेक्षण से जाहिर है कि नरेंद्र मोदी लोकप्रियता के शिखर पर बरकरार हैं और सच परिवार के एजेंडे को मिली जबरदस्त वकालत

हां! मैं इंडिया टुडे को सब्सक्राइब करना चाहता/चाहती हूँ

अपनी पसंद के सब्सक्रिप्शन को टिक करें और फॉर्म को इस पते पर भेज दें- वी केआर, लिविंग मीडिया इंडिया लि. सी-9, सेक्टर-10, नोएडा 201302 (भारत)

टिक करें	अवधि	कुल अंक	कवर प्राइस (₹)	ऑफर प्राइस (₹)	डिस्काउंट
☐	3 वर्ष	156	~~6240~~	4680	25%
☐	2 वर्ष	104	~~4160~~	3330	20%
☐	1 वर्ष	52	~~2080~~	1770	15%

कृपया फॉर्म को ब्लॉक लेटर में भरें

मैं चेक/डीडी जमा कर रहा/रही हूँ जिसकी संख्या.....है और इसे दिनांक.....को लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड के पक्ष में (बैंक का नाम).....रुपये की धनराशि (दिल्ली से बाहर के चेक के लिए ₹ 50 रुपये अतिरिक्त जोड़ें, समान मूल्य के चेक मान्य नहीं होंगे) के लिए बनवाया गया है.

नाम..... पता.....
..... शहर..... राज्य..... पिन.....
मोबाइल..... ईमेल.....



सब्सक्राइब करने के लिए यहां स्कैन करें.

ऑफर के विषय में विशेष जानकारी के लिए निम्न माध्यमों से संपर्क भी कर सकते हैं

हमारे टॉल फ्री नंबर पर कॉल करें
18001800100 (0120) 2479900

ईमेल भेजें
wecare@intoday.com

लॉग ऑन करें
www.indiatoday.in/indiatoday-hindi

ओडिशा

ये आग कब बुझेगी?

महेश शर्मा

विजय अग्रवाल



दावानल

सिमलीपाल नेशनल पार्क में लगी आग

ओडिशा का सिमलीपाल नेशनल पार्क धू-धूकर जल रहा है। जंगल के कोर एरिया की ओर आग का बढ़ना बेहद चिंताजनक बताया जा रहा है। इसकी वजह से दुर्लभ वनस्पतियों और सरीसृप के नष्ट होने की आशंका है। यहां की कुल 21 रेंजों में से अब तक यह आग आठ रेंज को अपनी चपेट में ले चुकी है। इसे बुझाने के सारे उपाय नाकाफी साबित हुए, हालांकि युद्धस्तर पर प्रयास जारी हैं। हाल ही में हुई हल्की-फुल्की बारिश से आग थोड़ी शांत हुई पर यह फिर से विकराल रूप धारण करने लगी है। दरअसल, बेपरवाह प्रशासन और शासन ने स्थानीय लोगों की शिकायत पर ध्यान ही नहीं दिया। वे मानकर बैठे थे कि इन दिनों मौसम के कारणों से आग लगना-बुझना आम बात है।

स्थानीय लोगों के अनुसार, पहली बार 22 फरवरी को यहां आग देखी गई थी। तब से 28 फरवरी के बीच प्रशासन और वन विभाग को सूचित किया गया, पर कोई जुंबिश तक नहीं हुई। मयूरभंज शाही घराने की राजकुमारी अक्षिता भंजदेव के ट्वीट के बाद प्रशासन की आंखें खुलीं। उसके बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेन्द्र

प्रधान ने ट्वीट करके केंद्रीय वन एवं पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावडेकर और राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से हस्तक्षेप करने की अपील की। राजकुमारी अक्षिता के ट्वीट बाद 1 मार्च से सरकारी महकमा सक्रिय हुआ। तब तक 214 अलग-अलग स्थानों पर आग फैल चुकी थी। अब काफी कुछ नियंत्रण में होने का सरकारी दावा किया गया है। फिर भी वन विभाग की मानें तो सौ से ऊपर स्थानों अभी भी आग लगी है और दायरा भी बढ़ रहा है। हाल ही में नासा की ओर से जंगल में आग की तस्वीरें जारी करने के बाद इसे गंभीरता से लिया गया। नवीन पटनायक ने सिमलीपाल की

**2009 में यूनेस्को ने
सिमलीपाल को विश्व
नेटवर्क ऑफ बायोस्फेयर
रिजर्व्स की सूची में
शामिल किया था**

आग पर समीक्षा बैठक 3 मार्च को की और बयान जारी किया कि आग पूरी तरह काबू में है। लेकिन उसके बाद भी आग का फैलता दायरा साफ संकेत देता है कि उन्हें वन विभाग ने सही जानकारी नहीं दी थी।

जैव विविधता से संपन्न यह नेशनल पार्क बहुत महत्वपूर्ण है। यहां बंगाल टाइगर, एशियन एलीफैंट, चौसिंगा आदि बड़ी संख्या में हैं। 2009 में यूनेस्को ने सिमलीपाल को विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फेयर रिजर्व्स की सूची में शामिल किया था। 22 जून, 1994 को भारत सरकार ने इसे बायोस्फेयर रिजर्व घोषित किया था। इसे एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जैव मंडल (5,569 वर्ग किमी में फैला) कहा जाता है और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व (2,750 वर्ग किमी) भी इसी में आता है। यहां के टाइगरों और हाथियों को अब तक किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। पर वनकर्मियों के अनुसार, दुर्लभ पेड़-पौधों के साथ ही सरीसृपों और अन्य वन्यजीवों के जलकर मर सकते हैं।

यहां आग बुझाने में एक हजार से ज्यादा वन एवं अग्निशमन कर्मी लगाए गए हैं। हालात बेकाबू होते देख बीते 11 मार्च को दिल्ली से भेजे गए केंद्रीय दल ने इसका जायजा लिया। इसमें आईजी (फॉरेस्ट), एनटीसीए (राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकारी) और अन्य अग्निशमन विशेषज्ञ हैं। ये अपनी रिपोर्ट केंद्र को देंगे। घटना की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने वन विभाग और फायर विभाग कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी। मुख्यमंत्री ने टास्कफोर्स गठित कर दी है। राज्य के मुख्य वन संरक्षक बातचीत से कतराते हुए कहते हैं कि पहले आग बुझा लें फिर नुकसान के आकलन और अन्य बातों पर चर्चा होगी। वहीं पूर्व मुख्य वन संरक्षक संदीप त्रिपाठी की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स के स्थानीय सदस्य विजय कुमार अग्रवाल बताते हैं कि इन महीनों में सिमलीपाल में आग कोई नई बात नहीं है।

लेकिन, यहां आग का इतना विकराल रूप इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। टास्कफोर्स के प्रमुख संदीप त्रिपाठी का दावा है कि सिमलीपाल फायर अब नियंत्रण में है। वे कहते हैं कि थोड़ी बारिश होने से आग ज्यादा नहीं फैल पाई। मौसम विभाग ने भी ओडिशा में बारिश की भविष्यवाणी की है। बारिश होती है तो आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा सकता है। वहीं, सिमलीपाल संरक्षण के लिए सक्रिय पर्यावरण विशेषज्ञ भानुमित्र आचार्य कहते हैं कि शुरू में ही जरूरी कदम उठाए गए होते तो यह नौबत नहीं आती। ■



अर्थात्

सबसे बड़ा उलट-फेर

अंशुमान तिवारी

भात में यह फर्क अब खासा महत्वपूर्ण होने वाला है कि आप किस राज्य में रहते हैं और रोजगार का मौका कौन से राज्य में मिलता है। यह बात हरियाणा या झारखंड में राज्य के निवासियों को रोजगार (निर्धारित वेतन सीमा से नीचे) देने की शर्त तक सीमित नहीं है बल्कि रोजगारों और लोगों के जीवन स्तर में बेहतरी भविष्य में इस तथ्य से तय होगा कि विभिन्न राज्य मंदी के बाद आने वाले सबसे बड़े वित्तीय उलट-फेर को कैसे संभाल पाते हैं।

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मंदी की बहस से निकलकर अब राज्यों की तरफ देखने की जरूरत है, लॉकडाउन ने जिनकी अर्थव्यवस्थाओं की बुरी गत बना दी है। राज्यों के अपने राजस्व नुक्सान तो अलग हैं, ऊपर से उन्हें जीएसटी के हिस्से में इस वित्त वर्ष में केंद्र से करीब तीन लाख करोड़ रुपए कम मिले। अगले साल भी इतनी ही कमी रहनी है।

जोर का झटका

राज्यों की कमाई या राजस्व को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। केंद्र ने राज्य सरकारों को जीएसटी में नुक्सान की भरपाई की जो गारंटी दी है, वह 2023 में खत्म हो जाएगी। 15वें वित्त आयोग ने अपनी ताजा रिपोर्ट में इसे बढ़ाने की कोई सिफारिश नहीं की है। इस गारंटी के खत्म होने से राज्यों के राजस्व का पूरा संतुलन बदल जाएगा और नुक्सान की भरपाई का इंतजाम उन्हें खुद करना होगा।

यही नहीं, वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी का फॉर्मूला भी बदल दिया है। नई व्यवस्था में जनसंख्या नियंत्रण, स्वास्थ्य व शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के पैमाने भी जोड़े गए हैं। इंडिया रेटिंग्स की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय करों में आठ राज्यों (आंध्र, असम, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश) का हिस्सा 24 से लेकर 118 (कर्नाटक) फीसद तक घट जाएगा। महाराष्ट्र, गुजरात, अरुणाचल के हिस्से में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हो रही है।

केंद्र के टैक्स में सेस और सरचार्ज का हिस्सा बढ़ता जा रहा है, जिनमें राज्यों को हिस्सा नहीं मिलता। केंद्रीय टैक्स राजस्व में इनका हिस्सा 2012 में 10.4 फीसद से बढ़कर 2021 में 19.9 फीसद हो गया है।

वित्त आयोग ने केंद्र से राज्यों को जाने वाले अनुदानों में बढ़ोतरी की सिफारिश की है लेकिन शिक्षा, बिजली और खेती के लिए केंद्रीय अनुदान बेहतर प्रदर्शन की शर्त पर मिलेंगे। बेहतर काम के लिए राज्यों को ज्यादा खर्च या निवेश करना होगा जबकि खजाने और ज्यादा खाली हो जाएंगे।

कर्ज का अंबार

कोविड की मंदी ने केवल केंद्र के बजट को ही ध्वस्त कर सरकार को बैंकों व सरकारी संपत्तियों की सेल लगाने पर बाध्य नहीं किया है, राज्यों की हालत और ज्यादा खराब है। मौजूदा वित्त वर्ष में (7 अप्रैल से 16 मार्च तक) 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर बाजार से रिकॉर्ड 8.24 लाख करोड़ रुपए का कर्ज उठा चुके हैं। यह कर्ज पिछले वित्त वर्ष से 31 फीसद ज्यादा है।

मध्य प्रदेश, झारखंड और सिक्किम पिछले साल की तुलना में दोगुने से ज्यादा कर्ज उठा चुके हैं। कर्ज पर ब्याज की दर ज्यादातर राज्यों के लिए 7 फीसद से ऊपर हैं।

जीएसटी में नुक्सान की भरपाई पर केंद्र के इनकार के बाद अगले साल राज्यों को 2.2 लाख करोड़ रु. अतिरिक्त कर्ज उठाने होंगे। अगले साल राज्यों के कुल कर्ज दस लाख करोड़ रु. से ऊपर निकल सकते हैं। अगले दो साल में संघीय अर्थव्यवस्था में दो बड़े बदलाव होने हैं:

■ जीएसटी की क्षतिपूर्ति खत्म होने और केंद्रीय करों के हिस्से में कटौती कई बड़े राज्यों में जिंदगी और कारोबारी लागत बढ़ाएगी। सरकारों को बिजली, रोड ट्रांसपोर्ट, भूमि पंजीकरण की दरें बढ़ानी होंगी, जरूरी खर्चे काटने होंगे और निजीकरण तेज करना होगा।

■ राज्यों पर कर्ज की देनदारी का नया चक्र शुरू होगा जिसके लिए संसाधन नाकाफी हैं।

नई दुनिया में (अपवादों को छोड़कर) सफलता केवल प्रतिभा या क्षमता से तय नहीं होती है बल्कि इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि वह अमेरिका में पैदा हुआ है या तीसरी दुनिया के किसी देश में। यही वह ओवेरियन लॉटरी (जन्म स्थान का सौभाग्य) है जिसे मशहूर निवेशक वारेन बफे की जीवनी *द स्नोबॉल* में दिलचस्प ढंग से समझाया गया है।

यह सिद्धांत भारत के राज्यों पर भी लागू होने वाला है क्योंकि तेज विकास के पिछले वर्षों में क्षेत्रीय असमानता बढ़ती चली गई है।

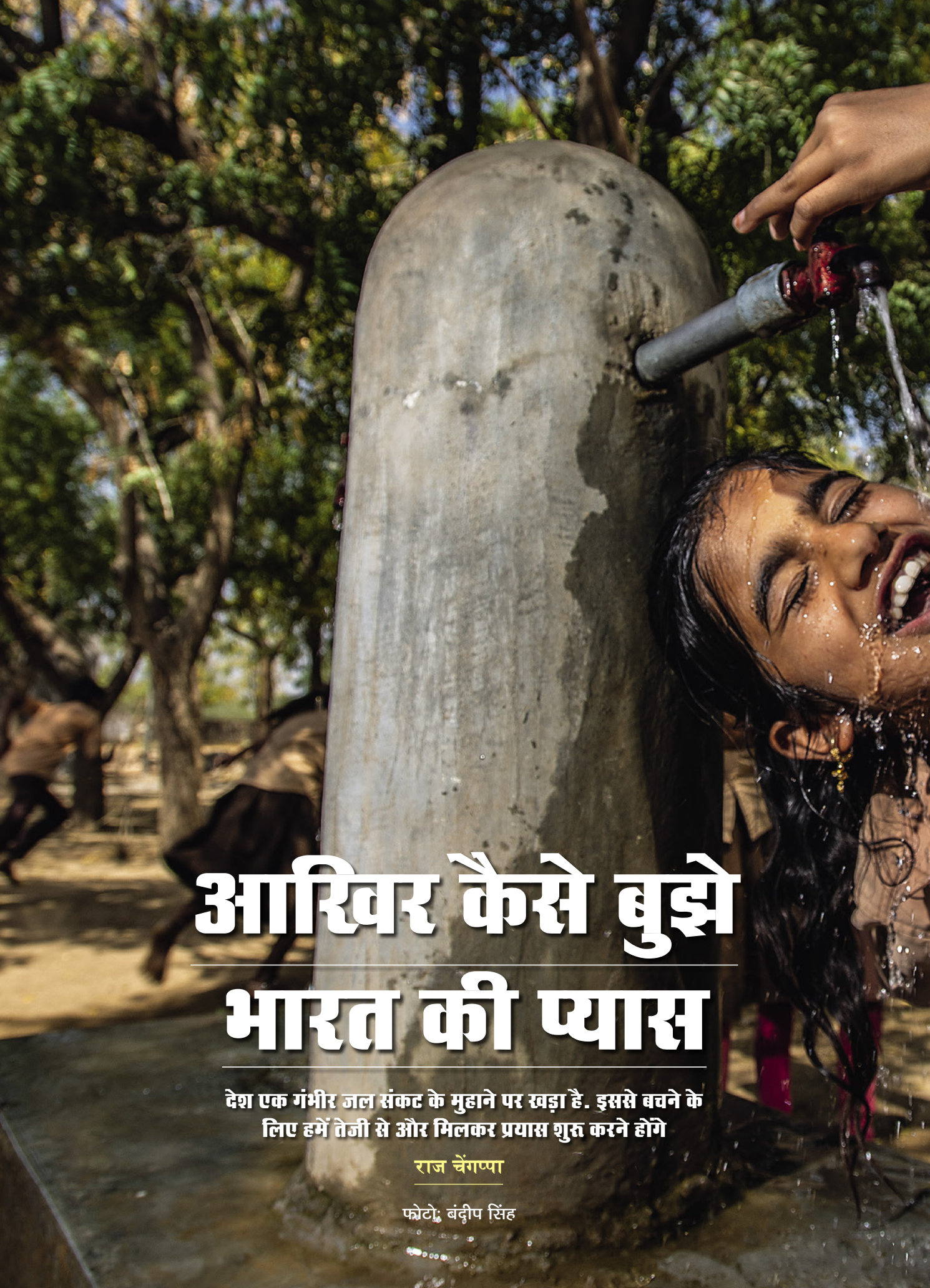
डबल इंजन की सरकारों के दावों को चुनावी नमक के साथ चाहिए क्योंकि कोविड 2016-20 के बीच केवल हरियाणा, कर्नाटक, गुजरात और तेलंगाना की विकास दर राष्ट्रीय औसत से ऊपर रही थी (इंडिया रेटिंग्स रिपोर्ट 2021) बाकी सब के जस के तस रहे।

चिरंतन चुनावी चौकसी से निकल कर केंद्र सरकार को मंदी से उबरने के लिए राज्यों के साथ साझा रणनीति बनानी होगी क्योंकि मंदी के बाद किस राज्य में रहने में फायदा होगा यह डबल इंजन की सरकार से नहीं बल्कि टैक्स, कारोबारी, सुविधाओं जीवन की लागत और स्थानीय अर्थव्यवस्था में मांग पर निर्भर होने वाला है।

@anshuman1tiwari



अगले दो साल में राज्यों की अर्थव्यवस्था में होने वाला है बड़ा परिवर्तन

A young girl with long dark hair is drinking from a public water tap. She is smiling and her face is wet with water. The tap is mounted on a large, weathered metal cylinder. In the background, there are trees and a few people walking, suggesting a rural or semi-rural setting. The overall tone is one of relief and hope for access to clean water.

आखिर कैसे बुझे भारत की प्यास

देश एक गंभीर जल संकट के मुहाने पर खड़ा है. इससे बचने के लिए हमें तेजी से और मिलकर प्रयास शुरू करने होंगे

राज चेंगप्पा

फोटो: बंदीप सिंह



● ● ●

ऐसे करते हैं कंठ तर

राजस्थान के जालौर जिले में लचोरी गांव के उत्कृष्ट राजकीय प्राथमिक विद्यालय में पानी पीती 11 वर्षीया दरिया

60

करोड़

लोग गंभीर से अति गंभीर जल संकट से गुजर रहे हैं

75%

परिवारों के पास अपने घर में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है. 84 फीसद ग्रामीण परिवारों तक नलके का पानी अभी भी नहीं पहुंच पाया है

70%

पानी दूषित है, हमारे यहां का. जल गुणवत्ता सूचकांक पर 122 देशों की सूची में भारत 120वें पायदान पर खड़ा है

6%

सब कुछ अगर इसी ढर्रे पर चलता रहा तो 2050 तक हम करीब 6 फीसद जीडीपी पानी के संकट की वजह से गंवा देंगे

स्रोत: नीति आयोग वाटर रिपोर्ट, 2018

ढा

ई हजार वर्ष से भी पहले जब सिंधु घाटी सभ्यता अपने विकास के चरम पर थी, रहस्यमय तरीके से इसने अपनी चमक खो दी और अचानक लुप्त हो गई। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि ऐसा भीषण जल संकट के कारण हुआ था, जो नदियों के मार्ग बदल लेने या फिर कठोर जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ होगा और इसकी वजह से लोग नगर छोड़ने को मजबूर हुए होंगे। सभ्यता पूरी तरह लुप्त हो गई। बचे तो बस अवशेष जिनकी खोज 20वीं शताब्दी में हुई। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। भारत के लिए वह मनहूस स्थिति फिर से आने वाली है। नीति आयोग की 2018 की रिपोर्ट में कहा गया है कि 60 करोड़ लोग या भारत की लगभग आधी आबादी पानी के अत्यधिक तनाव का सामना कर रही है।

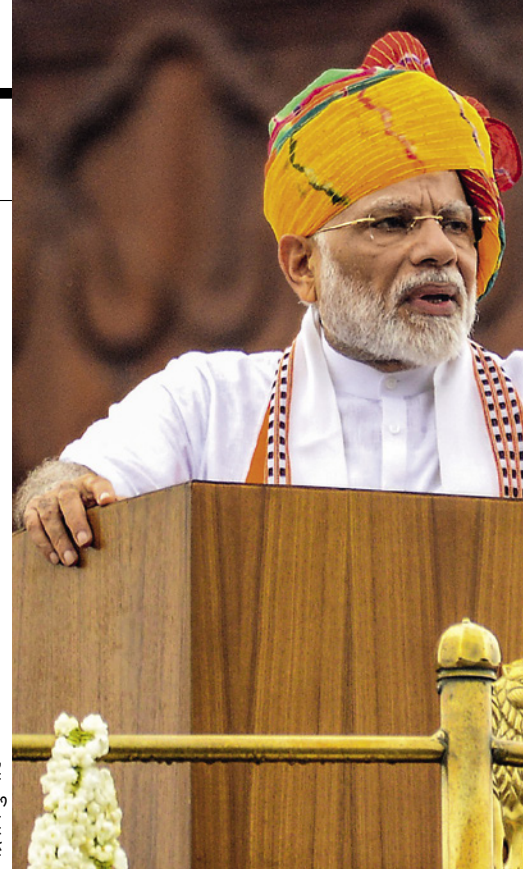
भारत के तीन-चौथाई ग्रामीण घरों में नल का पानी उपलब्ध नहीं है और वे ऐसे स्रोतों पर निर्भर हैं जो एक गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करते हैं। भारत भूजल का दुनिया का सबसे बड़ा दोहनकर्ता बन गया है, और अपने कुल उपलब्ध भूजल का 25 प्रतिशत निचोड़ चुका है। हमारे 70 प्रतिशत जलस्रोत दूषित हैं और प्रदूषण के कारण हमारी प्रमुख नदियां मर रही हैं। निष्कर्ष: 'भारत अपने इतिहास के सबसे खराब जल संकट का सामना कर रहा है.'

अस्तित्व बचाने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा। पर हम करें क्या? सबसे पहले, हमें अपनी उपलब्धता और खपत के पैटर्न दोनों को समझना होगा। भारत में दुनिया की कुल आबादी का 18 प्रतिशत निवास करती है लेकिन वैश्विक जल संसाधनों का केवल 4 प्रतिशत उपलब्ध है। जल संतुलन गंभीर रूप से प्रतिकूल है। आम धारणा से उलट, भारत की जलापूर्ति को न तो घरेलू उपयोग करते हैं और न ही उद्योग। यह खेती है जहां हमारे पानी के 85 प्रतिशत से अधिक की खपत होती है। केवल 40 प्रतिशत पक्के सिंचाई प्रबंध के साथ हमारे

किसान अपनी जरूरतों के लिए या तो बारिश या भूजल पर बहुत अधिक निर्भर हैं। भारत में मॉनसून की अवधि चार महीनों की है पर भारी बारिश यहां बमुश्किल 30 दिन होती है। वर्षा जल संरक्षण के प्रयास तो नितांत नाकाफी हैं।

फिर भी इन सारी दिक्कतों के बीच इस संकट से बाहर निकलने के लिए अभिनव समाधानों की तलाश ने गति पकड़ ली है, ऐसा *इंडिया टुडे* की टीम ने इस विशेष अंक के लिए कथाओं के संकलन के दौरान पाया। मसलन,

बड़े बजट वाली बड़ी परियोजनाओं से इतर **बुनियादी भूजल स्तर को चार्ज करने वाले मामूली-सी लागत वाले एक अरब उपक्रम** हमें जल संकट से निजात दिला सकते हैं



चंद्रदीप कुमार

पीने के पानी को ही ले लें। हर घर में शौचालय उपलब्ध कराने और अपने पहले कार्यकाल में भारत को खुले में शौच मुक्त बनाने के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे कार्यकाल के शुरू में जल जीवन मिशन की घोषणा की। अगस्त 2019 में शुरू इस महत्वाकांक्षी योजना का लक्ष्य 2024 तक 19.1 करोड़ ग्रामीण घरों में नल के जरिए पेयजल उपलब्ध कराना है। फिलहाल छह घरों में से एक में ही यह उपलब्ध है।

कोविड महामारी के कारण हुए व्यवधान को देखते हुए जल शक्ति मंत्रालय का लक्ष्य पूरा करने की क्षमता पर संदेह था। बाधाओं के बावजूद, इस दौरान 3 करोड़ से ज्यादा नए घरों में नल का पानी मुहैया कराया गया है जो आजादी के बाद से अब तक जितने घरों को उपलब्ध कराया गया, उसके बराबर है। मोदी सरकार ने इस लक्ष्य को 3.6 लाख करोड़ रु. की भारी-भरकम धनराशि देकर इसे एक अभियान की तरह चलाते हुए और प्रगति की निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी के भरपूर इस्तेमाल से संभव किया है। उधर, राज्य सरकारें पानी समितियों के रूप में जल आपूर्ति व्यवस्था के संचालन और रखरखाव के लिए सामुदायिक समितियों को प्रोत्साहित कर रही हैं ताकि हर घर में पानी की आपूर्ति पक्की हो सके। केंद्र और राज्य इसे एक बार करने के बाद बेफिक्र हो जाने की बजाए, पानी की सतत आपूर्ति और गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इन प्रयासों का सबसे अहम नतीजा यह है कि जिन महिलाओं के कंधों पर घरों के



30

दिन का ही हिस्सा होता है बरसात
का जब भारी बारिश होती है हालांकि
मौसम चार महीने का होता है



एक मिशन यह भी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 में
स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित
करते हुए, इसी भाषण में उन्होंने जल
जीवन मिशन का ऐलान किया था

जल जीवन मिशन दरअसल महिलाओं को पानी देने के श्रमसाध्य उपक्रम से मुक्त करने का मिशन है.

यह मुक्ति देने वाला एक
मिशन साबित होगा

की खेती को रोकने और किसानों को अन्य
फसलों का रख करने के लिए प्रोत्साहित करने
के लिए नकद सब्सिडी की योजना शुरू कर
एक राह दिखाई है. जाहिर है, राज्यों को आदेश
जारी करने की बजाए, उत्प्रेरक के रूप में काम
करना होगा और किसानों को उन फसलों का
रख करने को राजी करना होगा जो खाद्य
जरूरतें पूरा करते हुए बेहतर दाम दिलाते हों.

एक और संकट से हमें तत्काल निबटने
की जरूरत है: महानगरों में पानी की बढ़ती
किल्लत. नीति आयोग का अनुमान है कि
दिल्ली सहित 21 प्रमुख शहरों का भूजल
2030 तक समाप्त हो जाएगा. इसका सरल
समाधान है जलस्रोतों को पुनर्जीवित करना
जैसा कि बेंगलूरु ने किया जो कभी टैंकों का
शहर कहा जाता था. हमारी अपशिष्ट निपटान
रणनीति और अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण पर
पुनर्विचार करने का भी यही समय है. अभी
100 ग्राम मल प्रवाहित करने के लिए हम
छह लीटर पानी का उपयोग करते हैं. क्या
हम प्रौद्योगिकी विकसित कर सकते हैं जिसमें
कम पानी की जरूरत हो जैसा कि विमानों
के शौचालयों में होता है? हमारे शहरों के
ठोस अपशिष्ट को शहरों के बाहरी इलाकों
के एक ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाने के लिए
सीवेज पाइप बिछाने की जो तकनीक इस्तेमाल
हो रही है वह सदियों पुरानी है. क्या अधिक
स्थानीय उपचार संयंत्र खोजा जा सकता है
और उपचारित पानी को औद्योगिक उपयोग या
आसपास के क्षेत्रों में पार्कों में फिर से उपयोग
लायक बनाया जा सकता है? दिल्ली अपने
परनालों के गंदे पानी के शोधन के एक प्रयोग
पर काम कर रही है ताकि इसे औद्योगिक
इस्तेमाल के लायक बनाया जा सके.

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जीवन
जीने में आसानी के अलावा, पानी की हमारी
जरूरतों को पूरा करने के लिए और बड़े बांधों
के निर्माण की बजाए मौजूदा जल निकायों को
पुनर्जीवित करना आर्थिक रूप से भी फायदेमंद
है. आगे के पन्नों पर हमने पानी के संरक्षण
की दिशा में देशभर में हो रही अनूठी पहलों
पर रोशनी डाली है जिन्हें जरूरत के मुताबिक
बदलावों के साथ दोहराया जा सकता है.
अनुमान है कि सब आज जैसा ही चलता रहा
तो 2030 तक भारत के पास अपनी जरूरत का
आधा पानी ही उपलब्ध होगा. तबाही का वह
दिन एक सदी नहीं बल्कि सिर्फ एक दशक दूर
है. हमें जल्द ही और बहुत कुछ करना होगा. ■

लिए पानी ढोकर लाने की जिम्मेदारी होती थी
और इस काम में रोजाना उनका काफी कीमती
समय बर्बाद होता था, वे अब इस चिंता से
मुक्त हो रही हैं. यह एक बड़ी आजादी का भाव
है. सामाजिक आर्थिक विकास और पानी की
उपलब्धता के बीच एक स्पष्ट संबंध है.

विशेषज्ञ पेयजल आपूर्ति प्रदान
करने के लिए मानसिकता में
आए बदलाव की सराहना करते
हैं, लेकिन उनका मानना है कि खेती में पानी
के उपयोग में क्रांति लाना असली चुनौती होगी.
यह उत्साहवर्धक है कि सरकार और किसानों
के बीच दुर्लभ सार्वजनिक निजी साझेदारी से
इस दिशा में प्रयास शुरू हुए हैं और कम लागत
वाले नए, प्रभावी समाधान आने लगे हैं. मध्य
प्रदेश के देवास जिले में किसान पानी की भारी
कमी के चलते एक ही फसल उगा पाते थे. एक
जागरूक डिप्टी कमिशनर ने लोगों को साथ
लिया और खेतों में 10,000 ताल खुदवाए
जहां मॉनसून के पानी का भंडारण किया जा
सकता था. इसके लिए किसानों को सस्ते कर्ज
दिए गए. प्रभाव भी तुरंत दिखने लगा. अगली
बरसात के बाद, किसान ज्यादा उपज देने वाली
गेहूं की किस्मों की खेती के साथ-साथ कई
अन्य तरह की फसलें उगाकर फसल विविधता
लाने में सक्षम थे.

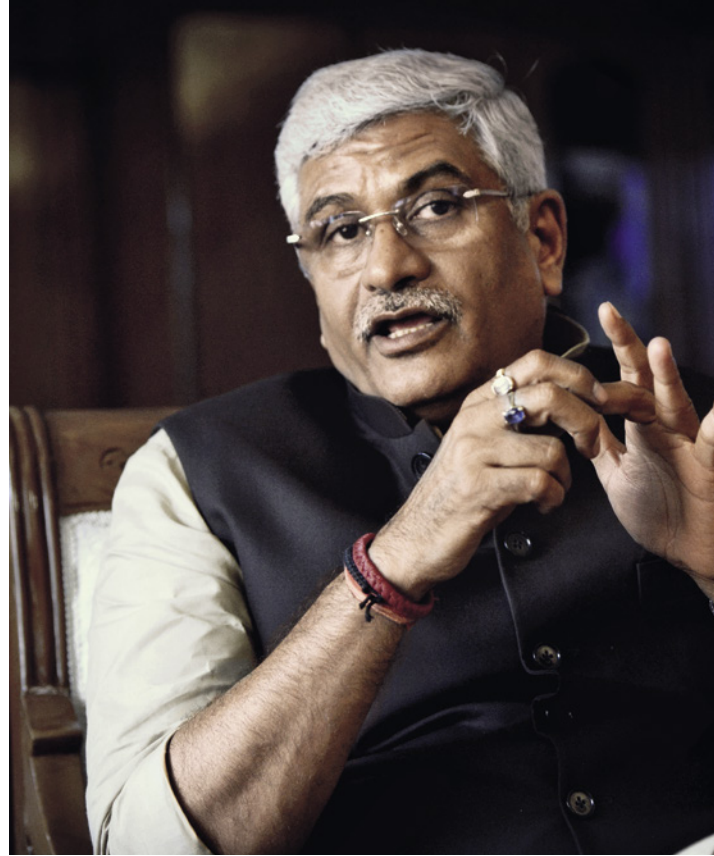
कई मिसालें हैं जिसमें किसान पानी का
संरक्षण कर किस्मत बदल रहे हैं. बड़ा संदेश यह
है कि बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से

ऊंची लागत पर पानी के हस्तांतरण की बजाए,
इसका अच्छा समाधान स्थानीय स्थितियों के
अनुकूल कम लागत वाली एक अरब भूजल
पुनर्भरण तकनीक लागू करके खोजा सकता है.

आपूर्ति पर ध्यान देना अच्छी बात है,
लेकिन जोर मांग पक्ष को दुरुस्त करने पर होना
चाहिए, जैसा कि सरकार के 'पर ड्रॉप मोर
क्रॉप' नारे में आह्वान भी किया गया है. कभी
सूखाग्रस्त राज्य रहे गुजरात ने किसानों को ड्रिप
सिंचाई तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित करके
सूखे से निबटने में बड़ी प्रगति की है. राज्य
ने स्प्रींकलर की लागत पर 60-80 प्रतिशत
की सब्सिडी देने के अलावा ड्रिप तकनीक
अपनाने वाले किसानों को उनके पहले फसली
सीजन के दौरान हर प्रकार की सहायता और
परामर्श उपलब्ध कराके इसमें सफलता पाई है.
20 प्रतिशत किसान पहले ही सूक्ष्म सिंचाई को
अपना चुके हैं जिससे पानी और श्रम लागत
में 40 प्रतिशत की बचत होती है. अहमदाबाद
स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान के अध्ययन में
यह सामने आया है.

पंजाब में धान के लिए पानी के अत्यधिक
दोहन से भूजल स्तर में भारी गिरावट देखी गई
है. वहां फसलों में विविधता लाते हुए कम पानी
वाली ऐसी दूसरी फसलें उगाने की तत्काल
आवश्यकता है जो किसानों को समान आय
दे सकें. महाराष्ट्र के गन्ना किसानों को भी
यही करने की जरूरत है क्योंकि वहां पानी
की उपयोग दक्षता निराशाजनक है. हरियाणा
ने किसानों को कम भूजल वाले क्षेत्रों में धान

“ सफलता के लिए जल अभियानों को जनांदोलनों की तरह हमें लेना होगा ”



केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने भारत के सामने खड़े गंभीर जल संकट और इस स्थिति में सुधार लाते हुए लोगों को सभी तरह के उपयोगों के लिए स्थायी और गुणवत्तापूर्ण जलापूर्ति करने की दिशा में मोदी सरकार के प्रयासों के बारे में ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर राज चेंगप्पा से बातचीत की. प्रमुख अंश:

● भारत में जल संकट कितना गंभीर है ?

हम सभी जानते हैं कि पानी की उपलब्धता की चुनौती का सामना पूरी दुनिया कर रही है, और भविष्य बहुत कठिनाई भरा लग रहा है. हमारी आबादी और इसकी वृद्धि दर के कारण भारत के लिए यह संकट और भी अधिक कठिन तथा चुनौतीपूर्ण है. हमारे पास दुनिया की आबादी का लगभग 18 प्रतिशत है, लेकिन पानी केवल 4 प्रतिशत उपलब्ध है. जलवायु परिवर्तन के प्रभाव हमारे दरवाजों पर दस्तक दे रहे हैं जिनसे बादल फटने या बहुत कम बारिश होने जैसी घटनाएं हो रही हैं. हमारे जल निकाय और जलस्रोत कुछ सबसे अधिक दूषित निकायों और स्रोतों में से हैं इसलिए हमारे लिए चुनौती और भी बड़ी है. प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता के संदर्भ में कहें तो अगर 50 साल पहले लगभग यह 5,000 घन मीटर था तो अब यह 1,500 घन मीटर रह गया है. चुनौती वाकई बहुत बड़ी है.

● वर्ष 2024 तक सभी घरों में पाइप लाइन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने का वादा पूरा करने के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं ?

जब 2014 में मोदी जी सत्ता में आए तो उन्होंने आम आदमी का जीवन आसान बनाने के लिए कई पहल की, चाहे वह बैंक खाते हों, गैस सिलेंडर हों या फिर आवास या शौचालय. जब वे दूसरी बार सत्ता में आए तो इनसे आगे बढ़ते हुए उन्होंने हर घर को पीने का पानी उपलब्ध कराने की पहल की. देश के 19 करोड़ घरों में से केवल 16 प्रतिशत या 3.02 करोड़ परिवारों को अपने घर में नल के माध्यम से पानी मिल रहा था, बाकी लोग सार्वजनिक नलों या हैंड पंपों पर निर्भर थे. ऐसे में, महिलाएं पानी के लिए अपने घरों से मीलों दूर तक जाने को बाध्य थीं. पानी की उपलब्धता के अलावा इसकी गुणवत्ता भी बहुत बड़ी

“पूरी दुनिया जल संकट की चुनौती का सामना कर रही है. भारत में यह संकट और बड़ा है क्योंकि **हमारी आबादी और इसकी बढ़ोतरी की रफ्तार अधिक है**”



चंद्रदीप कुमार

चुनौती थी. ऐसे में, प्रधानमंत्री ने 2024 तक हर घर में पाइप के माध्यम से सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और निश्चित मात्रा में पानी उपलब्ध कराने की पहल की. इसके लिए 3.6 लाख करोड़ रुपये की घोषणा की गई और हमने इस पर काम करना शुरू कर दिया है. चूंकि पानी राज्यों का विषय है इसलिए हम यह काम उनके साथ परामर्श और सहयोग से कर रहे हैं. लेकिन मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि महामारी के बावजूद 15 महीनों के भीतर हमने 3.02 करोड़ परिवारों को पीने योग्य पानी उपलब्ध कराया है, जिससे वर्तमान संख्या पहले की दोगुना हो गई है. हम मिशन मोड पर काम कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि हम 2024 का लक्ष्य पूरा कर लेंगे.

● 'हर घर नल से जल' कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए आपने क्या किया?

हमने ऐसा चार चीजों के माध्यम से किया है—राजनैतिक इच्छाशक्ति, जो प्रधानमंत्री ने दिखाई है, सरकार की ओर से हो रहा

सार्वजनिक व्यय, हमने भागीदारियों की हैं, और, हम लोगों से इस संबंध में निरंतर आग्रह कर रहे हैं.

● भारत में भूजल दोहन बहुत ज्यादा होता है. गिरते जल स्तर के अलावा, हम पानी की भारी कमी का भी सामना कर रहे हैं. सरकार इस संबंध में क्या कर रही है?

भूजल बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि इस पर हमारी निर्भरता दुनिया में सबसे ज्यादा है. देश भर में लगभग 1,580 (कुल 7,197 में से) विकास खंडों में भूजल का अत्यधिक या गंभीर रूप से दोहन हुआ है. भारत के 735 में से 257 जिलों में गहरा जल संकट है. अपने दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री ने पानी से जुड़े सभी विभागों और मंत्रालयों को एक मंत्रालय के अधीन कर दिया है. हमने प्राकृतिक जलस्रोतों (एक्विफर) को चिन्हित करने के कार्यक्रम को गति दी है और इस डेटा के आधार पर, हम एक पुनर्भरण (रिचार्ज) तंत्र पर काम करेंगे. हमारा जोर जल संसाधनों की दीर्घकालिकता पर है.

● पानी की सबसे ज्यादा खपत कृषि में होती है. ऐसे में यह सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय क्या कर रहा है कि किसान इसका उपयोग कुशलता से करें?

हम जब जल संरक्षण की बात करते हैं तो आमतौर पर उद्योगों को दोष देते हैं. लेकिन सच्चाई यह है कि पानी की कुल खपत का 89 फीसद कृषि में जाता है. हम गेहूं, चावल और गन्ने के दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में शामिल हो सकते हैं, लेकिन जब प्रति बूंद फसल की बात आती है तो अन्य विकसित देशों की तुलना में

“इस समय हम दृढ़ विश्वास के साथ ऐसा (पानी की कीमत लगाना) कर सकते हैं; भविष्य में ऐसा हमें मजबूरी में करना होगा. अंततः हमें यह करना तो पड़ेगा ही”

हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं है. इसलिए, हमें जल उपयोग दक्षता पर काम करने की आवश्यकता है. हालांकि कृषि राज्यों का विषय है फिर भी मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार सूक्ष्म सिंचाई सहित कुशल सिंचाई प्रणालियों को आगे बढ़ा रही है.

● क्या वह समय नहीं आ गया है जब हम पानी की कीमत लगाएं?

यह समय है जब हम दृढ़ विश्वास के साथ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन भविष्य में हमें ऐसा मजबूरी में करना होगा. अंततः हमें यह करना तो पड़ेगा ही.

● गंगा की सफाई की हम 1985 से बात करते आ रहे हैं. मोदी सरकार का नमामि गंगे कार्यक्रम कितना अलग है?

पहले गंगा की सफाई टुकड़े-टुकड़े में की जा रही थी और कुल मिलाकर केवल 4,000 करोड़ रुपये इस पर खर्च हुए थे. कई परियोजनाएं अधूरी थीं या ठीक से संचालित नहीं हो रही थीं क्योंकि वे राज्यों की जिम्मेदारी थीं और उन्होंने इनके लिए पर्याप्त धन नहीं दिया था. मोदी जी के तहत, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन को प्राधिकरण का दर्जा दिया गया और इसके लिए 20,000 करोड़ रुपये मंजूर किए गए. गंगा को साफ करने के लिए 350 से अधिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं. हम इसे दुनिया की शीर्ष 10 सबसे स्वच्छ नदियों में से एक बनाएंगे.

● क्या आप अन्य प्रदूषित नदियों जैसे यमुना के लिए भी ऐसी ही पहल की योजना बना रहे हैं?

गंगा की सफाई की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने पूरे गंगा बेसिन की सफाई की परिकल्पना की है. हमने पहले स्तर की सहायक नदियों जैसे यमुना और कोसी तथा अन्य सभी सहायक नदियों पर एक साथ काम शुरू किया है. देश की अन्य नदियों की सफाई के लिए यह एक मॉडल बन जाएगा.

● अंत में, विश्व जल दिवस पर भारत की ओर से आपका मुख्य संदेश क्या है?

पानी का संबंध हर किसी से है. सभी को पानी का उपयोग तर्कसंगत और दक्ष तरीके से करना होगा. अपने विभिन्न जल अभियानों में सफल होने के लिए हमें उन्हें जनांदोलनों के रूप में चलाना होगा. ■



हंसी-खुशी की धारा

राजस्थान के सिंदूर गांव में रात में
अपने घर के सुकून में नल से पानी
भरती महिलाएं



जल विशेषांक  ग्रामीण पेयजल

प्यास है कि बुझती ही नहीं

आजादी के सात दशक बाद भी देश के 19.1 करोड़ परिवारों में तकरीबन एक-तिहाई को ही नल कल से पीने का पानी नसीब, अब देश की उम्मीदें महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन पर टिकीं

राज चेंगप्पा

फोटो: बंदीप सिंह

न

ई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के मुख्यालय में अतिरिक्त सचिव तथा जल जीवन मिशन के निदेशक भरत लाल अपने कंप्यूटर पर क्लिक करके सरकार के उस विशाल कार्यक्रम की प्रगति का जायजा लेते हैं जो हरेक ग्रामीण घर में पेयजल के लिए नल कनेक्शन देने का वादा करता है। उनके क्लिक करते ही मंत्रालय की वेबसाइट पर तेजी से उभरता है कि उस एक दिन देश भर के 1,27,000 घरों में सुचारू नल कनेक्शन लगा दिया गया है। फिर वे पता करते हैं कि 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुरुआत करने के बाद अब तक कुल कितने घरों में सुचारू नल का कनेक्शन लगाया गया है। 3.84 करोड़ का आंकड़ा सामने आ जाता है। यह असाधारण प्रगति है, खासकर इस बात को देखते हुए कि इस मिशन की लॉन्चिंग से पहले महज 3.2 करोड़ घरों में सुचारू नल के कनेक्शन आजादी के बाद से लगाए गए थे।

हालांकि, जल जीवन मिशन की इस तेज रफ्तार तरक्की के बावजूद, महज 36.9 फीसद घरों में ही नल का पानी पहुंच सका है, जो देश में कुल 19.1 करोड़ घरों में से एक-तिहाई से कुछ ही ज्यादा है। यह देश और उसके नेताओं के लिए निश्चय ही शर्म की बात होनी चाहिए कि करीब 63 फीसद ग्रामीण आबादी को अब भी अपनी रोजमर्रा की जरूरत का पानी लाने के लिए अपने घरों से बाहर निकलना पड़ता है और कई बार घंटों कतार में लगना पड़ता है।

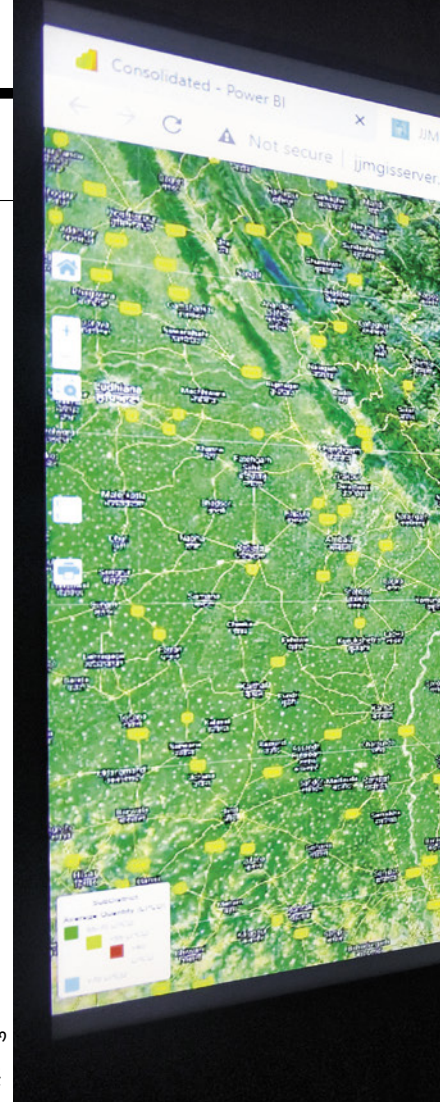
यही वजह है कि लाल और उनके साथी धुन और पक्के इरादे से इस जल जीवन मिशन में जुटे हैं और इसकी समय सारिणी पर बाज की तरह आंखें गड़ाए हैं, जो स्कूलों के अलावा सारे ग्रामीण घरों में 2024 तक सुचारू नल का कनेक्शन लगाने का वादा करता है। पेयजल मुहैया करने की अतीत में भी जबरदस्त कोशिशों की गई हैं, जिनमें 1986 में राजीव गांधी के हाथों लॉन्च राष्ट्रीय पेयजल मिशन भी शामिल है, लेकिन उनमें से कोई भी जल जीवन मिशन की बराबरी नहीं करता। 'हर घर नल से जल' कार्यक्रम के तहत 2024 का लक्ष्य पूरा करने के लिए सरकार को अगले तीन साल में हर साल 3 करोड़ नए घरों में नल लगाना है।

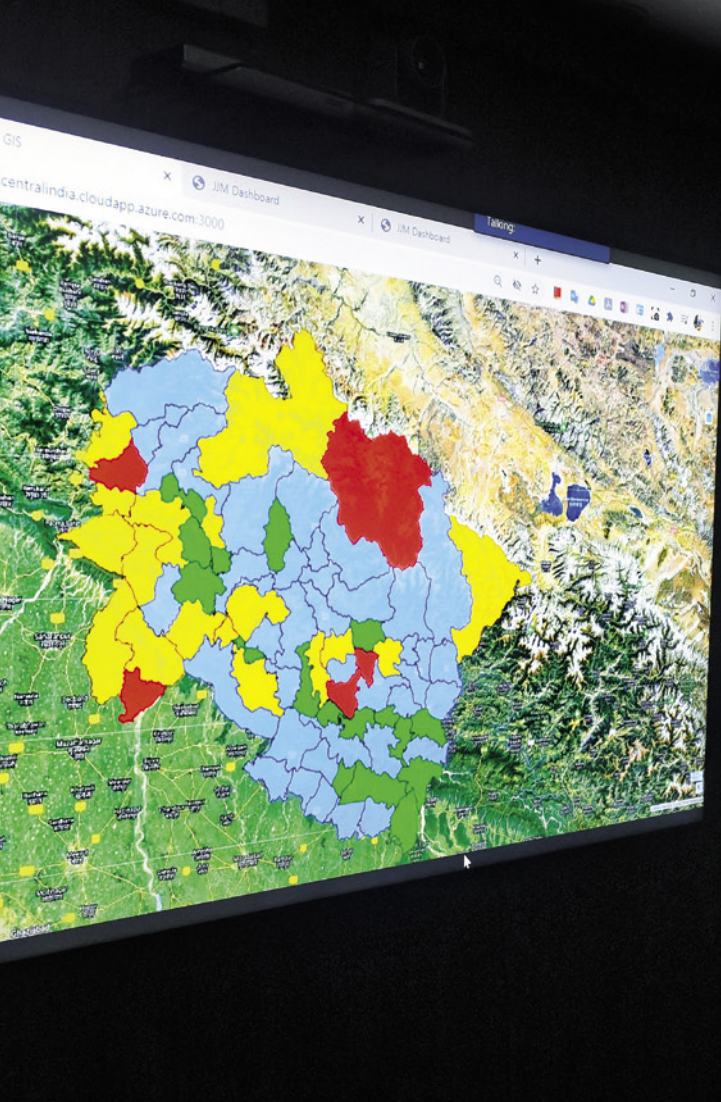
रोकड़ा कोई मसला नहीं है। इसे हासिल करने

के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने 3.26 लाख करोड़ रुपए अलग रख छोड़े हैं। मगर जल जीवन मिशन की टीम जो काम कर रही है, वह यह है कि नल का जल मुहैया करने के लिए जरूरी पाइप, नलों और दूसरे साजो-सामान के मानक रूपों के इस्तेमाल पर जोर देने और मिशन की प्रगति पर नजर रखने के लिए बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाए। लाल देश के किसी भी जिले या गांव पर ध्यान गड़ा सकते हैं और वहां बुनियादी ढांचा लगाने और नलों में पानी आने के बारे में हुई प्रगति का पता लगा सकते हैं। यही वह लगातार निगरानी है जो न केवल जलापूर्ति की मात्रा पक्की करती है बल्कि इससे उसकी गुणवत्ता की भी जांच की जा रही है।

लाल ने ही 2000 के दशक के मध्य में गुजरात की पुरस्कार विजेता जल आपूर्ति और स्वच्छता योजना की अगुआई की थी। लिहाजा वे जल जीवन कार्यक्रम को जमीन पर उतारने की जटिलताओं से बखूबी वाकिफ हैं। अपने लक्ष्य पूरे करने में पिछड़ रहे राज्यों की बहानेबाजी से वे अधीर हो उठते हैं। उनके तई सामुदायिक भागीदारी ही यह पक्का करने की कुंजी है कि नल का जल न केवल हरेक घर में पहुंचे बल्कि अच्छे और सधे तरीके से संचालित भी किया जाए और यह टिकाऊ साबित हो।

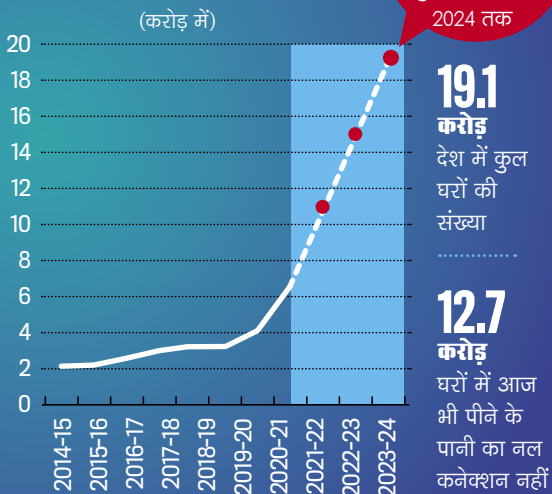
चंद्रदीप कुमार





बूंद-बूंद

देश को अभी लंबा सफर तय करना है क्योंकि अधिकांश ग्रामीण घरों में आज भी नल कनेक्शन नहीं



स्रोत: जल जीवन मिशन

ग्राफिक: तन्मय चक्रवर्ती

मिशन 'पानी समिति' की अवधारणा पर जोर दे रहा है जो जलापूर्ति की देख-रेख और संचालन के लिए ग्रामीणों और खासकर महिलाओं को ताकतवर बनाती है (देखें जहां महिलाओं का बोलबाला है)।

जल जीवन मिशन के तहत टैंकों का निर्माण, नल और बिजली के काम, जल गुणवत्ता प्रबंधन, जलशोधन, कैचमेंट या जलग्रहण सुरक्षा और संचालन और प्रबंधन सरीखे कार्य सामुदायिक भागीदारी के जरिए किए जाएं. लाल कहते हैं, "हरेक घर में नल का कनेक्शन मुहैया करना देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए बेहद अहम और जरूरी है. पानी भरकर लाने की यंत्रणा महिलाओं को झेलनी पड़ती है और अगर घर पर सुचारू नल न हो तो इसका मतलब है कि उनका बहुत सारा समय और ऊर्जा जाया होती है. नल उन्हें कड़ी मशक्कत से बचाता है और ताकत देता है. घर पर शोधित पानी की आपूर्ति का मतलब कम बीमारी और कम खर्च भी है. कुल मिलाकर, इससे खासकर महिलाओं के लिए जिंदगी कहीं ज्यादा आसान और अच्छी होगी."

जल स्रोतों की निरंतरता पक्की करने के लिए मिशन जल संग्रह की तकनीकों के जरिए स्थानीय जल स्रोतों को बढ़ाने और मजबूत करने पर भी ध्यान दे रहा है. ग्रामीणों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे अपशिष्ट पानी का शोधन करके उसे काम में लाएं और खेती-किसानी के कामों में उसका इस्तेमाल करें. टैंकों का निर्माण, पानी के पाइप बिछाना और नल लगाना ग्रामीण तकनीशियनों के लिए रोजगार का विशाल स्रोत है. इससे उन्हें रोजगार मिला है तो स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा. अगर जल जीवन मिशन अपने वादे पर खरा उतरता है तो यह 2024 तक ग्रामीण भारत का कायापलट कर देगा. ■



जहां महिलाओं का बोलबाला है

साल दर साल जल संकट से
जूझ रहे गुजरात के एक गांव
की महिलाओं ने पाइप से
जल आपूर्ति का प्रबंधन अपने
हाथों में लिया और उनकी
किस्मत बदल गई

राज चेंगप्पा


महिलाएं सबसे ऊपर
मोतीपुरा वेदा मे पानी
समिति की सदस्याएं



य

ह याद करते हुए अब भी गीता बेन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि 22 साल पहले जब वे हसमुख भाई से शादी करके गुजरात के गांधीनगर में उनके गांव मोतीपुरा वेदा आई थीं तब उन्हें पानी के लिए रोज कितनी जहोजहद करनी पड़ती थी. उन्हें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पर्याप्त पानी भरकर लाने की खातिर तीन किलोमीटर दूर लगे नलकूप के कई चक्कर लगाने पड़ते थे. गांव में उनकी और 1,000 दूसरे लोगों की जिंदगी उस वक्त नाटकीय ढंग से बदल गई जब नर्मदा नदी से पानी लेकर आने वाला एक पाइप 2004 में उनके गांव के नजदीक लगा दिया गया. लगभग उसी वक्त गुजरात के जल और स्वच्छता प्रबंधन संगठन (डब्ल्यूएसएमओ या वास्मो) ने गांवों में पानी की आपूर्ति के लिए व्यापक सामुदायिक भागीदारी वाली एक अभिनव योजना लॉन्च की. यह योजना भुज के गांवों में पानी पहुंचाने के लिए पहले ही आजमाई जा चुकी थी.

वास्मो के अफसरों ने मोतीपुरा वेदा के बाशिंदों से कहा कि अगर ग्रामीण 10 फीसद लागत का योगदान देने को राजी हों तो वे 16.5 लाख रुपए की लागत से 50,000 लीटर की क्षमता के एक ऊंचे जलाशय का निर्माण करेंगे. यह ग्रामीण ही तय करेंगे कि पंप-हाउस और भूमिगत स्टोरेज टैंक सहित जलाशय कहां स्थित हों. गांव की महिलाओं ने पुरुषों पर जोर डाला कि वे गांव के योगदान के तौर पर 1.65 लाख रुपए दें. जलाशय जल्द ही बन गया. वास्मो के अफसर जानते थे कि मानवबल को खपाने और लागत में इजाफा करने के बजाए सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि हरेक घर को बराबर पानी की सप्लाई पक्की की जाए और पाइपलाइन के रख-रखाव की जिम्मेदारी गांव के लोगों को ही सौंप दी जाए. वास्मो के चीफ इंजीनियर दीपक रामचंदानी कहते हैं, “यह मोतीपुरा के ग्रामीणों के लिए सच्चा स्वराज था. उन्हें न केवल यह तय करना था कि ऊंचा जलाशय कहां बने बल्कि पानी का सुचारु वितरण भी पक्का करना था.”

वास्मो ने ग्रामीणों को ‘पानी समिति’ गठित करने के लिए प्रोत्साहित किया. इसके नौ में से आधे सदस्य अनिवार्य तौर पर महिलाओं को बनाया जाना था. वास्मो ने जो 1.65 लाख रुपए इकट्ठा किए थे, उन्हें समिति के बैंक खाते में सावधिक जमा के तौर पर रख दिया गया ताकि यह बार-बार होने वाले खर्चों के लिए जमापूंजी का काम करे. पता यह चला कि मोतीपुरा गांव ने सभी महिलाओं की पानी समिति चुनने का फैसला किया.

समिति ने अलग-अलग घरों के लिए पानी का शुल्क इस तरह तय किया कि समिति की तरफ से तय समय पर पानी की आपूर्ति का इंतजाम करने के लिए ऑपरेटर रखने की लागत भी उसमें आ जाए. इस ऑपरेटर को रोजमर्रा का रख-रखाव भी करना था जिसमें टैंक को साफ रखना और पानी की शुद्धता का स्तर बनाए रखना शामिल था. पानी समिति ने तय किया कि पानी की आपूर्ति के लिए हरेक घर को सालाना 300 रुपए का शुल्क अदा करना

 98%

गुजरात के कुल 18,191 गांवों का जल आपूर्ति प्रबंधन वहां का समुदाय ही करता है

“यह मोतीपुरा के ग्रामीणों के लिए सच्चा स्वराज था. उन्हें न केवल यह तय करना था कि ऊंचा जलाशय कहां बने बल्कि पानी का सुचारु वितरण भी पक्का करना था”

दीपक रामचंदानी
चीफ इंजीनियर, वास्मो, गुजरात

बड़ी तस्वीर

- **समस्या:** मोतीपुरा गांव की महिलाएं पानी लाने के लिए दूर जाने के लिए बाध्य थीं
- **समाधान:** पाइप से जल आपूर्ति शुरू हुई. इसका प्रबंधन पानी समिति के जिम्मे है, जिसकी सारी सदस्याएं महिलाएं ही हैं

होगा. पैसा सीधे समिति के बैंक खाते में जमा करवाया जाएगा और रख-रखाव के अलावा परिचालन लागत में खर्च किया जाएगा. इस बीच गुजरात सरकार ने पंप चलाने के लिए बिजली आपूर्ति का खर्च माफ कर दिया ताकि पानी का शुल्क भारी न पड़े.

गीता बेन मोतीपुरा की पानी समिति की संयोजक हैं. वे कहती हैं कि ऊंचे जलाशय और पाइप से मिलने वाले पानी ने गांव की महिलाओं की जिंदगी का कायापलट कर दिया है. पहले नलकूप से पानी लाने में उनका बेटा उनकी मदद करता था. गीता बेन की पानी की जहोजहद बहुत आसान हो चुकी है. वे हर सुबह अपने रसोईघर में नल खोलती हैं और पानी से 20 मटके भर लेती हैं. इससे उनकी खाना पकाने और कपड़े धोने की सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं.

गीता बेन कहती हैं कि पानी भरकर लाने की यंत्रणा से मुक्त होने के बाद अब उनके पास इतना सारा वक्त होता है कि वे अपने बेटे को उसके होमवर्क में मदद करने के साथ-साथ कई दूसरे घरेलू काम भी कर लेती हैं. मोतीपुरा गांव की दूसरी महिलाओं के पास भी सुनाने के लिए ऐसी ही कहानियां हैं. पानी समिति योजना इस कदर कामयाब रही है कि अगस्त 2020 तक गुजरात के कुल 18,191 गांवों में से 17,899 या 98 फीसद गांवों को पाइप से पानी की आपूर्ति की जाती है और इसकी देख-रेख भी समुदाय ही करता है. पानी समितियों के जरिए महिलाओं को ताकतवर बनाने का गुजरात मॉडल देश के बाकी हिस्सों के लिए भी अनुकरणीय है. ■



सीधे दहलीज पर

सिंदरथ गांव में एक घर पर नल से जल की आपूर्ति



बंदिप सिंह

हर घर नल की ताकत

पीने का पानी सीधे दहलीज पर लाकर 'हर घर नल से जल' योजना ग्रामीण भारत में हजारों महिलाओं को ताकतवर बना रही है

रोहित परिहार

जयपुर से 410 किलोमीटर दूर और राजस्थान के सिरोही कस्बे के नजदीक सिंदरथ गांव उत्साह और चहल-पहल से गुलजार है। घरों में नलों से पीने का पानी पहुंचने लगा है। इससे महिलाओं को सामुदायिक टैंक और नलों पर पानी भरने के लिए लंबी कतारों में खड़े होने से निजात मिल गई है। 38 वर्षीया ज्योत्सना पुरोहित कहती हैं, "मैंने अपनी शादी के 21 में से ज्यादातर साल पानी के लिए कतार में इंतजार करते बिताए हैं।" अब जब पानी सीधे दहलीज पर आने लगा है, उनकी 17 साल की बेटी अरुणा को उम्मीद है कि उसे पढ़ाई के लिए ज्यादा वक्त मिल सकेगा। सिंदरथ में पानी

का संकट बढ़ती आबादी की वजह से भूमिगत जल पर दबाव बढ़ने के साथ 20 साल पहले शुरू हुआ था।

पानी में फ्लोराइड की बढ़ती मात्रा की वजह से ज्यादातर बोरवेल बेमतलब हो गए थे।

बड़ी तस्वीर

- **समस्या:** ग्रामीण इलाकों में पेयजल की कमी, पानी के लिए लोग दूर तक जाने को मजबूर होते थे
- **समाधान:** 'हर घर नल से जल' कार्यक्रम का उद्देश्य 2024 तक ग्रामीण इलाकों के सभी घरों तक पाइप के जरिए पानी पहुंचाना है। इसके लिए मामूली शुल्क लिया जाता है

2019 में आशा की एक किरण उभरी—केंद्र-राज्य के धन से जल जीवन मिशन के तहत 'हर घर नल से जल' कार्यक्रम। इस परियोजना का उद्देश्य 2024 तक हरेक ग्रामीण घर में सुचारू घर नल कनेक्शन (एफएचटीसी) लाना है। सिंदरथ राजस्थान के 397 गांवों में से एक है जहां प्रत्येक घर में एफएचटीसी पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अफसरों को यह पक्का करने की हिदायत दी है कि 2024 की आखिरी समय सीमा तक 43,000 गांवों के 1 करोड़ घरों में नल का कनेक्शन लग जाए।

इस कार्यक्रम के तहत केंद्र ने स्कूल और आंगनवाड़ियों सहित ग्रामीण संस्थाओं में भी एफएचटीसी पहुंचाना तय किया है। बदले में उनसे इस्तेमाल और रख-रखाव की लागत के आधार पर सेवा शुल्क वसूल किया जाएगा।

नल का पानी हासिल करने के लिए सिंदरथ के 525 में से हरेक परिवार ने 1,000 रुपए अदा किए हैं। यह उस 5 फीसद योगदान का हिस्सा है जो परिवारों ने परियोजना की 1.18 करोड़ रुपए की लागत में दिया है। इसमें 5 फीसद पंचायत भी देती है। ग्राम समिति एक बार दिया जाने वाला फाइनल शुल्क और सरकारी मासिक शुल्क तय करेगी। सरपंच शिवराज सिंह कहते हैं, "इंजीनियर सप्लाई के लिए जरूरी प्रेशर और वॉल्यूम की जांच कर रहे हैं। गांव के भीतर अलग-अलग क्लस्टर के लिए सप्लाई के घंटे तय किए जाएंगे और उसके बाद ही मासिक बिल आएगा।"

'हर घर नल से जल' योजना ने हजारों लोगों को लंबी दूरी से पानी भरकर लाने की यंत्रणा से मुक्ति दिलाने की उम्मीद जगा दी है। मुख्यमंत्री गहलोत कहते हैं, "मैं रेगिस्तान के इलाके का हूँ और जानता हूँ कि घर पर पानी की सप्लाई मिलना परिवारों को कितना ताकतवर बना देता है।"

स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों ने सिंदरथ के कई परिवारों के मनोबल और स्वाभिमान में इजाफा किया। जल जीवन मिशन एक और गेमचेंजर है जो लोगों को आर्थिक ताकत दे सकता है। ज्योत्सना कहती हैं कि पानी की कतार में खड़े होने से बचे समय का उपयोग वे सिलाई के काम में करके कुछ और धन कमाएंगी. ■

जुगत से आया जल

वर्षा जल से वंचित सिक्किम का एक जिला
निरंतर जल संकट से उबरने के लिए हिमालय के
जलस्रोतों को कर रहा है पुनर्जीवित

रोमिता दत्ता

साल 2012 में जब 28 वर्षीया अलका छेत्री ने शादी की और दक्षिण सिक्किम के मुनग्राम गांव में रहने आ गई, तब उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी दूर-दराज से पानी भरकर लाना. छेत्री कहती हैं, “मैं दार्जीलिंग से आई थी और नल के पानी की आदी थी. चार किलोमीटर दूर झरने से पानी भरकर लाना मुझे बुरी तरह थका देता था. जिस पानी से कपड़े और सब्जियां धोती थीं फिर उसी पानी से मुझे बर्तन और शौचालय साफ करने पड़ते थे. अचानक मेरी जिंदगी पानी के इंतजाम के इर्दगिर्द घूमने लगी.” उनकी जिंदगी में बेहतरी तब आई जब धारा विकास योजना के फायदे दक्षिण सिक्किम के कोने-कोने में पहुंचने लगे. यह योजना ग्रामीण प्रबंधन और विकास विभाग (आरएमडीडी) ने हिमालय के पहाड़ी जलस्रोतों या धाराओं को फिर से जिंदा करने और ग्रामीण घरों में जल सुरक्षा पक्की करने के लिए 2008 में शुरू की थी.

एक अनुमान के मुताबिक दक्षिण सिक्किम के 80 फीसद ग्रामीण घर अपनी पानी की जरूरतों के लिए 1,500 धाराओं पर निर्भर हैं. दक्षिण और पश्चिम सिक्किम के जिलों में पानी की कमी है क्योंकि ये रेन शेडो इलाकों यानी



साफ पानी

मुनग्राम के लोग देवी थाने सोते के सोर्स टैंक से पानी लेते हैं

बड़ी तस्वीर

- **समस्या** दक्षिण और पश्चिम सिक्किम के जलस्रोत कैचमेंट क्षेत्र सूखने या उनके मौसमी स्वभाव की वजह से सूख रहे थे
- **समाधान** धारा विकास योजना के तहत वर्षा जल को रोकने, जलस्रोतों को रिचार्ज करने और स्रोतों को फिर से जिंदा करने के लिए पहाड़ों पर गहरे खोदे गए

पर्वतमालाओं से घिरे होने के कारण सूखे रह जाने वाले जमीन के टुकड़ों में आते हैं.

दशकों के दौरान जलग्रहण क्षेत्रों में गिरावट आने की वजह से पानी के कई सोते सूख गए. कई दूसरे सोते जैसे भी मौसमी हैं और सर्दियों के महीनों में सूख जाते हैं. आरएमडीडी के अध्ययन इस नतीजे पर पहुंचे कि पानी के स्रोतों को फिर से भरने के लिए उनके रास्ते में पड़ने वाली और भूजल इकट्ठा करके रखने वाली चट्टानी परतों यानी जलभरों का इस्तेमाल करना चाहिए. इसी के साथ धारा विकास ने आकार ग्रहण किया.

महसूस किया गया कि बहकर चले जाने वाले बारिश के पानी को रोकने के लिए पहाड़ी ढलानों पर गहरे खोदकर और जलभरों को फिर से भरकर धाराओं को जिंदा करने में मदद मिल सकती है. धाराओं के मुहानों के नजदीक ‘स्रोत टैंकों’ का निर्माण किया गया ताकि वे ग्रामीणों के लिए जलाशयों का काम कर सकें. लंगचोक कामारे पंचायत के धारा विकास अधिकार रूपिंदर राय कहते हैं, “इन गड्डों में इकट्ठा पानी रिसकर भूमिगत जल में चला जाएगा जिससे पानी के स्रोतों को भरने में मदद मिलेगी. हमने मुनग्राम में 40 हेक्टेयर में 4,000 गड्डे खोदे. इनमें से हर एक बारिश के दौरान करीब 1,300 लीटर पानी रोक सकता है.”

दक्षिण सिक्किम में 729 हेक्टेयर में कोई 73,000 गड्डे खोदे गए, जो 6-10 फीट चौड़े और 2.5 फुट गहरे हैं. इस काम के लिए लाए गए ग्रामीणों को मनरेगा का मेहनताना दिया गया. इससे पानी के करीब 80 सोते फिर से जिंदा करने में मदद मिली. मुनग्राम के देवी थाने सोते में, जो नवंबर के बाद सूख जाया करता था, फरवरी के आखिर में भी पानी था. गाद या तलछट निकालकर करीब 240 तालाबों को फिर से जिंदा किया गया.

धारा विकास का फायदा दक्षिण सिक्किम के करीब 2,00,000 लोगों को मिला है. 56 वर्षीया रनमयी गुरुंग कहती हैं, “पानी की जबरदस्त कमी के चलते मैं काफी वक्त से अपने करीबी और प्रिय लोगों को भी घर बुलाने से कतराती थी. अब और नहीं. मैं अक्सर अपनी बेटी, दामाद और नाती-नातिनों से मिलती हूं.” ■



जल विशेषांक  शहरी आपूर्ति

कतरा-कतरा बचाने की जरूरत

इंटरनैशनल वॉटर एजेंसी के अनुसार, 2050 तक कम से कम 30 भारतीय शहर भीषण जल संकट का सामना कर रहे होंगे. जल स्रोतों का कुप्रबंधन, दूषित आपूर्ति, जल वितरण नेटवर्क में लीकेज और भारी मात्रा में अनुपचारित अपशिष्ट जल को नदियों में बहा दिए जाने जैसी कई समस्याएं भारत के जल संकट के लिए जिम्मेदार होंगी

कौशिक डेका



अपर्याप्त

नगर निगम के टैंकर से
जरूरत का पानी भरते
दिल्ली के निवासी

साल

2019 की गर्मियों में चेन्नै के जलाशय सूख गए थे और अन्य जगहों से रोजाना 1 करोड़ लीटर पानी लाने के अलावा, सरकार के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। एक शहर जहां साल में औसतन 1,400 मिमी बारिश होती है—लंदन में होने वाली बारिश से दोगुने से भी अधिक—के लिए यह एक अभूतपूर्व स्थिति थी। केवल चेन्नै ही नहीं, पूरे भारत के शहरों को बड़े पैमाने पर जनसंख्या वृद्धि और अनियोजित तीव्र शहरीकरण के कारण पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। नेचर में प्रकाशित 2018 के एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया कि 2050 तक जयपुर दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा पानी संकट का सामना करने वाला शहर होगा जबकि चेन्नै का स्थान 20वां होगा। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) की 2020 की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि जनसंख्या में तेज वृद्धि के कारण 2050 तक 30 भारतीय शहर 'गंभीर जल संकट' का सामना कर रहे होंगे।

स्थिति पहले से ही चिंताजनक है। केंद्रीय जल आयोग की निगरानी वाले 91 सबसे महत्वपूर्ण जलाशयों में जल भंडारण का स्तर, हाल के वर्षों में उनकी कुल क्षमता के आधे से अधिक को कभी पार नहीं कर सका। चिंता बढ़ाने वाली बात यह है कि, लंबे समय तक भूजल के अंधाधुंध दोहन से अधिकांश भारतीय शहरों में भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है। सेंटर फॉर साइंस ऐंड एनवायरनमेंट के अध्ययन के अनुसार, भारत की शहरी जल आपूर्ति का 48 प्रतिशत भूजल से आता है—और 10 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में से सात में, भूजल स्तर दो दशकों में काफी गिर गया है।

सीमित आपूर्ति नेटवर्क के कारण शहरी निवासियों को भी संकट से जूझना पड़ता है। भारत की 34 प्रतिशत से अधिक आबादी शहरों में रहती है; हालांकि 31 प्रतिशत शहरी घरों में, ज्यादातर अनधिकृत कॉलोनियों—मलिन बस्तियों में पाइप से मिलने वाले पानी या फिर सार्वजनिक नलों से पेयजल की व्यवस्था नहीं थी। मौजूदा पाइपों के सूख जाने का खतरा भी मंडरा रहा है। अधिकांश शहर केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन की ओर से निर्धारित प्रति व्यक्ति रोजाना 135 लीटर जल आपूर्ति स्तर को नहीं छू सकते। आपूर्ति वाले पानी की गुणवत्ता भी

संदिग्ध रही है। पिछले साल 21 शहरों से एकत्र नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरे। नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का लगभग 70 प्रतिशत पानी दूषित है, जो हर चार में से तीन व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है। इस वजह से केंद्रीय जल मंत्रालय ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य 2024 तक सभी घरों में पाइप से पानी पहुंचाने के नेटवर्क का विस्तार करना है। इसकी सफलता राज्यों पर निर्भर है क्योंकि पानी राज्य का विषय है।

डब्ल्यूडब्ल्यूएफ संकट से निपटने के लिए नदी घाटियों की सेहत सुधारने, जलोत्सारण क्षेत्रों और जलप्लावित भूमि के संरक्षण जैसे प्रकृति आधारित समाधानों का प्रस्ताव करता है, लेकिन ये तरीके पानी की उपलब्धता की समस्या का समाधान करेंगे, वितरण की दिक्कतों का नहीं। वर्षा जल संचय भी एक अन्य प्रभावशाली समाधान माना जाता है और इसकी चर्चा खूब हुई लेकिन काम बहुत कम हुआ है। इसलिए, विशेषज्ञ एकीकृत दृष्टिकोण का प्रस्ताव रखते हैं, जिसमें वितरण नेटवर्क की दक्षता बढ़ाना और अपशिष्ट जल का उपयोग करना शामिल है। जल स्रोत सीमित हैं, इसलिए शहरों और लोगों को कुशल और विवेकपूर्ण उपयोग पर ध्यान देना चाहिए। स्थायी नीति की दिशा में यह पहला कदम होगा। ■

महानगरों की मुश्किल

अगले तीन दशकों में देश की शहरी आबादी में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी जिससे समस्या बढ़ेगी क्योंकि मौजूदा आपूर्ति ही मांग के मुकाबले अपर्याप्त है

40%

भारत की आबादी के 2030 तक शहरी क्षेत्रों में रहने का अनुमान है, जो कि 2011 के 34 प्रतिशत से बहुत अधिक है

31%

शहरी घरों में पाइप का पानी नहीं पहुंचता और न ही इनकी सार्वजनिक नल तक पहुंच है

67.3%

शहरी भारतीय घर पाइप वाले सीवर विसर्जन सिस्टम से नहीं जुड़े हैं

48%

शहरी जल आपूर्ति भारत में भूमिगत जल से की जाती है, ऐसी जानकारी सेंटर फॉर साइंस ऐंड एनवायरनमेंट ने दी है

स्रोत: संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग; राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, 2015-16; जनगणना 2011; केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन; सेंटर फॉर साइंस ऐंड एनवायरनमेंट

ग्राफिक: तन्मय चक्रवर्ती

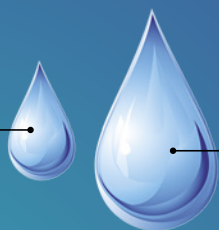


आपूर्ति का अंतर

भारत में स्थानीय शहरी निकायों की तरफ से पानी की सप्लाई का औसत

69.25

लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन



शहरों में पानी की जो मात्रा उपलब्ध कराए जाने की जरूरत है वह है

135

लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन

पानी बरकरार रखना जरूरी

देश के शहरों में रहने वाले 80 प्रतिशत घरों में पानी का स्रोत परिसर के भीतर है लेकिन इसे रिचार्ज रखना सबसे बड़ी चुनौती है

घर के बाहर लेकिन परिसर के भीतर

24.6%

200 मीटर से कम दूरी पर

13.8%

200 मीटर-500 मीटर

3.2%

500 मीटर-1 किमी

1.2%

1 किमी-1.5 किमी

0.5%

1.5 किमी से अधिक

0.6%

घर के भीतर

56.1%



सबसे ज्यादा जोखिम वाले 30 शहर

डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की इंडिया रिपोर्ट में अनुमान जाहिर किया गया है कि आबादी तेजी से बढ़ने के कारण निम्न शहर वर्ष 2050 तक गंभीर जल संकट से जूझेंगे

- | | |
|------------|-------------------|
| 1. जयपुर | 9. विशाखापट्टनम |
| 2. इंदौर | 10. बेंगलूरु |
| 3. ठाणे | 11. कोलकाता |
| 4. वडोदरा | 12. अहमदाबाद |
| 5. श्रीनगर | 13. जबलपुर |
| 6. राजकोट | 14. मुंबई |
| 7. कोटा | 15. लखनऊ |
| 8. नासिक | 16. हुबली-धारवाड़ |



- | | |
|--------------|--------------|
| 17. नागपुर | 24. भोपाल |
| 18. चंडीगढ़ | 25. ग्वालियर |
| 19. अमृतसर | 26. सूरत |
| 20. लुधियाना | 27. दिल्ली |
| 21. जालंधर | 28. अलीगढ़ |
| 22. पुणे | 29. कोझिकोड |
| 23. धनबाद | 30. कुन्नूर |



यासिर इकबाल

जायजा

आइआइटी दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी के प्रोफेसर टी.आर. श्रीकृष्णन बारापुला नाले के किनारे

दोबारा शोधन ही समस्या का समाधान

दिल्ली पानी की अनेक चुनौतियों का सामना करती है जिसे बढ़ती मांग व कम सप्लाई और गंभीर बना देती है. इससे पार पाने के लंबे वक्त के समाधानों के लिए अनेक प्रयास करने होंगे और इसमें महत्वपूर्ण होगा पड़ोसी राज्यों का सहयोग

कौशिक डेका



पानी की खपत के मामले में हालांकि दिल्ली को विशेष दर्जा हासिल है. यहां रोज प्रति व्यक्ति 240 लीटर पानी की खपत होती है जो देश में सबसे ज्यादा है.

लेकिन यह आंकड़ा एक बदनुमा हकीकत छिपा लेता है. राजधानी के प्राकृतिक जल स्रोत जो मुख्य रूप से यमुना और भूमिगत जल हैं, इसकी मांग पूरी करने के लिए नाकाफी हैं. इसे इस तरह देखें: 2019 में दिल्ली में रोज औसतन 1,22.2 करोड़ लीटर पानी की कमी थी.

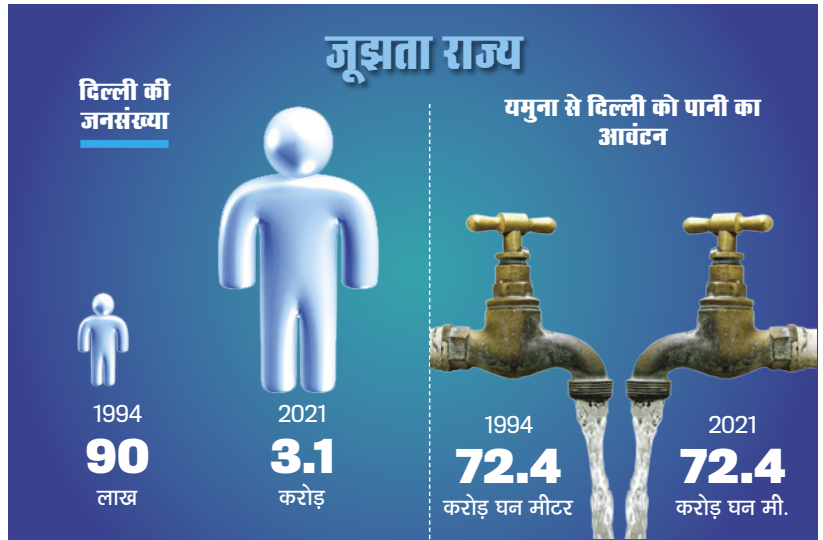
जहां तक यमुना की बात है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली की सरकारों ने 1994 में इस नदी के पानी के बंटवारे को लेकर समझौते पर दस्तखत किए थे. इसके तहत दिल्ली को हर साल 72.4 करोड़ घन मीटर पानी लेने की इजाजत दी गई थी. दिल्ली का हिस्सा आज भी उतना ही है जबकि इसकी आबादी में तब से करीब 2.2 करोड़ का इजाफा हो चुका है. भूजल की स्थिति भी बेहतर नहीं है. जमीन के नीचे से लगातार बहुत ज्यादा पानी उलीचने के चलते भूजल स्तर बीते 20 सालों में करीब आधा रह गया है. शहर का जलापूर्ति नेटवर्क भी मरणासन्न है.



हालांकि दिल्ली जल बोर्ड का कहना है कि उसका पाइप नेटवर्क 93 फीसद आबादी तक पहुंचता है, लेकिन दिल्ली के 2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण में अनुमान जाहिर किया गया है कि सप्लाई का 40 फीसद पानी रिसाव और चोरी की भेंट चढ़ जाता है।

पानी की कमी से निपटने का एक तरीका यह है कि शोधित पानी का उत्पादन और इस्तेमाल बढ़ाया जाए. ऐसे पानी का इस्तेमाल कृषि, निर्माण और उद्योग सहित कई क्षेत्रों में किया जा सकता है. इससे यमुना में हो रहे जबरदस्त प्रदूषण में भी कमी आएगी. हाल के सालों में इंडो-डच सहकारी प्रयास लोटस-एचआर (लोकल ट्रीटमेंट ऑफ अर्बन सीवेज स्ट्रीम्स फॉर हेल्दी रियूज) सरीखी कई अभिनव परियोजनाएं शुरू की गई हैं. यह परियोजना बारापूला नाले से निकले गंदे पानी को लेकर प्रयोग कर रही है. आइआईटी दिल्ली के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के प्रोफेसर टी.आर. श्रीकृष्णन की अगुआई में आइआईटी दिल्ली, टेरी (ऊर्जा और संसाधन संस्थान) और नीरी (राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान) के शोधकर्ताओं की एक टीम डच संस्था के साथ मिलकर 2017 से ही बारापूला के नाले के गंदे पानी से इस्तेमाल होने लायक शोधित पानी हासिल करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है. प्रोफेसर श्रीकृष्णन कहते हैं, “हम पारंपरिक प्रदूषक तत्वों और भारी धातुओं, दवाइयों के अवशेष, पर्सनल केयर प्रोडक्ट के अवशेष और ऐंटीबायोटिक के प्रतिरोधक सूक्ष्मजीवों सरीखे उभरते दूषक पदार्थों को गंदे पानी से हटाने के लिए टेक्नोलॉजी के असर और दक्षता की जांच कर रहे हैं.” परियोजना के नतीजों का इस्तेमाल कर देश भर में जलशोधन संयंत्रों के लिए टेक्नोलॉजी का टूलबॉक्स बनाया जाएगा.

अलबत्ता जलशोधन कहानी का एक हिस्सा भर है. इससे निकले पानी का इस्तेमाल भी किया जाना चाहिए. इस मामले में दिल्ली में शोधित किया जा रहा 30 फीसद पानी इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा है. इस पानी का इस्तेमाल मिसाल के लिए डीडिए (दिल्ली विकास प्राधिकरण) और एमसीडी (दिल्ली नगर निगम) के बगीचों को सींचने के लिए किया जा सकता है, जो फिलहाल इस काम के लिए भूमिगत पानी उलीच रहे हैं. मगर इस बदलाव के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे की खातिर वित्तीय समर्थन देने की राजनैतिक इच्छाशक्ति के साथ सरकारी महकमों के बीच सहयोग की



ग्राफिक: तन्मय चक्रवर्ती

बड़ी तस्वीर

● **समस्या:** आबादी बढ़ रही है और बढ़ती ही जाएगी तथा कच्चे पानी की सप्लाई स्थिर है और जर्जर सप्लाई नेटवर्क के साथ चोरी और लीकेज की भेंट चढ़ जाता है पानी

● **समाधान:** अपशिष्ट जल का ज्यादा से ज्यादा शोधन और इस्तेमाल किया जाए. पानी की अंतरराज्यीय हिस्सेदारी को बेहतर बनाने के साथ पाइपलाइन से पानी की बर्बादी को कम किया जाए

भी जरूरत है. नालियों के संशोधित पानी की आपूर्ति के लिए पीने के पानी से अलग दोहरी पाइपलाइन नहीं होने सरीखे बुनियादी ढांचे के अभाव की वजह से अप्रयुक्त संशोधित पानी की घरों में आपूर्ति तक नहीं हो पाती. कई विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा घरों में दोहरी पाइप लगाना व्यवहार्य नहीं है, लेकिन नए निर्माणों में भी इसे अनिवार्य बनाने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है. एक और विकल्प यह है कि नाली के पानी को पीने लायक बनाने के लिए उसे आगे और ज्यादा संशोधित किया जाए, लेकिन नाली के संशोधित पानी के उपभोग को लेकर कायम नकारात्मक धारणा के चलते इस विकल्प की छानबीन किए जाने की संभावना नहीं है. दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ निखिल कुमार कहते हैं, “नाली के पानी को पीने लायक स्तर तक शोधित करने की टेक्नोलॉजी मौजूद है. लेकिन इसके

खिलाफ एक मानसिक रुकावट है और इसकी वजह से पीने के पानी की आपूर्ति के लिए केवल नदियों या भूमिगत जल स्रोतों का पानी ही इस्तेमाल किया जाता है.”

प्राकृतिक जल की आपूर्ति बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार कुछ नए-नवेले समाधान लेकर आई है, मसलन, जलाशयों को भरने और उन्हें फिर से रिचार्ज करने की गरज से बारिश के अतिरिक्त पानी का इस्तेमाल करने के लिए यमुना के बाढ़ वाले मैदानों में जलाशय बनाना और बहकर बेकार जाने वाले संशोधित पानी का इस्तेमाल करके कृत्रिम झीलें बनाना. उसने पाइप जल नेटवर्क से बाहर छूट गए नागरिकों के लिए नए जलशोधन संयंत्रों का निर्माण किया है, पाइपलाइन बिछाई हैं और जल एटीएम भी बनाए हैं.

अलबत्ता दिल्ली की पानी की तकलीफों का दीर्घकालिक समाधान करने के लिए पड़ोसी राज्यों के बीच पानी के बेहतर बंटवारे की जरूरत है. मिसाल के लिए, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के पास प्राकृतिक जल के विपुल स्रोत हैं, वहीं उनका करीब 90 फीसद पानी कृषि और उद्योगों में इस्तेमाल किया जाता है. बेहतर बंटवारे का एक उदाहरण यह होगा कि दिल्ली का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा संशोधित पानी उद्योगों और कृषि के लिए सप्लाई किया जाए, जबकि पड़ोसी राज्य अपना प्राकृतिक पानी राजधानी की खपत के लिए दे दें. निखिल कुमार कहते हैं, “हमने पड़ोसी राज्यों को यह प्रस्ताव दिया है. ऐसे आदान-प्रदान जल संकट से लड़ने में राष्ट्र की मदद कर सकते हैं. हमें ‘पहले मैं’ की बजाए ‘पहले हम’ नजरिए की जरूरत है.” ■

सप्लाई का निजीकरण

अलहदा सोच और समाज का सहयोग पानी उपलब्ध कराने और लीकेज रोकने में मददगार रहा

किरण डी. तारे

नागपुर

महाराष्ट्र



सबकी मुस्कान

संघर्षनगर के हर घर का अब अपना नल है

मंदार देवधर

नागपुर के उपेक्षित इलाके संघर्षनगर निवासी सोनू उकेय का कहना है कि दो साल पहले जब उनकी शादी हुई थी तब उन्होंने सास के मुंह से सार्वजनिक नल से पानी लाने से जुड़ी परेशानियों की डरावनी कहानियां सुनी थीं. अब, करीब 100 परिवारों की इस बस्ती में हर घर के बाहर अपना नल लगा है. सोनू बताती हैं, “सासुबाई कहती हैं कि दरवाजे पर पानी मिल जाने से रोजाना हमारा तीन घंटे का समय बच रहा है.”

उकेय की यह खुशी नागपुर नगर निगम (एनएमसी) की परिकल्पित उस 24x7 जल आपूर्ति योजना की सफलता की देन है जिसे एक निजी कंपनी ऑरेंज सिटी वाटर (ओसीडब्ल्यू) साकार कर रही है. ओसीडब्ल्यू एक फ्रांसीसी कंपनी, वेओलिया एनवायरनमेंट एस.ए की सहायक कंपनी है. 2012 तक नागपुर में पानी की स्थिति विकट थी. शहर के 27 लाख निवासियों में से लगभग 2,50,00 को पानी आसानी से उपलब्ध नहीं था. सैकड़ों निवासी, ज्यादातर झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले, हर साल गर्मियों में पानी किल्लत के विरोध में ‘मटका मार्च’ निकालते हुए एनएमसी कार्यालय तक जाते थे. यह स्थिति नागपुर को आसपास की चार

बड़ी तस्वीर

● **समस्या:** साल 2012 से पहले नागपुर में गंभीर जलसंकट था

● **समाधान:** पाइपलाइन नेटवर्क, पानी कनेक्शन और बिलिंग सिस्टम पर जोर देते हुए पानी सप्लाई का प्रबंधन निजी हाथों में देना

नदियों से पर्याप्त पानी उपलब्ध होने के बावजूद थी.

2012 के बाद स्थिति बदलने लगी जब एनएमसी ने नागपुर में पानी के प्रबंधन और वितरण कार्य के लिए ओसीडब्ल्यू के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए. 550 करोड़ रुपये के पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल प्रोजेक्ट के दो बड़े लक्ष्य थे—हर घर में पानी की आपूर्ति और पानी की बर्बादी को 60 से घटाकर 25 प्रतिशत पर ले आना. आज, वे मीटर के साथ पानी के 2,50,000 नए कनेक्शन देने में सफल रहे हैं और शहर को 660 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रति दिन) पानी की आपूर्ति करते हैं. करीब छह लाख लोगों या 25 प्रतिशत आबादी को अब

24x7 पानी मिलता है. प्रत्येक निवासी को एक दिन में 130 लीटर से अधिक पानी (दुनियाभर में इस मात्रा को आदर्श माना जाता है) मिलता है. ओसीडब्ल्यू के संस्थापकों में से एक और अब विश्वराज एनवायरनमेंटल के सीएमडी अनिल लखानी कहते हैं, “हम परंपरागत तरीके से अलग विचारों, सामुदायिक जुड़ाव और कड़ी मेहनत के कारण यह कर सके हैं.”

ओसीडब्ल्यू ने 600 किमी नई पाइपलाइन बिछाई है और लगभग 3,000 किमी पाइपलाइन के रखरखाव का काम भी करती है. कंपनी जल के प्रति जनता को संवेदनशील बनाने के लिए कार्यक्रम भी चलाती है. एक बड़ी चुनौती मीटर लगाने की थी. शुरुआत में, निवासियों ने इस आशंका से मीटर लगाने का विरोध किया कि इसका बिल बहुत अधिक आएगा लेकिन धीरे-धीरे वे राजी हो गए.

एनएमसी आयुक्त बी. राधाकृष्णन कहते हैं, “पानी की गुणवत्ता में सुधार के साथ, बिल संग्रह प्रक्रिया को भी दुरुस्त किया गया है. अभी 65 कमान क्षेत्रों में से 24 को 24x7 पानी मिल रहा है. हम और इलाकों में भी पानी की निरंतर आपूर्ति की व्यवस्था की योजना बना रहे हैं.” ■

नदियां जुड़ीं, उद्योग बचे

नदियों को जोड़ने के एक पीपीपी प्रोजेक्ट ने देवास के नजदीक नर्मदा और क्षिप्रा को जोड़ा जिससे दम तोड़ते औद्योगिक शहर को जीवनदान मिल गया

राहुल नरोन्हा

व्या

वसायिक शहर इंदौर के करीब स्थित देवास में 1970 और '80 के दशक में तेजी से औद्योगीकरण हुआ. अनुकूल स्थान, रेलमार्ग से जुड़ाव और कच्चे माल तक अच्छी पहुंच की बदौलत, शहर ने कई कपड़ा इकाइयों, सोयाबीन प्रसंस्करण संयंत्रों और दवा संयंत्रों को आकर्षित किया. हालांकि, बाद के दशकों में शहर का यह वरदान उसके लिए अभिशाप बन गया.

1990 के दशक से, शहर में पानी की भारी किल्लत होने लगी. इसका कोई समाधान नहीं निकला और शहर की करीब 950 औद्योगिक इकाइयों में से लगभग 60 प्रतिशत बंद हो गईं. देवास इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक खंडेलिया कहते हैं, “हमने मजदूरों को नौकरियां गंवाते और फैक्ट्रियों को दिवालिया होते देखा, विशेषकर उन्हें जहां पानी की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है.”

सहस्राब्दी की शुरुआत से, समस्या के समाधान के लिए बड़े प्रयासों की योजना बनाई जाने लगी थी. 2007 में, देवास से 120 किलोमीटर दूर स्थित नर्मदा से पानी लाने की कोशिश में एक परियोजना शुरू हुई. हालांकि, इंजीनियरिंग की समस्याओं के कारण यह प्रयास विफल रहा. 2018 में एक नया प्रयास किया गया—देवास इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट (डीआईडब्ल्यूएसपी) को एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत लॉन्च किया गया. इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी वेलस्पन ने मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर इस चुनौती को स्वीकार किया. पिछले प्रयास की विफलता को देखते हुए, इंजीनियरिंग में काफी बदलाव किए गए.



उद्योगों पर जोर
देवास इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट

यासिर इकबाल

डीआईडब्ल्यूएसपी में नर्मदा से क्षिप्रा को जोड़ने पर काम शुरू हुआ जो देवास से होकर बहती थी, लेकिन अत्यधिक दोहन के कारण सूख गई थी. नर्मदा-क्षिप्रा लिंक राज्य की पहली बड़ी नदी-जोड़ने वाली परियोजना थी, जिसमें शहर की औद्योगिक जरूरतों और पीने के पानी की आपूर्ति के साथ राज्य के अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी लाभ पहुंचा.

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (एनवीडीए), मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम और वेलस्पन के बीच 2037 तक आपूर्ति किए जाने वाले पानी की मात्रा को लेकर एक समझौता हुआ है, जिसमें पिछले कुछ वर्षों में पानी की आपूर्ति की मात्रा 1

करोड़ लीटर प्रति दिन से बढ़कर 3 करोड़ लीटर प्रति दिन हुई है. एनवीडीए के मुख्य अभियंता अजय सिंघल कहते हैं, “नर्मदा से क्षिप्रा तक पानी की पम्पिंग, बड़े पैमाने पर इंटरलिंकिंग की पहली परियोजना थी. इसकी सफलता ने हमें राज्य में ऐसी अन्य परियोजनाएं शुरू करने का हौसला दिया है.”

वेलस्पन ने क्षिप्रा के तट पर एक पम्पिंग स्टेशन भी स्थापित किया, जहां से नदी के पानी को देवास औद्योगिक क्षेत्र में बने जल शोधन और उपचार संयंत्र में लाया जाता है. उपचारित होने के बाद, औद्योगिक इकाइयों को प्रति दिन 24 घंटे और प्रति यूनिट के आधार पर पानी की आपूर्ति की जाती है. पानी की उपलब्धता ने देवास औद्योगिक क्षेत्र में नई जान फूंक दी है. खंडेलिया कहते हैं, “देवास फिर से औद्योगिक गढ़ के रूप में खड़ा हो चुका है. 2018 के बाद से यहां रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है. 10,000 नई नौकरियां पैदा हो रही हैं और देवास 7,500 करोड़ रुपये के निर्यात ऑर्डर प्राप्त कर रहा है.” कई इकाइयां जिन्हें बीमार घोषित किया जा चुका था, वे फिर से चल पड़ी हैं और यह केवल पानी की उपलब्धता के कारण हुआ है. ■

बड़ी तस्वीर

● **समस्या:** तेजी से बढ़ते देवास शहर को जल संकट ने उद्योगों की कब्र बना दिया

● **समाधान:** पीपीपी के तहत साकार हुई नदी जोड़ने की एक परियोजना से क्षिप्रा में नर्मदा से पानी लाया जा सका

जल विशेषांक  संरक्षण

गुजरात का जलतंत्र

दो दशकों के भीतर भारी जल संकट वाले राज्य से पर्याप्त पानी की
उपलब्धता वाले सूबे में तब्दील होने के पीछे सिर्फ नर्मदा कैनाल नहीं है,
ऐसा वहां के दूरदर्शी नेतृत्व की वजह से मुमकिन हुआ

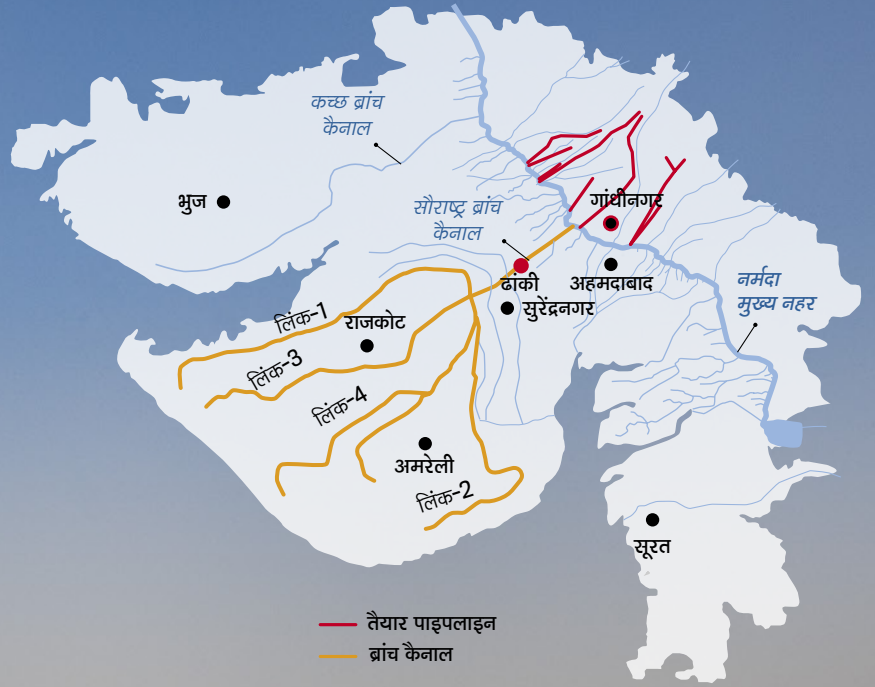
राज चेंगप्पा

फोटोग्राफ : बंदीप सिंह



पानी का भूगोल

मुख्य नर्मदा कैनाल से पानी सौराष्ट्र ब्रांच में ढांकी पहुंचता है और यहां से वाटर लिफ्टिंग तथा अनेक ब्रांच कैनाल के जरिए यह सूखे क्षेत्रों तक पहुंचाया जाता है



स्रोत: गुजरात वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन



पानी का उठान

ढांकी स्थित पंपिंग स्टेशन से नर्मदा कैनाल के पानी को 10.81 मीटर ऊपर उठाकर ढलान वाले सिस्टम में डाला गया है



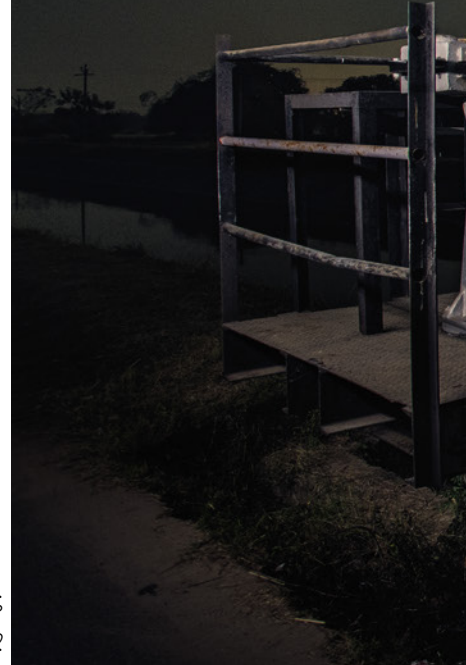
द

क्षिण और मध्य गुजरात के इलाकों से 458 किलोमीटर लंबी नर्मदा नहर हरे-भरे हाइवे की तरह सरपट गुजरती है। राज्य की राजधानी गांधीनगर से ज्यादा दूर नहीं, इस नहर की एक शाखा इस इलाके के धूल भरे मैदानों में स्थित विशाल पंपिंग स्टेशन ढांकी तक पानी ले जाती है। यहां से पानी को ऊंचाई पर ले जाने के अविश्वसनीय सिलसिले की पहली शुरुआत होती है, जो नहर के पानी को सूखाग्रस्त सौराष्ट्र इलाके तक पहुंचाती है। वही सौराष्ट्र जिसे पहले राज्य का केवल 17 फीसद पानी हासिल था। राज्य के प्रधान सचिव (जल) धनंजय द्विवेदी बताते हैं कि ऐसा इसलिए था क्योंकि “सौराष्ट्र उलटे कटोरे के आकार का है और नहर का पानी 69 मीटर या 23 मंजिला इमारत जितनी खड़ी चढ़ाई पर पंप करके ले जाना पड़ता था ताकि वह इलाके के हरेक हिस्से में पहुंच सके।” इसी तरह नहर की शाखाएं कच्छ के रेगिस्तान और उत्तर गुजरात के शुष्क इलाकों तक पानी ले जाती हैं। नर्मदा के पानी ने महज दो दशकों में राज्य के समूचे भूदृश्य और यहां के लोगों की जिंदगियों का कायापलट कर दिया है।

इस नहर का काम शुरू होने से पहले देश के सूखाग्रस्त भूभाग में बसा गुजरात हमेशा पीने और सिंचाई दोनों के पानी की कमी से त्रस्त रहता था। द्विवेदी याद करते हैं कि कई जिलों के डिप्टी कमिशनर के नाते उनका एक मुख्य काम पेयजल की जरूरतें पूरी करने के लिए पानी के टैंकों और यहां तक कि पानी की रेलों का इंतजाम करना होता था। *इंडिया टुडे* ने 2003 में ‘प्यासी धरती, प्यासे लोग’ शीर्षक से एक बड़ी स्टोरी की थी और तब उसकी आवरण तस्वीर में गुजरात के लिंबडी तालुका के एक गांव में सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ को एक बालटी पानी लेने के लिए एक कुएं को घेरे खड़े दिखाया गया था। गृहणी सोना वाघेला याद करती हैं कि किस तरह रोज उनके चार घंटे सूखे कुओं से पानी भरकर लाने में बीतते थे। वे कहती हैं, “ज्यादा से ज्यादा पानी लेने के लिए कहा-सुनी और कई बार तो मार-पीट तक होती थी। पूरे परिवार को कुएं पर भीड़ लगानी पड़ती थी क्योंकि एक सदस्य दो बालटी से ज्यादा पानी नहीं ले सकता था।” 2021 में लिंबडी का नजारा पूरी तरह बदल चुका है। सूखी झील लबालब भरी होने से इलाका पानी से भरपूर है और वाघेला के घर सहित अनेक मकानों में नल लगे हैं। यह सब इसलिए हो सका क्योंकि 2008 के आसपास नर्मदा नहर की एक ब्रांच इस इलाके में पानी की आपूर्ति करने लगी।

तो भी यह आसान कायाकल्प नहीं था और अगर यह कामयाब हुआ है तो नरेंद्र मोदी की दूरगामी दृष्टि की वजह से, जिन्होंने पहली बार 2001 में मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य की कमान संभाली थी जब नर्मदा नहर का निर्माण हो रहा था। मोदी ने अफसरों से कहा कि केवल नर्मदा नहर पर ही निर्भर न रहें बल्कि मौजूदा नहर प्रणालियों को भी मजबूत करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि पेयजल और सिंचाई के पानी का प्रबंधन भागीदारी से परिपूर्ण होना चाहिए। इसका मतलब था परियोजनाओं पर अफसरशाही के शिकजे को तोड़ना और बिल्कुल शुरुआत से ही इस काम में एनजीओ के साथ पानी के लाभार्थियों को भी शामिल करना। सबसे अहम बात यह कि मुख्यमंत्री के तौर पर मोदी ने पानी आपूर्ति का बुनियादी ढांचा खड़ा करने के लिए धनराशि अलग रखी, क्योंकि वे जो सामाजिक-आर्थिक बदलाव लाना चाहते थे उसमें इसे सबसे अहम मानते थे। बीते दो दशकों में राज्य ने जल संसाधनों में कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है।

बंटीप सिंह



बड़ी तस्वीर

● समस्या:

साल 2000 तक गुजरात की गिनती पानी के लिए तरसते राज्यों में थी।

● समाधान:

नर्मदा कैनाल और उसके बाद बने सब सिस्टम, खासकर पेयजल और सिंचाई के पानी के प्रबंधन से राज्य में पर्याप्त पानी उपलब्ध हुआ



77%

की बढ़ोतरी दर्ज की गई सिंचित भूमि में जब से नर्मदा के पानी का पूरे राज्य में वितरण शुरू हुआ



95%

गुजरात के गांवों में 'पानी समितियां' हैं जो पानी सप्लाई का प्रबंधन करती हैं



सहज परिचालन

57 साल के ए.के. बरिया नर्मदा सब कैनाल के वाल्व को खोलते हुए जिससे उनके जैसे 600 किसानों के खेत तक पानी पहुंचता है। वे वाटर यूजर्स एसोसिएशन के सचिव हैं, जिसके जिम्मे सिंचाई के पानी की देखरेख है। इसके सदस्यों से फीस ली जाती है और उससे कैनाल सिस्टम का रखरखाव किया जाता है

लिंगडी: 2003



लिंगडी: 2021



दुख-सुख

सुरेंद्रनगर जिले के लिंगडी तालुका में कुएं की यह तस्वीर, इंडिया टुडे के 11 जून, 2003 अंक के कवर पर छपी थी; सोना वघेला, जो उस तस्वीर में थीं, 2021 में उसी कुएं के पास खड़ी हैं। वह कुआं अब बड़े तालाब में डूब गया है



इफरात

सुरेंद्रनगर जिले के राजसीतापुर में चेक डैम पीपीपी आधार पर बनाया गया। इससे 38 वर्षीय महेश पटेल जैसे किसानों को साल में तीन फसल उगाने और वार्षिक आय बढ़ाने में मदद मिली



“हमेशा पानी संकट से जूझते गुजरात में अब पीने के लिए, सिंचाई के लिए और उद्योग के लिए पर्याप्त पानी है और इससे आर्थिक विकास का भी सूत्रपात हुआ है”

धनंजय द्विवेदी
प्रधान सचिव (जल)

आगा खान ग्रामीण सहायता कार्यक्रम के वाइस-प्रेसीडेंट, वाटर, इरिगेशन एंड पावर प्रोग्राम्स, अपूर्व अजय ओझा, जिन्होंने इस मिशन पर गुजरात सरकार के साथ नजदीक से मिलकर काम किया था, कहते हैं कि इस कामयाबी के पीछे तिहरे कारण थे। वे कहते हैं, “पहला, नरेंद्र मोदी ने पानी के मौजूदा स्रोतों को मजबूत करने की अहमियत को तुरंत पहचान लिया था, यहां तक कि तब भी जब नर्मदा नहर से राहत मिलने लगी थी। दूसरे, उन्होंने जल संरक्षण और विशेष रूप से ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। तीसरे, प्रबंधन के कामों के लिए इंजीनियरों पर निर्भर होने के बजाए उन्होंने एनजीओ को लोगों को शिक्षित करने के कामों में शामिल होने के लिए

प्रोत्साहित किया और संचालन संभालने के मकसद से पेयजल के लिए पानी समितियां या सिंचाई के पानी के वितरण के लिए वाटर यूजर एसोसिएशन का गठन कराया।”

फिर मोदी ने जल संसाधनों की साज-संभाल के लिए अफसरशाही के संगठन का स्वरूप बदलते हुए उसे एक छत्र संगठन के बजाए कामकाजी महकमों में बांट दिया। गुजरात वाटर सप्लाई और सीवरेज बोर्ड जल संसाधनों और नालियों के विकास और नियमन का प्रभारी बना रहा। जलापूर्ति सुविधाओं का संचालन और प्रबंधन करने के मकसद से ग्राम स्तरीय संस्थाओं को ताकतवर बनाने के लिए जल और स्वच्छता प्रबंधन संगठन (डब्ल्यूएसएमओ या वास्मो) बनाया गया। सरदार सरोवर निगम लिमिटेड को स्वायत्तशासी निकाय बना दिया गया जो सरदार सरोवर परियोजना को जमीन पर उतारने के लिए जिम्मेदार था। गुजरात वाटर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को नर्मदा का पानी लाने के मकसद से बल्क-वाटर पाइप ग्रीड का निर्माण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई।

गुजरात जल संसाधन विकास निगम (जीडब्ल्यूआरडीसी) भूमिगत जल के सर्वेक्षण, निगरानी और विकास के लिए जिम्मेदार स्वायत्तशासी निकाय बन गया। अफसरशाही के तंत्र को सरल और कारगर बनाने के बाद मोदी ने पानी और स्वच्छता के कामों से जुड़े संगठनों के लिए पांच बड़े क्षेत्र तय किए जिन पर उन्हें ध्यान देना था। इनमें जल संरक्षण, पानी को एक से दूसरे बेसिन में पहुंचाना और उन्हें आपस में जोड़ना, मौजूदा

नहर प्रणाली को मजबूत बनाना, पानी और सिंचाई का भागीदारी से परिपूर्ण प्रबंधन और माइक्रो-इरिगेशन या सूक्ष्म-सिंचाई शामिल थे। इस तरह एकाग्र ढंग से ध्यान देकर काम करने के बड़े नतीजे मिले—राज्य के सिंचाई योग्य क्षेत्र में 77 फीसद का इजाफा हुआ, भूमिगत जल का भराव 2002 के मुकाबले 55 फीसद ऊपर आ गया, और अब शुद्ध बुआई का 20 फीसद क्षेत्र सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत आ गया है। 1,84,000 से ज्यादा चेक डैम और 3,27,000 कृषि तालाब बनाए गए हैं। इसके अलावा 31,500 अन्य तालाबों को गहरा करके उनकी क्षमता बढ़ा दी गई है। साथ ही, बेकार मानकर छोड़ दी गई करीब 1,000 बावड़ियों को पुनर्जीवित और साफ-सुथरा करके इस्तेमाल किया जा रहा है।

अब 18,200 के आसपास (करीब 95 फीसद) गांवों में पानी समितियां हैं जो अपनी जलापूर्ति का काम संभालती हैं और बताती हैं कि भागीदारी वाले प्रबंधन ने गहरी जड़ें पकड़ ली हैं। द्विवेदी कहते हैं, “वह राज्य जो हमेशा पानी की कमी से जूझता रहता था, महज दो दशकों में ऐसे राज्य में बदल गया है जिसके पास पीने, खेती-किसान, पशुपालन, उद्योगों के लिए पर्याप्त पानी है और इसने आर्थिक वृद्धि का भी सूत्रपात किया है।” जल संसाधनों के मामले में मोदी मुख्यमंत्री के तौर पर जल प्रबंधन का सफल मॉडल विकसित करने का निश्चित तौर पर दावा कर सकते हैं। अब प्रधानमंत्री के तौर पर वे उन सबकों में से कुछ को देश भर में रोप रहे हैं जो उन्होंने गुजरात के अपने लंबे कार्यकाल में सीखे थे। ■



स्वच्छता की पहल

मदुरै के डीएचएन फाउंडेशन का काम ये साबित करता है कि बेकार हो चुके जल स्रोतों को नया जीवन देना मुमकिन है ताकि सिंचाई हो सके

मदुरै में सी. प्रवीणकुमार



मदुरै शहर के सूखे या गंदे तालाबों और जल निकायों के बीच इरावथानल्लूर में कडियानुर इरिगेशन टैंक अपने साफ पानी के लिए जाना जाता है. इरावथानल्लूर के रहने वाले एम. सेधुरामु बताते हैं, “तीन साल पहले आपका ध्यान केवल गंदे पानी पर जाता होगा, लेकिन अब यह साफ हो गया है, स्वच्छ है और 50 एकड़ से ज्यादा खेतों की सिंचाई में पानी देता है. स्थानीय लोगों के योगदान और डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमेन ऐक्शन यानी डीएचएन के अथक प्रयास से यह संभव हो पाया.” इसकी वजह वायलागम टैंकफेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम (वीटीएडीएस) है जिसने उन्हें इस असंभव से दिखने वाले कार्य के लिए प्रेरित किया.

बड़ी तस्वीर

- **समस्या** सीवर का पानी कडियानुर टैंक में घुसकर उसे बर्बाद कर रहा था
- **समाधान** स्थानीय लोगों और डीएचएन फाउंडेशन के अथक प्रयासों से टैंक की गाद निकालकर उसे साफ किया गया. टैंक 9 एकड़ में फैला है और इससे 50 एकड़ खेती की सिंचाई होती है

सेधुरामु कहते हैं, “हमने 2016 में डीएचएन फाउंडेशन को अप्रोच किया. इसके लिए उन्होंने पांच किसानों का चयन किया जिसमें तीन पुरुष और महिलाएं थीं. वे हमें कुछ जल निकायों को दिखाने के लिए बेंगलूरु ले गए जिन्हें पुनर्जीवित किया गया था. यह हमारा पहला अनुभव था जिसके आधार पर हमने कडियानुर टैंक का निर्माण करने की योजना तैयार की.”

उन्होंने सबसे पहले 9 एकड़ चौड़े कडियानुर टैंक के चारों ओर चारदीवारी बनवाई. टैंक के लिए पानी चोटाईथेटी कैनाल से आता है, लेकिन रास्ते में बहने वाले सीवेज की वजह से टैंक में केवल गंदा पानी ही बना रहता था. टीम ने प्राकृतिक, जैविक तरीके से पानी को शुद्ध करने के लिए कलवाजाई (कन्न ईडिका) प्लांट का इस्तेमाल किया.

इस प्रोजेक्ट के एजीक्यूटिव एस. लोकेश कहते हैं, “टैंक के पानी को बिना निर्बाध बहने के लिए कैनाल को इरावथानल्लूर की सीमा से लेकर 2 किलोमीटर तक के इलाके को 14 फीट चौड़ा कर दिया गया था. प्रवाह को रोकने वाले जलकुंभी को भी हटा दिया गया था.” गाद हटाने से इलाके में भूजल की गुणवत्ता सुधारी है. इस प्रोजेक्ट की लागत बड़ी समस्या थी. सेधुरामु गर्व से कहते हैं, “इसे बनाने में लागत 20 लाख रुपए आई, जिसमें से 18 लाख रुपए कुछ कॉर्पोरेट से आए जबकि 2 लाख रुपए लोगों से जुटाए गए.” वीटीएडीएस प्रोजेक्ट के लीडर एन. वेंकटेशन कहते हैं, “डीएचएन फाउंडेशन ने अब तक 2,000 से अधिक तालाबों और 104 जल निकायों का निर्माण किया है.” वीटीएडीएस को दक्षिण भारत के सभी सात राज्यों में लागू किया जा रहा है. स्थानीय लोग बढ़-चढ़कर अतिक्रमण हटाने में जुटे हैं और डिसिल्टिंग से संबंधित काम में भी शामिल हैं, इससे न केवल प्रोजेक्ट की लागत घटती है बल्कि लोगों को रोजगार भी मिलता है. ■



तीन साल की मेहनत
कडियानुर इरिगेशन टैंक में
अब निर्मल पानी है



खुद का नखलिस्तान

जल स्रोत विकसित करने की एक योजना और मौजूदा जल संसाधनों को समुचित इस्तेमाल में सुधार से सरकार ने पानी के मामले में सूबे को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए

रोहित परिहार



फायदा
टिकेल नारुकन गांव
के महेंद्र चौधरी

राजस्थान ऐसा राज्य है जिसके पास देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 10 फीसद है और करीब 5.2 फीसद आबादी वहां रहती है लेकिन इसके पास देश के कुल जल संसाधनों का महज 1.16 फीसद हिस्सा है। राज्य की 60 फीसद जमीन रेगिस्तान है और यहां बार-बार सूखा भी आता रहता है। जल संकट से



पुरुषोत्तम दिवाकर

निबटने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 2016 में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान (एमजेएसए) शुरू की थी। योजना राज्य के जल संसाधनों के संचयन, भंडारण और उसके इस्तेमाल को प्रभावी बनाने में सुधार के लिए शुरू की गई थी। 2016 से 2018 के बीच इसे तीन चरणों में लागू किया गया था और इसमें तालाब खोदकर नए जलस्रोत क्षेत्र बनाना और वृक्षारोपण के जरिए वर्षाजल संचयन का काम भी शामिल था। अभियान के तहत पूरे राज्य में 12,056 गांवों में 1.38 करोड़ पौधे रोपे गए और कुल 3,74,292 परियोजनाएं पूरी की गईं।

ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय में संयुक्त निदेशक सुशीला यादव कहती हैं, “इस योजना में कुल खर्च 5.059 करोड़ रुपए हुआ। हमने रिमोट सेंसिंग और जियो-टैग से निगरानी जैसी तकनीक अपनाई ताकि इसका प्रभावी तरीके से कार्यान्वित किया जा सके।” सरकार कहती है कि योजना से सिंचित क्षेत्र में 1,00,000 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है और भूजल स्तर में 1 से 10 मीटर की बढ़ोतरी हुई है। ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग, जो इस योजना का नोडल और कार्यकारी विभाग है, के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित आर.सिंह कहते हैं, “हम इस

बड़ी तरसीर

● **समस्या** मरुस्थलीय राज्य राजस्थान लगातार सूखे के साल देखता रहा है और किसी नदी का न होना हालात को और विकट बनाता है

● **समाधान** जलस्रोतों का उद्धार, बेहतर जल संचयन और उपलब्ध जल संसाधनों के पूरे इस्तेमाल की राज्यव्यापी योजना के फलस्वरूप भूमिगत जल के स्तर में 1 से 10 मीटर की बढ़ोतरी, सिंचित जमीन में बढ़ोतरी जैसे अन्य फायदे राज्य के किसानों को हुए

योजना को राजीव गांधी जल संचय योजना के तौर पर जारी रख रहे हैं। हमारा लक्ष्य इसको 40,000 से अधिक गांवों तक विस्तारित करने का है।” इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से 1,000 करोड़ रु. की जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है।

जयपुर जिले के टिकेल नारुकन गांव में एमजेएसए परियोजना में 250 तालाब खोदने का काम शुरू किया गया था जिससे करीब 200 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई मुमकिन हो

पाई है। इसकी वजह से भूजल स्तर में भी सुधार आया है। गांव में करीब 10 हेक्टेयर जमीन में खेती करने वाले महेंद्र चौधरी बताते हैं कि वह बंजर घोषित की जा चुकी जमीन पर अब गेहूं की फसल उगा पा रहे हैं।

कसेल गांव में, लोकेश चौधरी कहते हैं कि तालाब की वजह से अब वह मटर, आलू और गेहूं की फसल की पैदावार ले पा रहे हैं और इससे उनकी आय 50,000 रुपए से बढ़कर 5,00,000 रुपए सालाना हो गई है।

यहां से कोई 500 किमी दूर, राज्य के मेवाड़ में मारो का खेड़ा गांव में जलछाजन विकास परियोजना की वजह से यहां एक पिकनिक स्पॉट उभर आया है, जहां 36,000 पौधों और 40,000 घृतकुमारी (एलोवेरा) के पौधों ने एक पहाड़ी को हराभरा कर दिया है। भीलवाड़ा के परियोजना प्रबंधक एसएन उपाध्याय कहते हैं, “गांव में अभी 560 लोग रहते हैं, और जो 977 मवेशी पालते हैं। उन लोगों ने दूध उत्पादन में बढ़ोतरी देखी है क्योंकि पहाड़ी के आसपास वे चारा उगा पा रहे हैं। इसके लिए, वह महज 1,000 रुपए सालाना खर्च कर रहे हैं जबकि पहले उन्हें चारा खरीदने में 50,000 रुपए खर्च करना होता था।” ■

मेड़ और पेड़ का कमाल

पानी की भारी किल्लत झेल रहे बुंदेलखंड के एक गांव ने पानी बचाने के लिए खेतों में अपने खर्चे पर जलबंध बनाए और सूखाग्रस्त गांव के अभिशाप से निकलकर पानी से भरपूर गांव बन गया, जहां साल में कई फसलें उगती हैं

आशीष मिश्र



जल योद्धा

जखनी गांव में उमाशंकर पांडेय (सबसे आगे) गांववालों के साथ

चंद्रदीप कुमार

उत्तर प्रदेश में पानी का अभाव झेल रहे बुंदेलखंड के बांदा जिला मुख्यालय से प्रयागराज की ओर जाने वाले हाइवे पर 20 किलोमीटर दूर महुआ ब्लॉक का जखनी गांव एक दूसरी ही तस्वीर पेश करता है. यहां खेतों में सरसों, चना, गेहूं की फसल लहलहा रही है. खेतों में पानी है. गांव के सभी छह तालाब और 33 कुएं लबालब भरे हुए हैं. सूखे का प्रकोप झेलने वाले जखनी ने पानी प्रबंधन कर मिसाल बनाई है.

जखनी गांव में यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ. यहां के रहने वाले किसान 51 वर्षीय उमाशंकर पांडेय ने “खेत में मेड़, मेड़ पर पेड़” जैसी अनोखी योजना शुरू कर जखनी का कायाकल्प कर दिया. 500 परिवारों वाले जखनी में पानी की किल्लत के कारण से आधे से ज्यादा परिवार पलायन कर दूसरे जिलों में चले गए थे. इसी दौरान उमाशंकर पांडेय ने 25 अप्रैल, 2005 को दिल्ली के विज्ञान भवन में पानी पर आयोजित एक सेमिनार में हिस्सा लिया. इस सेमिनार में



बड़ी तस्वीर

- **समस्या** बुंदेलखंड के जखनी गांव में पानी की कमी से खेती बर्बाद हो गई थी, जिसके चलते परिवार वहां से पलायन करने पर मजबूर हो गए थे
- **समाधान** 2005 में ‘खेत में मेड़, मेड़ पर पेड़’ कार्यक्रम की शुरुआत हुई, ताकि बारिश में बेकार बह जाने वाले पानी को बचाया जा सके और खेती के काम में भी उसका उपयोग हो सके

मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद तत्कालीन राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने अपने संबोधन में सूखे का प्रकोप झेल रहे इलाकों के गांवों को “जलग्राम” के रूप में विकसित करने की बात कही.

पांडेय बताते हैं, “जलग्राम से तात्पर्य ऐसे गांव से था जहां पर प्राकृतिक ढंग से जल का संचयन किया जाए. विज्ञान भवन के सेमिनार के बाद मैंने जखनी को ‘जलग्राम’ के रूप

में विकसित करने का निर्णय लिया.” पांडेय ने दीन दयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान केंद्र, चित्रकूट, गुजरात के अहमदाबाद और सूरत जैसे जिलों का भ्रमण कर यहां के गांवों में जल संचयन के तौर-तरीकों का अध्ययन किया. इसके बाद पांडेय ने गांव के कुछ साधियों के साथ मिलकर एक पहले 50 बीघा खेत में मेड़ बनाकर बारिश के पानी को खेतों में रोका. इस तकनीक ने कुछ काम किया. खेतों में एक बीघा में पांच कुंतल गेहूं पैदा हुआ. अगले वर्ष 2006 में उमाशंकर पांडेय और गांव के किसानों ने खेत की मेड़ पर अरहर, नींबू, अमरूद के पेड़ भी लगाए.

पांडेय बताते हैं, “मेड़ पर पेड़ लगाने से न केवल मेड़ मजबूत हुई बल्कि एक भी बूंद बारिश के पानी को व्यर्थ नहीं बह जाने दिया. इससे खेत में काफी पानी मौजूद रहा और बासमती चावल की खेती भी संभव हुई.” वर्ष 2020 में जखनी गांव ने 25,000 कुंतल बासमती धान की रिकॉर्ड पैदावार की है. इससे किसानों ने 10 करोड़ रु. की कमाई की है. खेत में मेड़, मेड़ पर पेड़ योजना ने इलाके में भूगर्भ जल स्तर में भी इजाफा किया है.

उत्तर प्रदेश के जल शक्तिमंत्री डॉ. महेंद्र सिंह कहते हैं, “जखनी गांव की ‘खेत में मेड़, मेड़ पर पेड़’ योजना को यूपी सरकार प्रदेश में एक हजार से अधिक गांवों में लागू कर रही है. इससे न केवल किसान आत्मनिर्भर बनेंगे बल्कि पानी भी बचाएंगे.” ■

जल विशेषांक  टेक्नोलॉजी

बूंद-बूंद बहुमूल्य

भारत में दूर-दराज के कम बारिश के इलाकों से ज्यादा कौन समझेगा इसकी कीमत! अब यहां के किसानों को भी एहसास हो गया है कि टेक्नोलॉजी, अपना समुदाय और संसाधनों में साझेदारी ही उनकी बेहतरी का मंत्र

राज चेंगप्पा





गु

जरात के गांधीनगर जिले के खोरज गांव में रमेश भाई भीकाभाई मोरे के पांच हेक्टेयर के फार्म में अमरूद के पेड़ों की कतारों के बीच खरबूज की बेल और उन्हें चारों ओर से घेरे छोटे-छोटे प्लास्टिक पाइपों के गुच्छे देखे जा सकते हैं. भीकाभाई मोरे अपने गांव के उन पहले किसानों में शामिल हैं जिन्होंने कपास और गेहूं जैसी पारंपरिक फसलों के बजाय बागवानी फसलों को उगाने के लिए लघु सिंचाई प्रणालियों को आजमाया. इस नए प्रयास में,

भीकाभाई मोरे को गुजरात ग्रीन रिवॉल्यूशन कंपनी (जीजीआरसी) की मदद मिली, जो कृषि क्षेत्र में सक्रिय गुजरात सरकार की तीन इकाइयों और केंद्र सरकार का एक अनूठा संयुक्त उद्यम है.

2005 में गठित, जीजीआरसी उन किसानों के लिए वन-स्टॉप शॉप (एक जगह जहां जरूरत का सब कुछ उपलब्ध) है, जो उन्नत लघु सिंचाई तकनीकों को अपनाना चाहते हैं. ड्रिप सिंचाई प्रणाली की लागत आम तौर पर 50,000 रुपये से 1.5 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर आती है. यही वजह है कि ज्यादातर किसान इसमें निवेश से कतराते हैं. लेकिन जीजीआरसी न केवल किसानों को 70-90 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करता है, बल्कि इसके अधिकारी किसानों को तय मूल्य पर सर्वोत्तम लघु प्रणालियों का चयन करने में मदद भी करते हैं. वे किसान के पहली फसल लेने तक करीबी नजर रखते हैं और किसानों को विशेषज्ञों का परामर्श मिलता है. लघु सिंचाई के लिए पाइप जीजीआरसी के अधिकारी लगाते हैं, जिसमें स्प्रींकलर, ड्रिपर्स और रेन गन शामिल हैं और उनकी निगरानी तथा

बड़ी तस्वीर

- **समस्या** गुजरात में जल संकट से खेती करना मुश्किल हो रहा था
- **समाधान** गुजरात ग्रीन रिवॉल्यूशन कंपनी की पहल ने किसानों को माइक्रो सिंचाई पद्धति अपनाने में मदद की. इससे पानी की भी और मजदूरी लागत में भी 30-50 फीसद की बचत हुई; गुजरात में करीब 12 लाख किसान खेती में इस पद्धति को अपना चुके हैं

फौरन मदद के लिए जियो-फेंसिंग और टैगिंग का उपयोग किया जाता है. जीजीआरसी के सुपरिडेंटिंग इंजीनियर हार्दिक पंचोली कहते हैं, “हम किसानों को अपना ग्राहक और सब्सिडी की रकम को निवेश मानते हैं. हम वास्तव में किसानों की कामयाबी में हर संभव मदद करना चाहते हैं.”

एक एनजीओ के साथ मिलकर भारतीय प्रबंधन संस्थान (आइआईएम) अहमदाबाद के एक हालिया अध्ययन में पाया गया कि लघु सिंचाई से किसानों के लिए पानी और श्रम लागत दोनों में ही 35-50 प्रतिशत की बचत होती है. इसके अलावा, उर्वरक और बिजली की लागत में भी काफी बचत होती है, और फसल की पैदावार में पारंपरिक खेती की तुलना में 30 फीसदी तक की बढ़ोतरी होती है. अध्ययन में पाया गया कि लघु सिंचाई तकनीकों को अपनाकर किसान अपनी आमदनी को प्रति हेक्टेयर कम से कम 15,500 रुपये तक बढ़ाने में सक्षम हुए हैं.

राज्य के 12 लाख से अधिक किसान खेती के इस उन्नत तरीके को अपना चुके हैं. जीजीआरसी के अधिकारियों का दावा है कि उन्होंने ऐसे लगभग 60 प्रतिशत खेतों को कवर कर लिया है, जो लघु सिंचाई प्रणालियों को अपना सकते हैं, और उम्मीद है कि अगले पांच वर्षों में बाकी किसान भी इस तकनीक को अपना लेंगे. जीजीआरसी के अधिकारियों ने हाल ही में भीखाभाई मोरे के भतीजे, रंजीत सिंह हरिकृष्ण जाधव को भी इसे अपनाने के लिए राजी कर लिया है, जो जमीन के एक हिस्सेदार हैं. जाधव कहते हैं, “हमें भरोसा है कि हमने सही निवेश किया है और हमारी योजना अगले साल तक इसे पांच एकड़ और खेतों तक बढ़ाने की है.” ■

एक-एक बूंद

गुजरात के गांधीनगर जिले के खोरज गांव में भीकाभाई मोरे अपना माइक्रो सिंचाई नेटवर्क दिखाते हुए



सीधी धार

जल उपभोक्ता समिति
के सदस्य रोहिणी डैम
पर सिंचाई विभाग के
अधिकारियों के साथ

चंद्रदीप कुमार

धारा के साथ बढ़े आगे



बुंदेलखंड

किसानों और जल उपभोक्ताओं की निर्वाचित समिति ने सहभागिता वाले एक प्रोजेक्ट के तहत पक्का किया कि बुंदेलखंड के आखिरी खेतों को पानी मिले

आशीष मिश्र

बुंदेलखंड के ललितपुर जिले में मुख्यालय से करीब 80 किमी दक्षिण में महरौनी तहसील के चउका गांव के 60 वर्षीय मर्दन लाल पिछले साल कम बारिश होने से चिंतित हो गए थे. उनका गांव ललितपुर के रोहिणी डैम से निकलने वाली चउका माइनर के टेल पर पड़ता है. 1.21 करोड़ क्यूबिन मीटर पानी की क्षमता वाला भी पिछले साल कम बारिश के चलते इसका महज 34 फीसद हिस्सा ही भर पाया था. पानी कम होने से माइनर में सिर्फ

एक बार ही पानी रिलीज किया जा सकता था. ऐसे में टेल तक पानी पहुंचाना एक बड़ी चुनौती थी. समस्या के समाधान के लिए रोहिणी नहर प्रणाली के सहायक अभियंता नफीस अहमद ने नहर से जुड़ी छपरौली, तिसागनन, चउका और घरौली माइनर से जुड़ी जल उपभोक्ता समितियों की मदद ली.

छपरौली जल उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष हनुमंत सिंह तोमर कहते हैं, “समितियों ने किसानों से बात करके यह तय किया कि रोहिणी डैम से किस वक्त एक बार पानी डिस्चार्ज कराया जाए जिससे उसका अधिकतम फसल के लिए किया जा सके.”

पिछले साल नवंबर महीने में बारी-बारी से 15 दिन के लिए सभी चारों माइनर में पानी छोड़ा गया. जल उपभोक्ता समितियों के प्रयासों का नतीजा है कि मर्दन लाल के तीन एकड़ खेत में इस दफा 24 कुंतल मटर की पैदावार हुई, इसे 4,500 रु. प्रति कुंतल के हिसाब से बेचकर

उन्होंने एक लाख रु. से ज्यादा कमाए हैं.

मर्दन लाल की जगह चउका और गढ़ौली माइनर के कमांड एरिया में आने वाले 4,000 किसान परिवार जल उपभोक्ता समिति की कोशिशों से लाभान्वित हुए हैं. 2016 में विश्व बैंक के सहयोग से बुंदेलखंड में रोहिणी नहर प्रणाली का जीर्णोद्धार करने के लिए उत्तर प्रदेश वाटर सेक्टर रीस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई. इसमें करीब 10 करोड़ रु. की लागत से रोहिणी नहर प्रणाली की सभी कच्ची नहरों को पक्की नहर में बदलने की योजना बनी. यह काम 2018 में पूरा हुआ. इसी के साथ 2016 में सिंचाई विभाग ने बुंदेलखंड में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रोहिणी नहर प्रणाली में सहभागी सिंचाई प्रबंधन व्यवस्था लागू की. इसके तहत रोहिणी नहर प्रणाली से जुड़ी सभी माइनर में पहली बार आठ सदस्यीय जल उपभोक्ता समितियों का गठन किया गया. 2018 के बाद से सिंचाई प्रबंधन उन्हीं के हाथों में है. ■

बढ़ी तस्वीर

● **समस्या** रोहिणी बांध बन तो गया था 1984 में लेकिन इसकी छोटी नहरों में आखिर तक पानी कभी पहुंचा ही नहीं. करीब 4,000 किसानों के खेत में पानी नहीं पहुंच पा रहा था

● **समाधान** 2016 में बाकायदा मतदान से एक जल उपभोक्ता समिति का चुनाव हुआ. इसमें छोटी नहरों की कैचमेंट एरिया के किसानों ने वोट डाला

पानी को मिला रास्ता

ओडिशा में पानी पंचायतों ने इस कीमती संसाधन के बराबर बंटवारे का पुरस्ता इंतजाम किया और उपज बढ़ाई, सबसे अहम यह कि पानी के बंटवारे को लेकर होने वाले झगड़े कम हो गए

रोमिता दत्ता

क

टुक जिले के उसुमा गांव में 15 किलोमीटर दूर महानदी से आने वाली नहर के पानी को लेकर अक्सर झगड़े होते थे। कई बार तो कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति पैदा हो जाती थी। अब वह दौर गुजर चुका है। उसुमा और नौ अन्य गावों ने मिलकर 2000 में एक सफल 'पानी पंचायत' बनाई और पक्का किया कि उसुमा के 250 परिवारों को और उनकी 420 हेक्टेयर खेती योग्य भूमि को पानी का उचित हिस्सा मिले। ओडिशा की पानी पंचायतें किसानों के नेतृत्व में गठित निकाय हैं जो स्थानीय स्तर पर जल प्रबंधन और इसके न्यायोचित वितरण का दायित्व संभालती हैं।

आज 35,511 पानी पंचायतें हैं जिनकी देखरेख में खेतों में सिंचाई का पानी पहुंचाने का काम हो रहा है। उनका मुख्य काम यह पक्का करना है कि एक हेक्टेयर सिंचाई योग्य जमीन भी 'पानी से वंचित न रहे।' उसुमा पानी पंचायत के सचिव समीउल्ला खान कहते हैं, "जिस किसान को अपनी जमीन से प्यार है, वह स्वाभाविक रूप से दूसरों के खेतों में भी खुशहाली देखना चाहेगा। पानी के झगड़े में खून भी बहता रहा है पर पंचायत का गठन खेतों के लिए फायदेमंद रहा।"

दो दशक पहले शुरू हुई पानी पंचायत का विचार किसानों के अनुभव और जरूरतों से आया। शुरुआत में उन्हें 40-100 हेक्टेयर के न्यूनतम क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई, जिसे बाद में बढ़ाकर 500 हेक्टेयर तक किया गया। हर 10-40 हेक्टेयर के लिए एक जल स्रोत बनाया गया जिसका संचालन एक समिति (चाक) करती है। समिति पानी के वितरण, संचालन, रखरखाव

इंडिया टुडे



हरियाली के वकील
उसुमा में चल रही पानी पंचायत के सदस्यों की एक बैठक

बड़ी तस्वीर

- **समस्या** नहरों के पानी का समान वितरण न हो पाने से आए दिन कानून-व्यवस्था की समस्या खड़ी हो रही थी
- **समाधान** पानी के बराबर बंटवारे के अलावा स्थानीय स्तर पर नहरों के संचालन और उनकी देखरेख के लिए किसानों और दूसरे नागरिकों के साथ पानी पंचायतों का गठन किया गया

और अपने क्षेत्र में चैनलों के भीतर गाद की सफाई पक्की कराती है।

जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर डी.के. सामल कहते हैं, "किसानों को सशक्त बनाकर हम झगड़े कम करने और यह पक्का करने में सफल रहे कि एक भी ब्लॉक पानी से वंचित न रहे। पानी के दुरुपयोग के लिए दंड और जुर्माने के प्रावधान हैं।" अब किसान अपने लिए सही फसलों का चुनाव कर सकें इसके लिए चाक के अधिकार क्षेत्र को कम करने की आवश्यकता महसूस हुई है। धान में बहुत अधिक पानी लगता है, जबकि मूंगफली, तिलहन और दालों की खेती न्यूनतम जल के साथ की जा सकती है। सामल कहते हैं, "हम सभी किसानों को धान की ही खेती में झोंकने की बजाए अगर अनेक तरह की फसलें उगाने को प्रोत्साहित कर पाएं तो बड़ी मात्रा में पानी बचाने में सक्षम होंगे।"

खैर, अब तो कमान एरिया डेवलपमेंट के चीफ इंजीनियर राजेंद्र बेसरा कहते हैं, "सूखाग्रस्त कालाहांडी में दो फसलों की खेती होती है। पैदावार में औसतन 15 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। यह उस क्षेत्र की 267 पानी पंचायतों की वजह से संभव हुआ है।" ■



35,511

कुल पानी पंचायतें सक्रिय हैं ओडिशा में

रसीली बूंदों का वादा

सतह पर बनाए गए कृत्रिम तालाब, सोखता गड्ढे, चेक डैम और सामुदायिक तालाब, साथ में माइक्रो सिंचाई तकनीक ने सूखे के आदी इस अंचल में खेती को एक नई उम्मीद दी है

अरविंद गौड़ा

हेमंत मिश्र



अनंतपुरम

आंध्र प्रदेश

तीसरी कक्षा में पढ़ाई छोड़ देनेवाले एम. शिवशंकर रेड्डी अपने बचपन में बोरों पर सोया करते थे. आज

49 वर्षीय यह शख्स आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम जिले के प्रसन्नयापल्ली गांव के अपने तीन बड़े भूखंडों पर अनार, खरबूजे, अंगूर और सब्जियां उगाकर 3-4 लाख रु. प्रति एकड़ कमाता है. वे कहते हैं, “हमने तीनों भूखंडों पर 10 तालाब बनवाए और बूंद सिंचाई का तरीका अपनाया. इनमें जल संग्रहण क्षमता 10-30 लाख लीटर तक की है. इन तालाबों से भूजल स्तर रिचार्ज होता रहता है.” उनकी जमीन में 25 बोरवेल हैं और हर जगह अब 150 से 200 फुट पर पानी है. पड़ोस के गांव वेंकटरेड्डीपल्ली में 70 कृत्रिम तालाब, 12 चेकडैम और दो सोखता तालाब हैं. ये सभी पिछले छह साल में तैयार हुए हैं और इसमें सरकार ने उनकी मदद की है. इस गांव के 400 परिवारों ने जल उपभोक्ता समूह बनाए हैं ताकि एक-दूसरे की मदद कर सकें. बरसात में नजदीकी पेन्ना नदी से पानी लाकर कृत्रिम तालाबों में भंडारित किया जाता है, जिससे भूजल रिचार्ज होता है. बारह करोड़ लीटर वाला तालाब सामुदायिक

बड़ी तस्वीर

- **समस्या** सालोसाल सूखे का सामना करते आ रहे जिले में जलस्तर बेहद नीचे चला गया था. इससे पानी मांगने वाली फसलें लेना तो नामुमकिन ही हो गया था
- **समाधान** प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के धन का प्रयोग माइक्रो सिंचाई परियोजनाओं के लिए किया गया; 51,825 जलसंग्रह ढांचों से सिंचाई क्षमता 15,783 हेक्टेयर बढ़ गई, तालाब खुदवाए गए और जल उपभोक्ता संघों को फिर से खड़ा किया गया, कुछ ऐप तैयार किए गए

“अनंतपुरम में फलों की खेती से यहां की कृषि में सकल मूल्य में वृद्धि के नजरिए से देखें तो 11,000 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है. हम **58 लाख मी. टन फल सालाना** पैदा कर रहे हैं”

बोया सूर्या सुब्बारायुडू

प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एपीएमआइपी, अनंतपुरम

मेहनत का फल

एम. शिवशंकर रेड्डी अनंतपुरम जिले के परसन्नयापल्ली गांव में अंगूरों के अपने बाग के बीच

तालाब के तौर पर इस्तेमाल में लाया जाता है और भूजल रिचार्ज होने से इसका फायदा इस इलाके के दूसरे किसान भी उठाते हैं. प्रधानमंत्री के किसान सिंचाई योजना के ‘पर ड्रॉप, मोर क्रॉप’ हिस्से के रूप में अनंतपुरम जिले में 51,825 जल संचयन ढांचे बनाए गए हैं और इससे इसकी सिंचाई क्षमता 15,783 हेक्टेयर बढ़ गई है. यहां एक जिला सिंचाई योजना बनाकर, निष्क्रिय जल उपभोक्ता संगठनों को फिर सक्रिय किया गया, खेत के तालाबों की खुदाई हुई, सूखे मौसम में किसानों को नजदीकी जल स्रोत के बारे में मार्गदर्शन के लिए रिसोर्स मैप और मोबाइल ऐप डिजाइन किए गए. इसके साथ ही, किसानों को सूक्ष्म सिंचाई तरीकों, मसलन बूंद और फव्वारा सिंचाई अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया. आंध्र प्रदेश सूक्ष्म सिंचाई परियोजना (एपीएमआइपी) ने जिले में हॉर्टीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए अब तक 1,500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं. अनंतपुरम में इसके निदेशक बोया सूर्या सुब्बारायुडू कहते हैं, “जिले में हॉर्टीकल्चर के जरिए कृषि में कुल मूल्य संवर्धन करीबन 11,000 करोड़ रुपए का है.”



पलट दी किस्मत

तेलंगाना ने बेकार पड़ी सिंचाई की छोटी-छोटी नहरों और दूसरे स्रोतों को स्थानीय समुदायों की मदद से पुनर्जीवित किया और इस तरह से राज्य में खेती-किसानी में नए सिरे से जान डाल दी

अमरनाथ के. मेनन



हरित क्रांति

तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के शाबाद गांव में एन. पुरुषोत्तम



आदि.टी

अ

पने खेतों में सिंचाई के लिए बराबर पानी मिलने के फायदे पर 49 वर्षीय एन. पुरुषोत्तम कहते हैं, “यह मौका तो भगवान का दिया हुआ है.” 2017 तक तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में दो एकड़ के उनके खेत में इतना ही पानी पहुंच पाता था जिससे वह साल में धान की महज एक ही फसल ले पाते थे. लेकिन जब से गाद हटाकर और फीडर नहरों को दुरुस्त करके शाबाद गांव में पहलवान तालाब को पुनर्जीवित किया गया, पुरुषोत्तम जैसे

किसानों ने साल के आधे वक्त सब्जियां भी उगानी शुरू कर दी हैं. वे कहते हैं, “पहले जब बारिश होती थी तभी मैं सब्जी उगा पाता था. लेकिन बराबर पानी मिलने से ऐसी पत्तेदार सब्जियों को हम लगातार उगाते हैं, जिसकी मांग अधिक है.” 2015 से, मिशन काकतिया ने कुल 46,531 जलाशयों या तालाबों में 27,625 को स्थानीय समुदायों की मदद से पुनर्जीवित कर दिया है और इससे सूबे के 11,000 गांवों और उसके खेतों में पानी पहुंचाया जा सका है. हालांकि, बाकी बचे जलाशयों को पुनर्जीवित करने की कोई योजना नहीं है क्योंकि या तो उनका इस्तेमाल बंद हो चुका है या फिर उनसे 20 एकड़ से कम खेतों की सिंचाई होती है.

बड़ी तस्वीर

- **समस्या** तेलंगाना में छोटी झीलें, तालाबों जैसे सिंचाई के 46,531 स्रोतों की क्षमता का सिर्फ 37 फीसदी उपयोग हो पा रहा था
- **समाधान** मिशन काकतिया के तहत स्थानीय समुदायों की मदद लेकर उनमें 27,625 झीलें, तालाबों की गाद साफ करवाई गई, तटबंधों की मरम्मत कराई गई और फीडर चैनल फिर से बहाल किए गए

सभी दुरुस्त किए गए तालाबों की जियोमेट्रिंग की गई है और इस काम में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हैदराबाद की मदद ली गई है, ताकि डिजिटल टोपोग्राफी, सैटेलाइट तस्वीरों और अन्य उपकरणों की मदद से इनकी लगातार निगरानी की जा सके.

सिद्धिपेट जिले के पामुलपल्ली गांव के 52 वर्षीय कमला इलैया कहते हैं, “कपास या ज्वार जैसी फसलों के बदले मैं पांच एकड़ में साल में दो बार धान उगाता हूं और बीच की अवधि में उसमें सब्जियां लगा लेता हूं.” इलैया का दावा है कि 2010 में जिस जमीन की कीमत 8 लाख रुपए प्रति एकड़ थी, वह अब बढ़कर 1.5

करोड़ रुपए हो गई है.

अब तक तेलंगाना सरकार ने मिशन काकतिया पर 9,110 करोड़ रुपए खर्च किए हैं. इस परियोजना का नाम काकतीय वंश (1163-1323 ईस्वी) पर पड़ा है, जिनके शासकों ने इस इलाके के गांवों में तालाबों और सिंचाई के साधनों का विस्तृत जाल बिछा दिया था. तेलंगाना के जल संसाधन मंत्रालय के प्रमुख सचिव डॉ. रजत कुमार कहते हैं, “मिशन काकतिया के तहत पूरे राज्य में भूजल स्तर औसतन 10 मीटर बढ़ गया है.” राज्य की इस कोशिश से प्रभावित होकर 135 अप्रवासी भारतीयों ने मिशन काकतीय के मद में 18.5 करोड़ रुपए का दान दिया है.

नीति आयोग की 2019 समेकित जल प्रबंधन सूचकांक रिपोर्ट ने मिशन काकतीय को लघु सिंचाई ढांचों को पुनर्जीवित करने और छोटे तथा मझोले किसानों के लिए पानी उपलब्ध करने की दिशा में शानदार मिसाल बताया है. अब तक, 8.75 हजार मिलियन क्यूबिक फुट जल संचय क्षमता हासिल कर ली गई है. सूबे में सिंचित क्षेत्र में 45.6 फीसद की बढ़ोतरी हुई है. राज्य के सिंचाई महकमे का काम भी संभालने वाले वित्त मंत्री टी. हरीश राव ने कहा, “मिशन काकतीय देश के सबसे नए राज्य तेलंगाना में जलापूर्ति को दुरुस्त करने और कृषि में परिवर्तन की यात्रा है.” ■

कैसे हो रही भरपाई

भारत के विभिन्न राज्य अपने भूमि जल के संकट से निबटने और सालभर पेयजल की आपूर्ति तथा सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए क्या कर रहे हैं

फोटो: यासिर इकबाल



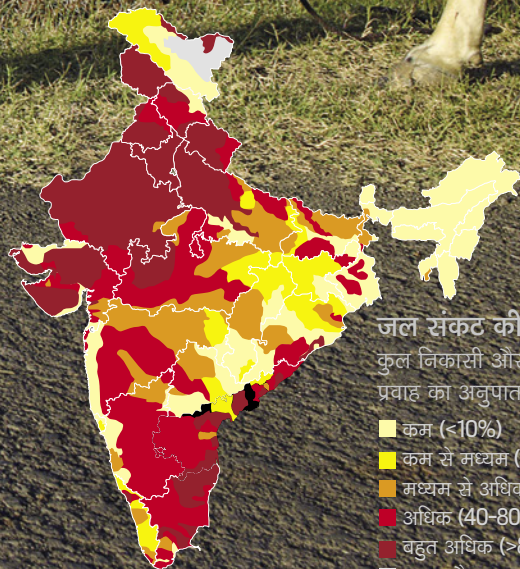

खेतों की ओर
देवास के किसान
तालाब से खेतों तक
पानी पहुंचाने वाले
पाइप बैलगाड़ी पर
लादते हुए



सूखी धरती

भारत अपने इतिहास के सबसे खराब जल संकट के दौर से गुजर रहा है. उसके भूमि जल संसाधन—जो हमारी जल आपूर्ति का 40 फीसद है—का इतना दोहन किया जा रहा है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती

स्रोत: नीति आयोग कम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, जून 2018



जल संकट की जड़
कुल निकासी और कुल
प्रवाह का अनुपात

- कम (<10%)
- कम से मध्यम (10-20%)
- मध्यम से अधिक (20-40%)
- अधिक (40-80%)
- बहुत अधिक (>80%)
- सूखा और जल का प्रयोग कम



फिल्लत नहीं

देवास का किसान अपने तालाब से खेत की सिंचाई करता हुआ



यासिर इकबाल

माटी में था समाधान

देवास के खेतिहर तालाब जल संकट से निबटने के मामले में यहां की सबसे बड़ी ताकत बन गए

राहुल नरोन्हा

मालव माटी गहन गंभीर, डग डग रोटी, पग पग नीर. सदियों तक इन पंक्तियों ने पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा इलाके की संपन्नता का गुणगान किया है. पर मालवा इलाके के हृदयस्थल में बसा देवास इसका अपवाद था. यह गहरे जलसंकट से जूझता रहा है. 2000 के दशक की शुरुआत में देवास शहर में ट्रेनों के जरिए पानी पहुंचाया जाता था. किसान सालभर में एक ही फसल लेने को मजबूर हो गए. स्थानीय अर्थव्यवस्था ढहने के कगार पर आ गई थी.

ऐसा नहीं था कि देवास में बारिश कम होती हो—यहां औसत बरसात 1,066 मिमी होती है—लेकिन 1990 के दशक में अत्यधिक दोहन की वजह से भूजल स्तर 600 फुट तक नीचे चला गया. उस गहराई में पानी में ऐसे खनिज घुल जाते हैं जो फसलों को चौपट कर सकते हैं. देवास में अधिकतर पानी नदियों के जरिए बह जाता है. इसको समझाते हुए कृषि विभाग में सहायक मृदा संरक्षण

बड़ी तस्वीर

- **समस्या** पीने के पानी और सिंचाई जल का भारी संकट था
- **समाधान** खेतों में ही खोदे गए तालाब, जिन्होंने वर्षाजल संचयन करके भूजल को रीचार्ज किया और सिंचाई के अलावा पीने का पानी की समस्या का भी समाधान दिया



10,000

से ज्यादा खेतिहर तालाब हैं आज देवास में. अकेले धतूरीया और गोरवा गांवों में तो 200-200 से ज्यादा ऐसे तालाब हैं

अधिकारी डॉ. मोहम्मद अब्बास कहते हैं, “देवास की मिट्टी को मध्यम काली कपासी मिट्टी के वर्ग में रखा जाता है जिसमें रिसाव 0.02 फीसद होता है जो रेतीली दोमट में 3-5 फीसद होता है.” यही नहीं, चंबल और काली सिंध जैसी बड़ी बड़ी नदियां देवास के पास से ही निकलती हैं और नर्मदा और क्षिप्रा यहां से बहती हैं. इसके बावजूद इसके नहरों और बांधों का लाभ इस जिले को नहीं मिलता था. ऐसे में देवास को मदद की जरूरत थी.

2006 में, जिलास्तरीय समन्वय समिति की बैठक में देवास के हरनवादा गांव के किसान रघुनाथ सिंह तोमर ने तब के जिलाधिकारी और आज के मुख्य सचिव उमाकांत उमराव से कहा कि उन्होंने एक बीघे में एक तालाब खोदी है जो बारिश के पानी से भर गई है और इससे 15 एकड़ खेत को सींचा जा सकता है. उमराव कहते हैं, “इससे मुझे ख्याल आया कि हमारे जल संकट का समाधान बांध बनाने में नहीं है, बल्कि वर्षाजल संचयन करके उसे भूजल रीचार्ज करने, सिंचाई और पेयजल के लिए इस्तेमाल में है. देवास की बारीक मिट्टी जो पानी को रिसने नहीं देती, एक छिपा हुआ वरदान साबित हुई.”

भगीरथ कृषक अभियान नाम से योजना बनी. इसके तहत देवास में आज 10,000 तालाब हैं. अब किसान यहां संतरे के बाग लगा रहे हैं. यहां बुआई का रकबा 2000 के दशक के मध्य के 1 लाख हेक्टेयर से बढ़कर आज 4 लाख हेक्टेयर हो चुका है. ■

हासिल हुई साझी संपन्नता

एक डीसिल्टिंग स्कीम के जरिए भूजलस्तर में सुधार लाया गया. इसके साथ ही रबी की बुवाई और टिकाऊ खेती में सुधार हुआ है. डीसिल्टिंग स्कीम वह होती है जिसके तहत कोई भी राज्य गाद पर अपनी रॉयल्टी माफ कर देता है और स्थानीय जल निकायों से गाद को हटाने में गैर-सरकारी संगठनों का समर्थन करता है

किरण डी. तारे

म



महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में दताला गांव के रहने वाले 36 साल के किसान अमोल पाटील 5 एकड़ में उगने वाली अपनी मौंबी की फसल को लेकर खासे उत्साहित हैं, जबकि इस फसल को पानी की बहुत जरूर होती है. वे बताते हैं, “राज्य सरकार की गालमुक्त धरन गालयुक्त शिविर (गादमुक्त बांध, गादयुक्त खेत) योजना के चलते इस इलाके में पानी की आपूर्ति में काफी सुधार हुआ जिसकी वजह से वे इसे उगाने में सक्षम हो पाए हैं.”

राज्य के मृदा और जल संरक्षण विभाग के इस कार्यक्रम को मार्च 2018 में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी सरकार की जलयुक्त शिवर अभियान (जेएसए) सिंचाई योजना के हिस्से के रूप में शुरू किया था. इसके तहत गैर सरकारी संगठनों को छोटे बांधों और दूसरे छोटे जल निकायों में एकत्र हो गई गाद की खुदाई करने

की अनुमति दी जाती है, साथ ही सरकार रॉयल्टी माफ कर देती है.

राज्य के सबसे बड़े गैर-सरकारी संगठनों में से एक भारतीय जैन संघटना (बीजेएस) ने पांच जिलों में गाद की खुदाई के लिए सरकार के साथ समझौता किया था. इस संगठन ने खुदाई करने वाले उपलब्ध करवाए, जबकि सरकार ने ईंधन और दूसरे खर्चों का भुगतान किया. किसानों को मुफ्त में गाद का उपयोग करने की अनुमति दे दी गई, उन्हें केवल इसे अपने खेतों तक ले जाने के लिए भाड़ा खर्च करना था. कुल मिलाकर सभी के लिए यह एक जीत थी—जैसे कि सरकार ने अपने मैनेजमेंट के तहत बांधों और जल निकायों को बहुत कम पैसों में गाद हटाकर साफ कर दिया, वहीं किसानों को अपने खेतों के लिए बेहद उपजाऊ मिट्टी मिल गई और कई जिलों में भूमिजल के स्तर और



3.2 करोड़ घन मीटर

जलधारण क्षमता बढ़ाई गई उन पांच जिलों के छोटे ताल-तलैयाँ की, जिनमें गाद हटाने की यह योजना लागू की गई



मंदार देवघर

हरिक विजेता
बुलढाणा जिले के
मल्कापुर में खेत में
तालाब की खुदाई

बड़ी तस्वीर

- **समस्या** पानी की भारी कमी थी और भूजल काफी नीचे चला गया था
- **समाधान** छोटे बांधों और तालाबों से गाद हटाकर उनकी जल संग्रहण की क्षमता बढ़ाई गई

वाटर टेबल हाइट्स में उल्लेखनीय सुधार देखा गया. नतीजा यह हुआ कि किसानों ने गन्ना, अमरूद और अंगूर की खेती शुरू कर दी है, जो कि पहले उनके लिए संभव नहीं था. खेतों में पैदावार की क्षमता तो बढ़ी ही, खेतों की कीमत में भी दस गुने से ज्यादा की वृद्धि देखी गई है.

विडंबना देखिए कि यह परिणाम एक नितांत उपयोगी राजनैतिक निर्णय के बाद ही मिल पाया था, पर अब किसी भी प्रकार की राजनीति इस सारे किए-धरे पर पानी फेर सकती है. सितंबर 2020 में मौजूदा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जेएसए की फंडिंग रोक दी और दिए गए फंड के कथित ‘अनुचित उपयोग’ की जांच के आदेश दे दिए. हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने फंडिंग रोके जाने का जबरदस्त विरोध किया है. इस योजना का मौजूदा चरण 31 मार्च को समाप्त हो जाएगा. इस योजना को महाराष्ट्र के 36 जिलों में से केवल पांच में लागू किया गया था. ■



जीवन पर संकट

फजिल्का जिले में घरेलू इस्तेमाल के लिए हैंडपंप से पानी निकालती महिलाएं

काला पानी

पानी पर अत्यधिक आश्रित रहने वाली फसलों और उर्वरकों के भारी इस्तेमाल ने मिलकर पंजाब के जल संकट को बढ़ाया

अनिलेश एस. महाजन



इसके अलावा प्राकृतिक रूप से होने वाले जल के रिचार्ज के मुकाबले भूजल निकालने का प्रतिशत 165 फीसद है. सबसे बड़ा दुश्मन धान की फसल है जो राज्य के 22 जिलों में उगाई जाती है. लुधियाना स्थित पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू) के एक अध्ययन से पता चलता है कि प्रति किलोग्राम धान को मोटे तौर पर 5,000 लीटर पानी की जरूरत होती है. पीएयू का अध्ययन यह भी बताता है कि पंजाब में प्रति हेक्टेयर 190.1 किलो उर्वरक का इस्तेमाल होता है जो राष्ट्रीय औसत 88.2 किलो के मुकाबले बहुत ज्यादा है. धान के अलावा, गेहूं (रबी की फसल) को उर्वरकों की भारी खुराक की जरूरत होती है. उर्वरकों के भारी इस्तेमाल के कारण भूजल को बहुत भारी नुकसान हो रहा है.

पंजाब में जल संसाधन मंत्रालय के प्रधान सचिव सर्वजीत सिंह कहते हैं, “खेती की आदतें रातोंरात नहीं बदलती हैं. किसानों की धान की खेती छोड़कर अन्य फसलों की खेती के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए नीतिगत स्तर के साथ-साथ जमीनी स्तर पर भी काम किया जा रहा है.” सर्वजीत सिंह कहते हैं कि पंजाब इज्राएल की राष्ट्रीय जल कंपनी मेकोरोट के साथ मिलकर जल संरक्षण और प्रबंधन का मास्टर प्लान तैयार करने की दिशा में काम कर रहा है. इज्राएल अपने यहां बेकार हो जाने वाले 80 प्रतिशत जल का दोबारा इस्तेमाल करता है. पंजाब में केवल 10 प्रतिशत से भी कम जल को रिसाइकिल किया जाता है, उसे यह लक्ष्य हासिल करने के लिए अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना होगा. उम्मीद की जाती है कि मेकोरोट राज्य में जल के इस्तेमाल के मौजूदा तरीकों का अध्ययन करेगी और उसके बाद जल के संरक्षण और रिसाइकिल को लेकर कोई समुचित समाधान मुहैया कराएगी. ■

इस समय पंजाब तीन बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है: 1) प्रदूषित नहरें, 2) तेजी से घटता भूमिगत जलस्तर और 3) प्रदूषित भूमिगत जल. ये तीनों ही समस्याएं एक-दूसरे से जुड़ी हैं लेकिन पंजाब में ऑर्गेनिक खेती को प्रोत्साहन देने वाले एक गैर-सरकारी संगठन ‘खेती विरासत मंच’ के निदेशक उमेश दत्त का कहना है कि एक तरफ जहां सतह पर जल एक बड़ी चुनौती है, वहीं भूमिगत जल के मामले जो हो रहा है, वह इससे भी कहीं बड़ी समस्या है. राज्य में भूजल का स्तर हर साल 49 सेंटीमीटर की दर से नीचे जा रहा है.

बड़ी तस्वीर

● **समस्या** प्रदूषित भूमिगत और भूमिगत का घटता स्तर

● **समाधान** किसानों को पानी पर बेहद आश्रित धान की फसल छोड़ने और अधिक उर्वरकों का इस्तेमाल वाली गेहूं की फसल का विकल्प आजमाने के लिए प्रोत्साहित करना



आंध्र प्रदेश: वाइएसआर कडपा में उपसतह बांध



80%

जमीन वाइएसआर कडपा की ऐसी है, जिसमें भूमिजल बहुत जल्दी रिस जाता है



नई उम्मीद

पापागि नदी पर बने पुल पर चिरुतानी प्रताप

ए. शिवा

बढ़ गया जलस्तर

सूखाग्रस्त वाइएसआर कडपा जिले में नई तरह के बांध से जल स्तर बढ़ा और सतत सिंचाई में मदद मिली

अमरनाथ के. मेनन

वा इएसआर कडपा जिले में पापागि नदी के पुल पर खड़े चिरुतानी प्रताप नीचे सूखे पड़े नदी तल पर झिलमिलाती छोटी-छोटी धाराओं की तरफ इशारा करते हैं। वे कहते हैं, “हमें ये बस बीते दो सालों में ही दिखाई देने लगी हैं। आम तौर पर यह नदी हर साल बारिश के मौसम में महज चार महीने ही एक धारा में बहती है.” आंध्र प्रदेश के जल संसाधन विभाग से जुड़े 50 वर्षीय पर्यावरण इंजीनियर नदी के अनूठे कायापलट की बात कर रहे हैं.

यह बदलाव पापागि नदी पर उपसतह या सतह से नीचे बने बांधों (एसएसडी) की बदौलत आ सका है. पापागि कई महीने लगभग सूखी पड़ी रहती है. धाराओं या घाटियों पर बनाए गए एसएसडी का मकसद भूमिगत जलाशयों का निर्माण करना



बढ़ी तस्वीर

- **समस्या** बहुत कम बारिश तथा ऐसी मिट्टी जिसमें वर्षाजल आसानी से नीचे नहीं जा पाता
- **समाधान** इलाके में सूखे के दिनों में भूजल स्तर बनाए रखने के लिए उपसतह या सबसर्फेस बांध (एसएसडी) का निर्माण. साथ ही, एसएसडी के निर्माण में सामान्य बांध का दसवां हिस्सा खर्च होता है

और भूमिगत जल को फिर से भरना है. इनका निर्माण पाइलिंग टेक्नोलॉजी से किया गया है, जिसमें टेढ़े-मेढ़े आकार की स्टील की चादरें रेत में 18 मीटर की गहराई तक उतारकर एक किस्म की दीवार बनाई गई है और भूमिगत जल का स्तर बढ़ाने के लिए नीचे पानी को घेरकर रखा गया है. कडपा में इन बांधों का निर्माण नदी के 34 किमी लंबे फैलाव की छह ढलानों पर मई 2017 और मार्च 2018 के बीच किया गया. 2019 आते-आते भूमिगत जल का स्तर इतना बढ़ गया कि यह गंडी में 5.19 मीटर से लेकर राजुपालम में 14.64 मीटर के बीच आ गया है. नतीजतन, खरीफ के सीजन के दौरान धान की फसल स्थिर हो चुकी है और रबी के सीजन में एक और फसल, ज्यादातर सूरजमुखी, उगाई जा रही है.

मरुस्थलीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने एसएसडी सरीखे भूमिगत जल बांधों का सुझाव दिया था और इन्हें सूखे या अर्ध-सूखे इलाकों में पानी के किफायती भंडार के लिए उपयुक्त टेक्नोलॉजी बताया था.

बजट में इस काम के लिए कोई धनराशि नहीं होने की दशा में वाइएसआर कडपा के जिला कलेक्टर सी. हरि किरण ने एसएसडी के निर्माण के लिए 26 करोड़ रुपए जुटाने की खातिर उस खनिज उपकर का सहारा लिया जो जिले में इकट्ठा गया था और विवेकाधीन इस्तेमाल के लिए मौजूद था. वाइएसआर कडपा में एसएसडी ने दो साल के भीतर खेती-किसानी का चेहरा बदल दिया है और करीब 8,000 एकड़ इलाके को फायदा पहुंचाया है. ■



8,000

एकड़ जमीन रिचार्ज हुआ वाइएसआर जिले में एसएसडी बनने दो साल के भीतर

पवित्र गंगा की अवरुद्ध जल धारा

गंगा की सफाई की कोशिशें पहले भी कई बार हुई हैं. लेकिन कभी भी इस तरह मिशन का स्वरूप उसे नहीं मिला, और अब प्रधानमंत्री खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं

राज चेंगप्पा

भा

रत में कोई भी दूसरी नदी मन में अगाध श्रद्धा नहीं पैदा कर पाती या उतनी ज्यादा धार्मिक भावनाओं और पर्व-त्योहारों के केंद्र नहीं है जितनी पराक्रमी गंगा. यह नदी अपना 2,525 किमी का सफर गंगोत्री के मुहाने से शुरू करती है और पश्चिम बंगाल में गंगासागर में जा गिरती है. इस सफर में यह देश के 26 फीसद भूभाग से गुजरती है और 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल भूभाग पर अपनी धार डालती है. यह पांच राज्यों से होकर बहती है और इसके बेसिन में छह दूसरे राज्य आते हैं. गंगा और उसकी सहायक नदियां देश के जल संसाधनों में 28 फीसद बड़ा योगदान देती हैं. देश में 43 फीसद या 50 करोड़ लोग इस पर निर्भर हैं और गंगा की उपजाऊ भूमि खाद्यान्न का कटोरा मानी जाती है.

नदी के मुख्य किनारों पर 97 बड़े शहरी केंद्र और 4,457 गांव बसे हैं और यही

मौन प्रार्थना

नरेंद्र मोदी मई 2014 में वाराणसी
से अपना नामांकन पर्चा दाखिल
करने के पहले गंगा की शरण में



पेशानी की जड़ हैं. दशकों के दौरान इन गांव-शहरों ने अपना गंदा पानी और उद्योगों से निकला सारा मैल अंधाधुंध ढंग से नदी में प्रवाहित किया है. नतीजतन इसका पानी अत्यंत प्रदूषित हो गया और कई पट्टियों में तो जलीय जीवन को ही लील गया.

जब भी स्वच्छ गंगा शब्द हमारी तरफ उछाला जाता है, मन में खीझ और चिढ़ पैदा होती है. इस बेहद प्रदूषित नदी को साफ-सुथरा करने की पहली कोशिश 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शुरू की थी. लेकिन जो वादा किया गया था और जो वाकई किया जा रहा था, उसमें भारी फर्क सामने आया. विभिन्न चरणों वाले इस मिशन को संभालने वाले अधिकारियों ने कहा कि मुख्य खोट यह था कि इसे आधे-अधूरे मन से और टुकड़ों में अंजाम दिया गया. केंद्र, राज्यों और स्थानीय निकायों के बीच कोई तालमेल नहीं था. 1985 और 2015 के बीच महज 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए और वे भी मुख्य रूप से गंदे पानी के लिए जलशोधन संयंत्रों की स्थापना पर खर्च किए गए. परियोजना के अमल में देरी ढर्रा बन गई. इसके अलावा बेसिन स्तर के मसलों को लेकर स्पष्टता का अभाव और टेक्नोलॉजी के नाकाफी हस्तक्षेप तो थे ही.

जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, तो उन्होंने नजरिए और तरीके में आमूलचूल बदलाव कर दिया. हिंदू इस नदी की पूजा करते हैं, लिहाजा गंगा की साफ-सफाई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के चुनावी वादों में शामिल थी. मोदी ने यह पक्का किया कि यह कार्यक्रम पिछली कोशिशों से ज्यादा कामयाब हो. नमामि गंगे कार्यक्रम (एनजीपी) का ऐलान करते हुए उन्होंने इसकी देख-रेख करने वाले प्राधिकरण के तौर पर राष्ट्रीय गंगा परिषद का गठन किया, जिसके प्रमुख वे स्वयं बने. क्रियान्वयन एजेंसी के तौर पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) बनाया गया. मोदी सरकार ने अधिसूचना जारी की कि एनएमसीजी को प्राधिकरण माना जाएगा और उसे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत संवैधानिक अधिकार हासिल होंगे. इस तरह इसे अफसरशाही से स्वायत्त और संबंधित राज्य सरकारों के साथ तालमेल बिठाकर मिशन के कामों को पूरा करने के लिए नियामक शक्तियां दे दी गईं. फिर प्रधानमंत्री ने पांच साल के लिए

20,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी, जो बीते 35 साल में प्रतिबद्ध धनराशि से पांच गुना थी. उन्होंने प्रमुख परियोजनाओं में सौ फीसद केंद्र का धन लगाना पक्का किया, ताकि राज्य धन देने की अपनी अनिच्छा से उबर सकें.

एनएमसीजी ने समग्र ढंग से काम को अंजाम देना शुरू किया. उसने अपने मिशन को चार बड़े हिस्सों में बांटा—निर्मल गंगा (प्रदूषण की साफ-सफाई), अविरल गंगा (पारिस्थितिकी और प्रवाह पक्का करना), जन गंगा (सफाई की कोशिशों में जन भागीदारी) और ज्ञान गंगा (नदी के प्रबंधन और नीतियों पर अनुसंधान को बढ़ावा देना). अतीत की कोशिशों के उलट इस बार जोर नदी के किनारे

“हमने काम पर पूरा फोकस किया और आक्रामक ढंग से मिशन को अंजाम देना शुरू किया. अब इसके नतीजे दिखने लगे हैं”

राजीव रंजन मिश्र

महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन



बड़ी तस्वीर

● **समस्या** गंगा के किनारे बसे 97 प्रमुख शहर और 4,457 गांवों का जल-मल और उद्योगों के मलबे ने उसे दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में एक बना दिया

● **समाधान** भाजपा सरकार ने पांच साल के लिए 20,000 करोड़ रुपए के बजट से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का गठन किया. फोकस समूचे मूल रूप का कार्याकल्प करना होगा, न कि सिर्फ किनारे बसे शहरों पर

बसे कुछेक शहरों की बजाए नदी के समूचे मूल रूप का कार्याकल्प करना था. नदी बेसिन की जलीय और तटीय जैवविविधता में नई जान फूंकने और उनका संरक्षण करने पर भी जोर दिया गया. जिस एक और बात से बहुत मदद मिली, वह यह थी कि विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी मिलने से पहले ही सात आइआइएम (भारतीय प्रबंधन संस्थानों) ने नदी बेसिन के प्रबंधन की विस्तृत योजना तैयार की और बहुत सारा मैदानी काम भी पूरा किया, जिसमें नदी के किनारे बसे बड़े शहरी और ग्रामीण केंद्रों से छोड़े जाने वाले गंदे पानी की मात्रा का अनुमान लगाना भी शामिल था. यह सब इसलिए किया गया ताकि योजनाओं पर अमल वैज्ञानिक तरीके से और समयबद्ध आधार पर करना पक्का किया जा सके.

एनएमसीजी के डायरेक्टर जनरल राजीव रंजन मिश्र कहते हैं कि पहले सामने आ चुकी समस्याओं से उबरने के लिए कई बड़े नीतिगत निर्णय लिए गए. इनमें सीवरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए हाइब्रिड एन्यूइटी मॉडल



142

परियोजनाएं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की पूरी हो गईं, कुल 333 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं



चंद्रदीप कुमार

मॉडल प्रोजेक्ट

दिल्ली के अपने दफ्तर में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्र

(एचएएम) भी शामिल था. इसमें परिचालन और रख-रखाव को परियोजनाओं का अभिन्न अंग बना दिया गया, जिससे सार्वजनिक-निजी भागीदारी की गुंजाइश पैदा हो गई, ठीक उसी तरह जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में किया जा रहा है. सरकार पूंजीगत खर्चों की 40 फीसद रकम अग्रिम अदा करेगी और बाकी 60 फीसद धनराशि वार्षिक तौर पर दी जाएगी. यह आमूलचूल बदलाव था और इसके साथ ऐसा ही एक नियम यह बना दिया गया कि प्रत्येक शहर के लिए एक ही ऑपरेटर होगा जिसे परियोजना दी जाएगी और जो उसके निर्माण के साथ-साथ 15 साल तक रख-रखाव का भी जिम्मेदार होगा. मिश्र कहते हैं, “इससे जल-मल प्रबंधन और जवाबदेही में भी सुधार आया, क्योंकि एजेंसी को लंबे वक्त तक काम करना है.”

एनएमसीजी ने उद्योगों के मलबे को शोधित करने पर भी ध्यान दिया. स्थानीय अधिकारियों के अलावा प्राधिकरण भी सालाना निरीक्षण करता है. इसकी वजह से नाटकीय सुधार आया और अगले पन्नों पर प्रकाशित विभिन्न केस स्टडी से पता चलता है, नदी के कई इलाके फिर से तरोताजा हो चुके हैं. यह पक्का किया गया कि पनबिजली परियोजनाओं के बांध से समय पर पानी छोड़ा जाए ताकि नदी के बहाव में कोई बाधा न आए. देखभाल सिर्फ नदी की ही नहीं, बल्कि उसकी घाटी के रख-रखाव की भी की गई है ताकि इलाके के भूमिगत जल स्तर में सुधार आए और जैवविविधता फलने-फूलने लगे.

बड़ी तादाद में डॉल्फिन की वापसी अच्छा संकेत है. नदी के किनारे रिवरफ्रंट मार्ग और वीथिकाओं का विकास किया जा रहा है ताकि स्थानीय लोग घूमने और दूसरे मनोरंजन के लिए वहां आ सकें. मिश्र कहते हैं, “हमने मिशन को आक्रामक ढंग से आगे बढ़ाया है और इसके नतीजे भी दिखाई दे रहे हैं.” एनएमसीजी ने 29,578 करोड़ रुपए की लागत से कुल 335 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें 142 पूरी हो चुकी हैं. चार्ट से पता चलता है कि कितना कुछ किया गया है, वहीं मिश्र स्वीकार करते हैं कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है. अलबत्ता अहम बात है समय पर काम पूरा करने की लगन और जोशो-खरोश. ■

एक नदी का ओर-छोर

2,525 किमी

लंबाई है गंगा नदी की, उत्तराखंड में गंगोत्री से लेकर पश्चिम बंगाल में गंगासागर तक

97

शहर और 4,457 गांव आबाद हैं मुख्य नदी के किनारे

28%

भारत के जल संसाधन में योगदान है गंगा और उसकी सहायक नदियों का

333

परियोजनाएं स्वीकृत हैं गंगा की सफाई के लिए

11

राज्य हैं नदी बेसिन में, मुख्य नदी पांच राज्यों से बहती है

29,751

करोड़ रुपए खर्च किए गए अब तक नमामि गंगे परियोजना पर

गंगा के लिए कार्य योजना

केंद्र सरकार की नमामि गंगे कार्यक्रम के पूरी हो चुकी और जारी परियोजनाएं. इस कार्यक्रम के तहत केंद्र और राज्य सरकारें व्यापक तरीके से गंगा की सफाई और संरक्षण के लिए सम्मिलित प्रयास कर रहे हैं

ग्राफिक: नीलांजन दास



उत्तराखंड

परियोजनाएं : 34

पूरी हो चुकी : 27

काम जारी है : 7

स्वीकृत खर्च : 1,151.81 करोड़ रु.

नदियां

गंगा : 32 परियोजनाएं

कोसी : 1 परियोजना

रिप्सना और बिंदाल : 1 परियोजना

बिहार

परियोजनाएं : 30

पूरी हो चुकी : 2

काम जारी है : 18

प्रस्तावित : 10

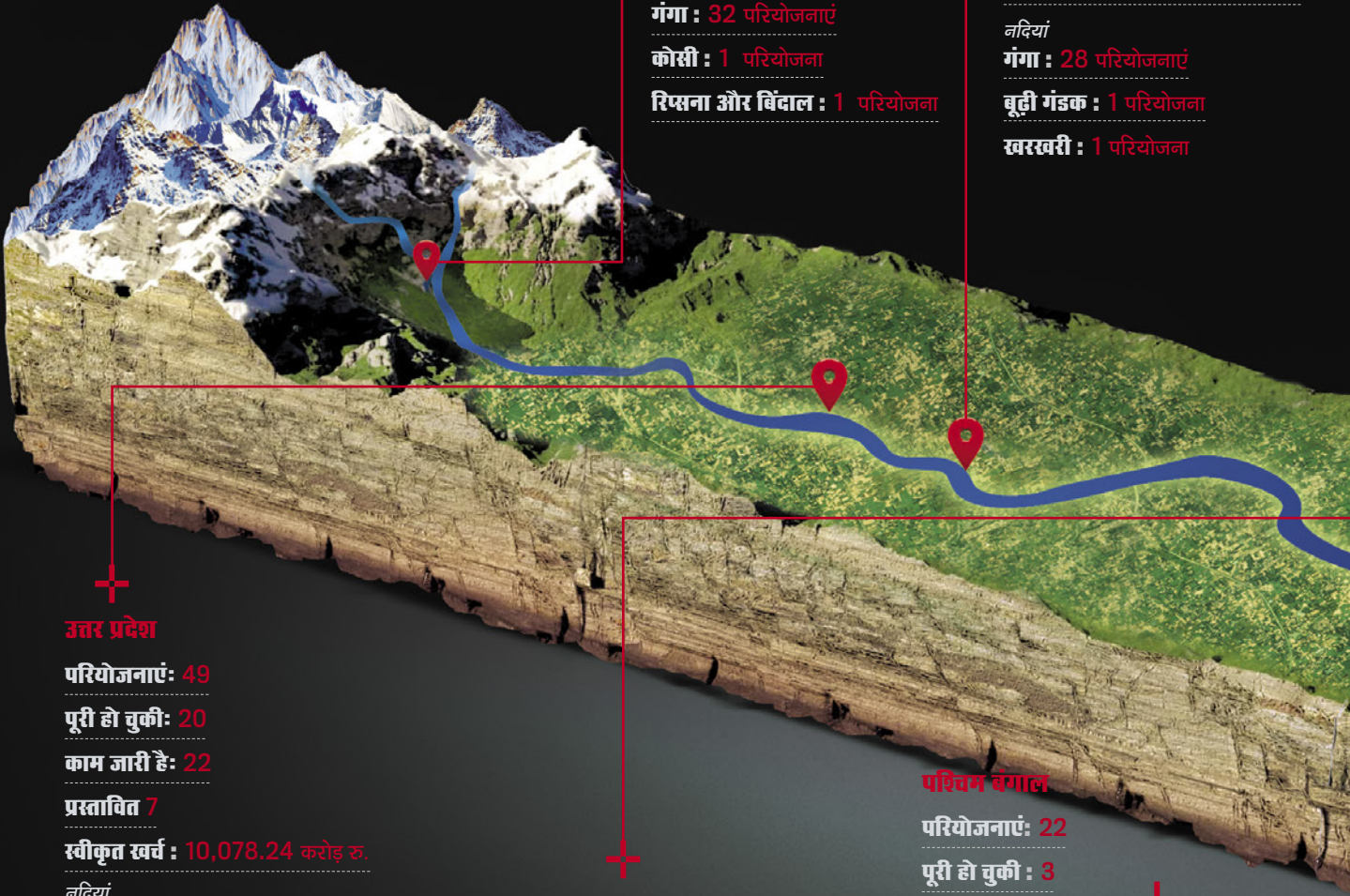
स्वीकृत खर्च : 5,328.30 करोड़ रु.

नदियां

गंगा : 28 परियोजनाएं

बूढ़ी गंडक : 1 परियोजना

खरखरी : 1 परियोजना



उत्तर प्रदेश

परियोजनाएं : 49

पूरी हो चुकी : 20

काम जारी है : 22

प्रस्तावित : 7

स्वीकृत खर्च : 10,078.24 करोड़ रु.

नदियां

गंगा : 32 परियोजनाएं

गोमती : 3 परियोजनाएं

काली (पूर्व) : 2 परियोजनाएं

काली (हिंडन) : 2 परियोजनाएं

रामगंगा : 3 परियोजनाएं

सरयू (घाघरा) : 1 परियोजना

यमुना : 6 परियोजनाएं

झारखंड

परियोजनाएं : 2

पूरी हो चुकी : 1

काम जारी है : 1

स्वीकृत खर्च :

156.12 करोड़ रु.

पश्चिम बंगाल

परियोजनाएं : 22

पूरी हो चुकी : 3

काम जारी है : 12

प्रस्तावित : 7

स्वीकृत खर्च :

3,815.95 करोड़ रु.

नदियां

गंगा : 19 परियोजनाएं

बंका : 1 परियोजना

दामोदर : 2 परियोजनाएं

सीवेज इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की स्थिति

गंगा मुख्य धारा



सीवेज जेनरेशन,
2016

वर्तमान स्थिति



1,240 एमएलडी

निष्पादन के विभिन्न चरणों में
30 सितंबर, 2020 तक की
क्षमता

एमएलडी: प्रति दिन दस लाख लीटर

और कामयाबी के लिए जारी परियोजनाएं

1,596

एमएलडी न्यू
एसटीपी क्षमता

1,481

किमी सीवर
नेटवर्क



सहायक

207

एमएलडी एसटीपी
क्षमता का निर्माण
किया गया

298

किमी सीवर
नेटवर्क तैयार
किया गया

156

कुल मल प्रबंधन परियोजनाएं

23,521

करोड़ रुपए कुल खर्च

335

परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं
नमामि गंगे के तहत

29,578

करोड़ रुपए
स्वीकृत खर्च

स्रोत: नमामि गंगे प्रोग्राम
एट ए ग्लांस, सितंबर 2020



चंद्रदीप कुमार

पवित्र काम

कानपुर निवासी फिरोज गंगा में मछली मारते हुए (बाएं); नदी-सफाई टीम का एक सदस्य नदी का पानी पीते हुए



चंद्रदीप कुमार

बदलाव की बयार

कानपुर के विभिन्न नालों, खासकर सबसे बड़े सीसामऊ नाला, की टैपिंग करने के बाद गंगा के प्रदूषण में इस शहर के योगदान में उल्लेखनीय कमी आई है

आशीष मिश्र

कानपुर के ग्वालटोली इलाके में रहने वाले 40 वर्षीय फतेह अली पिछले साल तक सब्जी बेचते थे. अब उन्होंने ग्वालटोली के खलासीलाइन के शूटरगंज में आसपास बसे कई अन्य परिवारों की तरह मछली बेचने का धंधा शुरू कर दिया है. सब्जी बेचने से पहले उनको जितनी कमाई होती थी अब वह उससे दोगुना कमा लेते हैं.

आखिर मछली पकड़ना उनके लिए आय का वैकल्पिक स्रोत कैसे बन गया है? इसका मूल कारण स्वच्छ गंगा है, जिसकी वजह से मछलियां पानी की सतह पर फिर से वापस आने लगीं और उन्हें पकड़ना आसान हो गया. सबसे जरूरी सवाल यह है कि गंगा साफ कैसे हुई? अंग्रेजों ने 1892 में कानपुर के गंदे पानी की निकासी के लिए सीसामऊ नाले का निर्माण कराया था. देश के सबसे बड़े इस खुले नाले की टैपिंग करके ऐसा संभव हो पाया है.

करीब 15 लाख लोगों के आवास वाले 40 मोहल्लों से गुजरता हुआ सीसामऊ नाला 12 किलोमीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा था जिससे हर रोज करीब 140 एमएलडी (प्रति दिन मिलियन लीटर) प्रदूषित जल और सीवेज कानपुर में 'रिवर साइड पावर हाउस' के पीछे गंगा में गिरता था. लेकिन मार्च 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार के सत्ता में आने के बाद 27 जुलाई, 2017 को इस नाले के टैपिंग पर काम शुरू हुआ.

बड़ी तस्वीर

● **समस्या** करीब 15 लाख लोगों के निवास वाले 40 मोहल्लों से गुजरता हुआ सीसामऊ नाला 12 किमी लंबा और 6 मीटर चौड़ा था जिससे रोजाना करीब 140 एमएलडी प्रदूषित जल गंगा में बहता था

● **समाधान** कानपुर के बकरमंडी में एक टैपिंग पॉइंट बनाने के बाद सीसामऊ नाले का 80 एमएलडी पानी बिंगवान एसटीपी भेजा गया

इसे पूरा करने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत दो-स्तरीय रणनीति की योजना बनाई गई थी. इस प्रोजेक्ट से जुड़े रहे जल निगम के एक जूनियर इंजीनियर बृजेन्द्र पुष्पाकर कहते हैं, "कानपुर के बकरमंडी में एक टैपिंग पॉइंट बनाने के बाद सीसामऊ नाले का 80 एमएलडी पानी बिंगवान सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) में भेजा गया. यहां पानी को साफ किया जाता और पांडु नदी में छोड़ दिया जाता. इसके अलावा 60 एमएलडी पानी को सीसामऊ नाले के बहाव की ओर एक टैपिंग पॉइंट बनाकर नदी के किनारे स्थित पावर हाउस के पास नवनिर्मित पंपिंग स्टेशन भेजा गया. यहां से पानी को पंप करके जाजमऊ एसटीपी में भेजा जाता. इस तरह शुद्ध किए गए पानी को जाजमऊ नहर में छोड़ दिया जाता था." 28 करोड़ रुपये की लागत के बाद दिसंबर 2018 को सीसामऊ नाला पूरी तरह बंद हो गया. कानपुर के आठ अन्य छोटे नालों को भी इसी तरह टैप कर दिया गया है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गंगा के पानी की गुणवत्ता की जांच करने के लिए अब कानपुर के गंगा बैराज और बिटूर में रियल-टाइम सेंसर स्थापित किए हैं. दिसंबर 2020 में प्रकाशित बोर्ड की डेटा रिपोर्ट के मुताबिक, अब कानपुर में बहने वाली गंगा नदी में डिजाल्वड ऑक्सीजन (डीओ) का अनुमानित स्तर 8.51 है, जो चार साल पहले की तुलना में पांच लेवल पर बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट था. डीओ के लिए मानक स्तर पांच से ऊपर है. कानपुर के कमिशनर राजशेखर कहते हैं, "अब लोग गंगा का पानी पीते भी हैं. वास्तव में यह एक बड़ा बदलाव है." ■

रंजन राही

नदी का पुनरुद्धार

राज्य अपने सीवेज नेटवर्क सिस्टम को चाक-चौबंद कर रहा है ताकि उसके शहरों से गंगा में जाने वाला अपशिष्ट जल गंदगी से मुक्त हो

अमिताभ श्रीवास्तव



मोर्चे पर

बेऊर स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के प्रभारी कुमार सौरभ

कुमार सौरभ अपने कार्यालय—पटना के बेऊर स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी)—में प्रतिदिन सुबह 9 बजे पहुंच जाते हैं और 2.17 एकड़ क्षेत्र में फैले इस प्लांट का दौरा करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं। इस वोल्टास-संचालित सुविधा के संचालन और रखरखाव के प्रभारी, 33 वर्षीय सौरभ के दैनिक निरीक्षण का पहला पड़ाव प्राइमरी स्क्रीनिंग जोन होता है जहां बाहर से आने वाला अपशिष्ट जल सबसे पहले पहुंचता है। पर्यावरणीय इंजीनियरिंग में एम.टेक की डिग्री रखने वाले सौरभ कहते हैं, “यह एक पुरानी आदत-सी हो गई है। इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए मेरे यहां मौजूद रहने की आवश्यकता नहीं है। अपशिष्ट जल की सफाई स्वचालित तरीके से और निरंतर होती रहती है। प्राथमिक टैंक में अपशिष्ट जल के पांच मीटर के स्तर तक पहुंचने के साथ ही पंप स्वतः चालू हो होता है।”

गंगा नदी के कुल 2,525 किलोमीटर के

प्रवाह क्षेत्र में से 445 किलोमीटर, बिहार में है। इसलिए नमामि गंगे कार्यक्रम (एनजीपी) के लिए राज्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और अपशिष्ट नदी के लिए सबसे बड़ी परेशानी बना हुआ है। अकेले पटना से 250 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) प्रदूषित जल गिरता है।

इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि राज्य के लिए नमामि गंगे की 6,017.37 करोड़ रुपए की निधि का 92 प्रतिशत या 5,487.75 करोड़ रुपए सीवेज ट्रीटमेंट (अपशिष्ट शोधन) की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए आवंटित की गई है।

2009 बैच के आइएएस अधिकारी, रमन कुमार की अगुवाई में शहरी विकास निकाय बीयूआइडीसीओ (बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम), सीवेज ट्रीटमेंट और जल निकासी की 30 परियोजनाओं को

संभाल रहा है। 15 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (एसटीपी) में से तीन पहले ही चालू हो चुके हैं, नौ अन्य प्लांट्स का कार्य पूरा होने के विभिन्न चरणों में हैं, जबकि तीन अन्य प्लांट्स जिन्हें मुंगेर, बक्सर और हाजीपुर में स्थापित किया जाना है, की निविदा प्रक्रिया चल रही है। बीयूआइडीसीओ को 15 इंटरसेप्शन और डायवर्जन परियोजनाएं भी सौंपी गई हैं, जिनमें से 12 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं और तीन परियोजनाओं की निविदा प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

11 एसटीपी और जल निकासी परियोजनाओं में से अधिकतर पटना में हैं; स्वीकृत परियोजनाओं को शामिल कर लिया जाए तो पूरे राज्य की सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता 651.5 एमएलडी हो जाएगी। वहीं, इनमें से दो परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, 22 परियोजनाएं प्रगति पर हैं और छह परियोजनाएं काम कर रही हैं।

150 करोड़ रुपए के पटना के दो प्रोजेक्ट-37 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) क्षमता वाला करमलीचक और 43 एमएलडी के ट्रीटमेंट क्षमता वाला बेऊर-टाटा समूह की कंपनी वोल्टास को सौंपे गए हैं। सितंबर 2020 से बेऊर एसटीपी चालू हो गया है।

बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. अशोक घोष कहते हैं, “बिहार में गंगा के पानी में सिर्फ 5 फीसद हिस्सा उस ‘गंगाजल’ का है, जिसकी उत्पत्ति हिमालय में होती है।” उम्मीद है नमामि गंगे से स्थिति बदलेगी। ■

बड़ी तस्वीर

● **समस्या** यहां अपशिष्ट की निकासी सबसे बड़ा मसला है। अकेले पटना 250 एमएलडी अपशिष्ट जल पैदा करता है

● **समाधान** बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम (बीयूआइडीसीओ) 30 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स और 15 ड्रेनेज परियोजनाओं को संभाल रहा है



दक्षिण का गान

इंडिया टुडे कॉन्क्लेव साउथ 2021 में जीवन के हर क्षेत्र के वक्ताओं ने मंच संभाला—नेता, एंटरटेनर, उद्योगपति और समाजसेवी. लेकिन 12 और 13 मार्च को चेन्नै में संपन्न इस दो दिवसीय आयोजन में चर्चा का मुख्य विषय तो तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और केरल में होने जा रहे विधानसभा चुनाव ही थे. सियासत और अभिव्यक्ति की आजादी पर बहस से लेकर महामारी के बाद के परिवेश के लिए भारत के ब्लूप्रिंट पर चर्चा—कॉन्क्लेव ने कितने ही विषयों को नजदीक से जाकर पकड़ा

फोटो: बंदीप सिंह, यासिर इकबाल और चंद्रदीप कुमार



दीप जले

इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस-चेयरपरसन कली पुरी कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री ई.के. पलानीस्वामी (बाएं); और डीएमके नेता एम.के. स्टालिन के साथ



“मैं डीएमके नेता (एम.के. स्टालिन) को चुनौती देता हूं कि वे मंच पर आएँ और मुझसे आमने-सामने बहस करें”

इडापट्टी के. पलानीस्वामी
मुख्यमंत्री, तमिलनाडु



“आधिकारिक रूप से क्रिप्टोकॉरेन्सी पर रिजर्व बैंक ही कोई फैसला ले सकता है पर इस मामले में हमने सारे दरवाजे बंद नहीं किए हैं”

निर्मला सीतारमण
केंद्रीय वित्त मंत्री



“मेरे ख्याल से हम बड़े आत्मविश्वास के साथ इससे (चीन से विवाद) निबटे. इसके लिए सेना को राजनैतिक नेतृत्व ने हर जरूरी सहयोग दिया”

एस. जयशंकर विदेश मंत्री



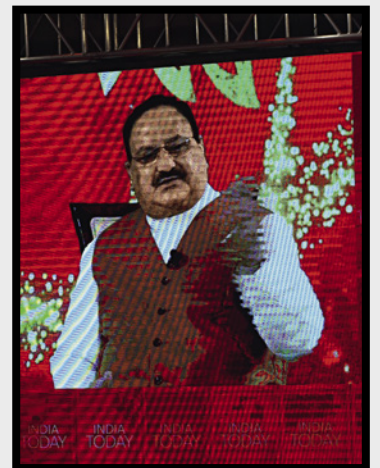
“एआइएडीएमके का राज तो बस एक महीने में खत्म होने जा रहा है. मुख्यमंत्री पलानीस्वामी तो अपनी खुद की सीट इडापट्टी भी जीत नहीं पाएंगे”

एम.के. स्टालिन
अध्यक्ष, द्रविड़ मुनेत्र कलगम



“तमिलनाडु की राजनीति पूरी तरह से बदल चुकी है और 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए की इमेज भी बदली है”

जगत प्रकाश नड्डा
राष्ट्रीय अध्यक्ष,
भाजपा





“साठ साल के अभिनय के अपने करियर में मैंने तारीफ और आलोचनाएं बहुत देखी हैं पर इतना प्यार कहीं नहीं देखा (जितना मुझे राजनीति में मिला)”

कमल हासन

अभिनेता और संस्थापक अध्यक्ष, मक्कल नीति मैयम

“यह उत्तर-दक्षिण या सक्षम-अक्षम की बात नहीं है. आप क्या रच रहे हैं, वह मायने रखता है. एहसासों की कोई जबान नहीं होती.”

अदिति राव हैदरी
अभिनेत्री

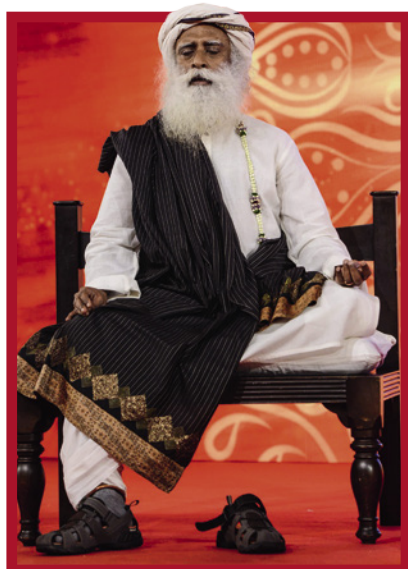


“(केंद्र) सरकार ने अभिव्यक्ति की आजादी और चुनने का अधिकार छीन लिए हैं”

कनिमोली करुणानिधि
डीएमके सांसद

“रजनीकांत आते तो वे जयललिता और एम. करुणानिधि जैसी शरिस्सयतों के जाने से राजनीति में बने खालीपन को दूर कर सकते थे”

एस. गुरुमूर्ति
संपादक, तुगलक



“हम तमिलनाडु के करीब 1,000 मंदिरों का डॉक्युमेंटेशन कर रहे हैं. संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि यहां के मंदिर बहुत बुरी हालत में हैं.”

सद्गुरु जग्गी वासुदेव
संस्थापक, ईशा फाउंडेशन





“एक (भाजपा) है जो सेकुलरिज्म के बारे में डर पैदा करती है और दूसरी (कांग्रेस) भ्रामक उम्मीदें जगाती है. सेकुलरिज्म को जिंदा रखने की जिम्मेदारी हमेशा मुसलमानों पर ही आती है”

असदुद्दीन ओवैसी
अध्यक्ष, एआइएमआइएम



“कांग्रेस बेशक मुश्किलों का सामना कर रही है लेकिन वह राजनीति के मोदी मॉडल से निबटने को तैयार है”

पी. चिदंबरम
कांग्रेस सांसद



“एआइएडीएमके और डीएमके का सियासी टकराव उद्योग क्षेत्र से दूर ही रहा, इसलिए वे फले-फूले”

एन. श्रीनिवासन,
उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, इंडिया सीमेंट्स



“यह (एआइएडीएमके) सरकार तो केंद्र की गुलाम जैसी है. शासन में पूरा भ्रष्टाचार है और नैतिकता नाममात्र की भी नहीं बची है”

ए. राजा
डीएमके सांसद



“कमल हासन तो भाजपा की बी टीम हैं और इस काम को वे पूरी बेशर्मी के साथ अंजाम दे रहे हैं”

दयानिधि मारन
डीएमके सांसद



“तमिलनाडु
एआइएडीएमके की
वापसी चाहता है।
इस सरकार ने वादों
से आगे बढ़कर कर
दिखाया है”

एस्पायर के स्वामीनाथन
सचिव, आइटी विंग,
एआइएडीएमके



“भाजपा
एआइएडीएमके के
साथ एक नकारात्मक
पहलू जोड़ती है जबकि
हम डीएमके गठजोड़
की सेकुलर चमक
बढ़ाते हैं”

कार्ति पी. चिदंबरम
कांग्रेस सांसद



“अब यह पूरी तरह से
साफ हो गया है कि देश
भर के लोग विकास
चाहते हैं और कांग्रेस
विकास का काम कभी
नहीं कर पाई”

कृष्ण सागर राव
प्रवक्ता, भाजपा



“बीसीके सामाजिक
न्याय की पैरोकार
है. चुनावी राजनीति
की हम कभी परवाह
नहीं करते”

तोल. तिरुमवालवन
सांसद और अध्यक्ष,
विदुतलाइ चिरुतैगल काच्चि



बंधन न कोई

गायक और संगीतकार **युवान शंकर राजा**,
कॉन्क्लेव में यह बताते हुए कि “संगीत में
भाषा की कोई लड़ाई नहीं है”



ताकतवर जोड़ी

अभिनेत्री और उद्यमी **राधिका सरतकुमार**
(बाएं) और उनके पति **आर. सरतकुमार**, अभिनेता
और संस्थापक, ऑल इंडिया समतुआ मक्काल काच्चि



देश का नं. 1 हिंदी न्यूज़ ऐप

जुड़े रहिए हर खबर से,
कहीं भी, कभी भी

अभी डाउनलोड करें

aajtak.in/app

उपलब्ध है





सभी फोटो: मनोज कुमार स्वैन

एसिड अटैक

तेजाबी जख्मों पर मरहम

ओडिशा के एक युवक ने तेजाबी हमले की पीड़िता से विवाह कर उसे दिया नया जीवन।
लेकिन ऐसी सैकड़ों अन्य जिंदगियां शारीरिक और मानसिक संत्रास में जीने को अभिशप्त

महेश शर्मा

तेजाबी छपाक से बुरी तरह झुलसीं ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले की प्रमोदिनी राउल अब श्रीमती प्रमोदिनी साहू बन चुकी हैं। पांच साल पहले इलाज के दौरान उनकी जिंदगी में सरोज साहू आए और अस्पताल में देखभाल करने लगे। उन्हें ऐसी सहानुभूति हुई कि उन्होंने प्रमोदिनी और उनके परिजनों का दिल जीत लिया। दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि दोनों ने सनातनी रीतिरिवाज से एक मार्च को विवाह कर लिया। विवाह उनके मूलस्थान जगतसिंहपुर जिले में ही संपन्न हुआ। भुवनेश्वर में 2 मार्च को रिसेप्शन था जिसमें दोनों को आशीर्वाद देने राज्यपाल प्रो. गणेशीलाल समेत कई मंत्री

और गणमान्य नागरिक मौजूद थे। भारी संख्या में लोगों ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। प्रमोदिनी के तेजाबी जख्मों को परिणय के मरहम ने कुछ ऐसा छुआ कि वे खुशी से फूली नहीं समा रही थीं।

उसे पर तेजाबी छपाक की घटना 2009 की थी तब प्रमोदिनी 16 की वय वाली एक खूबसूरत युवती हुआ करती थीं। अर्धसैनिक बल का जवान उसे इकतर्फा प्यार करने लगा। पर वह उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एक दिन मोटरसाइकिल से अपने दोस्त के साथ आकर अचानक उसने प्रमोदिनी को तेजाब से नहला दिया। यह तेजाबी छपाक प्रमोदिनी को बुरी तरह झुलसा गया। खेल और नृत्य में अपना भविष्य सवारने में जुटीं प्रमोदिनी ने

सोचा भी न था कि कोई वहशी उसका यह हाल कर देगा। वे बताती हैं, “ऐसा लगता था जैसे प्लास्टिक की तरह मेरा शरीर गल रहा है। बाल तक उड़ गए। एक आंख पूरी तरह गल चुकी थी और एक आंख से 60 प्रतिशत ही दिखता है।” इलाज के दौरान दवा सप्लाई का काम करने वाले युवक सरोज साहू की एक परिचित नर्स ने प्रमोदिनी की दर्द भरी कहानी उसे सुनाई। सरोज सहानुभूतिवश उनकी देखभाल करने लगा। दोनों की दोस्ती प्यार में कब बदल गई, पता ही नहीं चला।

सरोज अपना अधिक समय अस्पताल में प्रमोदिनी की देखभाल में बिताने लगे। इस कारण उनकी नौकरी भी जाती रही। धीरे-धीरे सरोज और प्रमोदिनी का प्यार परवान चढ़ने

लगा. दरअसल, प्रमोदिनी के पिता का निधन हो चुका है. नाते रिश्तेदार भी उनसे किनारा करते गए. उनकी जिंदगी में सरोज ही बचे थे जो उन्हें अच्छी तरह समझते थे. शीरोज नाम की एक संस्था और ओडिशा की सामाजिक कार्यकर्ता शुभाश्री दास की मदद से लखनऊ में दोनों की सगाई संपन्न हुई. प्रमोदिनी बताती है कि घटना के वर्ष 2009 से 2016 के बीच उन्हें धमकियां भी मिलती रहीं. आखिरकार 2017 में जाकर आरोपी गिरफ्तार हुआ और अब जेल की हवा खा रहा है. दोनों के विवाह में सक्रिय रहीं सोशल वर्कर शुभाश्री दास का कहना है कि “एसिड पीड़िताओं को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है. सरकार, बड़े-बड़े एनजीओ और कॉर्पोरेट घराने आगे आए तो यह कोई मुश्किल काम नहीं है.” शुभाश्री के अनुसार शीरोज कैफे का प्रस्ताव उन्होंने खुद राज्य सरकार को दिया है.

पांच साल में 700 से ज्यादा एसिड अटैक

महिला सम्मान को लेकर किए जाने वाले बड़े-बड़े दावों के बीच पूरे देश में 2014 से 2018 के बीच 700 से ज्यादा एसिड अटैक की घटनाएं सामने आई हैं जिसमें उत्तर प्रदेश में 260, पश्चिम बंगाल में 248, दिल्ली में 114, मध्य प्रदेश में 59, ओडिशा में 52, पंजाब में 50, आंध्र प्रदेश में 47, हरियाणा में 46, बिहार में 39 और गुजरात में 37 मामले एसिड अटैक के सामने आए हैं. हालांकि ये वे आंकड़े हैं जो सरकारी दस्तावेजों में दर्ज हैं. जबकि दावा है कि यह संख्या असल घटनाओं के मुकाबले बेहद कम है.

पुनर्वासन और सख्त कानून की जरूरत

तेजाबी हिंसा के उन्मूलन पर एसिड सरवाइवर्स ऐंड वीमेन वेलफेयर फाउंडेशन की ओडिशा अध्यक्ष और महिला आयोग की पूर्व सदस्य नम्रता चट्टा बताती हैं कि उनकी संस्था ने ओडिशा में 70 एसिड अटैक सरवाइवर्स में से दस को पूरा सपोर्ट दिया है. उनका कहना है कि तेजाबी हमले की घटना के वक्त लंबे-चौड़े वादे कर दिए जाते हैं लेकिन बाद में सरकारें भी मुआवजा देकर पल्ला झाड़ लेती हैं. उनके मुताबिक, “26 तरह की विकलांगता में एसिड अटैक पीड़िताएं भी हैं. विकलांगों के लिए नौकरी में दो प्रतिशत आरक्षण है पर इसका लाभ एसिड अटैक पीड़िताओं को आज तक नहीं मिला. इस बाबत मैंने सरकार को लिखा भी है. लेकिन जब बात की जाए तो जवाब में आश्वासन मिल जाता है बस.”



छपाक-से पहचान ले गया

■ एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, 2014 से 2018 के बीच देशभर में एसिड अटैक की 700 से ज्यादा घटनाएं सामने आईं

■ एसिड अटैक के सबसे ज्यादा 260 मामले उत्तर प्रदेश के थे. उसके बाद पश्चिम बंगाल (248), दिल्ली (114) और मध्य प्रदेश (59) का नंबर था. ओडिशा में इस तरह की 52 घटनाएं दर्ज की गईं

■ जानकारों के मुताबिक, इस तरह के बहुत-से मामले तो पुलिस तक आ ही नहीं पाते. कई बार तो हमलावर ही पीड़िता को डरा-धमकाकर चुप करा देते हैं

■ बहुत-से मामलों में देखने में आया कि एकतरफा प्यार में खारिज किए जाने पर सिरफिरे आशिक ऐसे हादसे अंजाम देते हैं

नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की एक रिपोर्ट के हवाले से नम्रता बताती हैं कि ओडिशा में 2011 से 2019 के बीच ओडिशा में एसिड अटैक के 70 मामले प्रकाश में आए. इनमें से 44 फीसदी एसिड अटैक सरवाइवर्स सिर्फ उत्तर भारत की हैं तो 27 प्रतिशत पूर्वी भारत की. ओडिशा पूर्वी भारत का राज्य है. कानून के मुताबिक, एसिड अटैक करने वालों को 10 साल की सजा या उम्र कैद हो सकती है. एसिड की उपलब्धता पर भी सख्ती बरती जानी चाहिए. इसके लिए सुप्रीमकोर्ट के दिशानिर्देश भी हैं.

मिनती पर पति ने तेजाब डाला

ओडिशा में एसिड सरवाइवर्स के रूप में कुछ और चौकाने वाली घटनाएं प्रकाश में आईं. प्रमोदिनी को तो सुंदर-से पति के रूप में सरोज मिल गए लेकिन ब्रह्मपुर जिले के कविसूर्यनगर की मिनती प्रधान के चेहरे पर उसके शक्की मिजाज पति ने ही तेजाब उड़ेल दिया. यह घटना

मेडिकल कॉलेज परिसर में ही 16 नवंबर 2007 को हुई. वे वहीं पर डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्निशियन (डीएमएलटी) कोर्स कर रही थीं. पति को बाद में जमानत मिल गई. मिनती बताती हैं कि पति समझौते के लिए धमकी भी देता है. उनकी एक आंख और चेहरा खराब है. तीन बहनों में सबसे बड़ी मिनती घर का खर्च भी देखती हैं. उन्हें लैब में कांटैक्चुअल नौकरी मिली थी, अब वह भी छूट गई.

कालाहांडी जिले के कलामपुर की 22 वर्षीया पूनम सिंहल को एकतरफा चाहने वाले सिरफिरे आशिक ने 17 अक्टूबर 2000 को सरेबाजार तेजाब से नहला दिया. वे पांच साल तक कटक और फिर दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज कराती रहीं. बेरोजगार पूनम आजकल परिवार के साथ दिल्ली में हैं. इसे एसिड अटैक का पहला बड़ा केस बताया जाता है. कालाहांडी की दमयंती बिहारी पर 15 जनवरी 2018 को एकतरफा प्रेम में तेजाबी हमला किया गया. दो साल बाद जाकर आरोपी परशुराम गिरफ्तार किया गया. दमयंती भुवनेश्वर के पुश आश्रम में रहकर स्टेनोग्राफी और कंप्यूटर सीख रही हैं.

देखने में आया है कि इस तरह के अधिकांश वाकए एकतरफा प्यार के आवेश में आशिक लड़कों की ओर से अंजाम दिए जाते हैं. और इस तरह से वे एक जीवन को तबाह और बर्बाद कर देते हैं. इसी तरह की एक घटना गंजम जिले के गंजपुर गांव में हुई. वहां मामुनी बिर्सोई पर 2018 में एकतरफा प्यार में तेजाब फेंका गया. आरोपी पकड़ा गया और फिलहाल जेल में है. कटक मेडिकल कालेज में मामुनी की आठ सर्जरी की गई. अनुसूचित जाति की मामुनी के पिता ठेका मजदूर हैं. कंधमाल के फुलबानी की अनाथ बच्ची संगीता पर तो उस वक्त तेजाब फेंका गया था जब वह आठ साल की थी. संगीता एक घर में नौकरानी थी और वहीं मालिक के बेटे ने इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया. वे सुभद्राश्रम में रह रही हैं. अब वे 18 साल की हैं और आइटीआई में टेलरिंग का प्रशिक्षण ले रही हैं.

चाहिए और सरोज

प्रमोदिनी बताती हैं कि सरोज उनका बहुत खयाल रखते हैं. “वे हृदय बहुत कोमल है. मैंने सोचा भी न था कि मेरे जीवन में कोई अजनबी आएगा और मेरा हमसफर बन जाएगा.” लेकिन एसिड अटैक का संत्रास झेल रही बाकी पीड़िताओं को उनका सरोज कब मिलेगा ? ■

सिनेमा

खुलेगा तो देखेंगे... दर्शक

नवीन कुमार

मुं

बई समेत पूरे महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामले बढ़ने के चलते लॉकडाउन का अंदेशा बढ़ने लगा है. लेकिन हिंदी फिल्मों बनाने वाले इससे अपने को अप्रभावित रखते हुए, करोड़ों रुपए खर्च करके जी-जान से काम में जुटे हैं. उनका अनुमान है कि अब महीने-दो महीने में हालात सुधरेंगे ही.

उस स्थिति में थिएटर खुलने पर लौटने

वाले दर्शकों के लिए भरपूर मसाला चाहिए होगा क्योंकि सिनेमा ही मनोरंजन का सबसे सुलभ माध्यम है. इसी के चलते कई बड़ी फिल्मों की शूटिंग जारी है. उम्मीद है कि सलमान खान और अक्षय कुमार सरीखे स्टार बड़े पैमाने पर दर्शक खींचकर लाएंगे. अक्षय की *सूर्यवंशी* 30 अप्रैल को और सलमान की *राधे ईद* पर रिलीज होगी.

महामारी के थोड़ा कमजोर पड़ते ही शूटिंग आदि के लिए मिली इजाजत का बेहतर इस्तेमाल अक्षय कुमार ने किया. फौरन लंदन जाकर *बेल बॉटम* की शूटिंग पूरी की, *पृथ्वीराज* खत्म कर ली और पिछले हफ्ते जैसलमेर जाकर *बच्चन पांडे* भी निबटा ली. अजय देवगन भी शूटिंग में मसरूफ हैं. एक महीने हैदराबाद में डेरा डालकर *मे डे* के अलावा फंसी हुई पुरानी फिल्म *भुज* भी कंप्लीट कर ली.

कोरोना के खतरे के चलते शूटिंग भी ज्यादातर मुंबई से बाहर ही हो रही है. मिलाप झवेरी के निर्देशन में जॉन अब्राहम ने *सत्यमेव जयते-2* की शूटिंग वाराणसी में, अक्षय कुमार ने *अतरंगी रे* की आगरा में, सिद्धार्थ मल्होत्रा ने *मिशन मजनुं* की लखनऊ में, वरुण धवन ने *भेदिया* की अरुणाचल प्रदेश में और तापसी पन्नू ने *लूप लपेटा* की शूटिंग गोवा में की. छोटे शहरों में शूटिंग का एक आकर्षण सब्सिडी भी है.

वैसे, छोटे बजट के निर्माता ज्यादा जोखिम नहीं ले रहे. थिएटर में उतरने वाली तीन फिल्मों से जुड़े कास्टिंग डाइरेक्टर कुणाल शाह के



1



2

शब्दों में, “15-20 करोड़ रु. लागत वाली फिल्मों फ्लोर पर नहीं जा रहीं. उनके निर्माताओं को दर्शकों के आने को लेकर अंदेशा है. इसका आधार है हाल ही रिलीज फिल्मों देखने के लिए भीड़ न उमड़ना. दूसरे, बड़े बैनरों की तरह छोटे निर्माता 15-20 करोड़ रु. फंसाकर नहीं रख सकते. वे दर्शकों का मूड पढ़ रहे हैं.” लेकिन यश राज, धर्मा, रिलायंस, साजिद नडियाडवाला जैसे बड़े प्रोडक्शन हाउस फिल्मों बना रहे हैं. पर हिंदी क्षेत्र के सिनेमाघरों को दक्षिण की तरह एक *मास्टर* का इंतजार है जिसने दर्शकों को थिएटर में आने पर मजबूर करके एक इतिहास रच डाला.

फिल्में फ्लोर पर भले न गई हों लेकिन मल्टीकलर कहानी दिखाने वाले लोग लॉकडाउन के दौरान भी व्यस्त रहे. आज किसी भी पटकथा लेखक या निर्देशक के पास 3-4 स्क्रिप्ट तैयार हैं, जिन्हें वह अभिनेताओं के सामने पिच करना चाहता है. फिल्म बिजनेस के विशेषज्ञ अतुल मोहन बताते हैं, “लेखकों की मांग बढ़ गई है. छोटे निर्देशक और अभिनेता भी व्यस्त हैं. ऐक्टर्स की कमी महसूस होने लगी है. एक मायने में लेखकों,



उतर पड़े मैदान में

1. अक्षय कुमार *राम सेतु* में पुरातत्वविद् की भूमिका में हैं। इसकी शूटिंग अयोध्या में मुहूर्त के बाद जल्द शुरू होने वाली है
2. गोवा में फिल्म *लूप लपेटा* की शूटिंग के दौरान एक सीन में तापसी पन्नू
3. मुंबई में फिल्म *ब्रह्मास्त्र* के सेट पर नागार्जुन, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट और अयान मुखर्जी
4. आगरा की केंद्रीय जेल में बने सेट पर *दसवीं* की शूटिंग के एक दृश्य में अभिषेक बच्चन



अभिनेताओं और टेक्नीशियंस का स्वर्णिम काल शुरू हो गया है। पोस्ट प्रोडक्शन के लिए टेक्नीशियंस ने घर पर ही सेटअप बना लिया है। स्टुडियो के खुलने का इंतजार करने की जरूरत नहीं। "लालरंग की निर्माता नीतिका ठाकुर के पास तीन पटकथाएं तैयार हैं। जी5 के *पॉइजन-2* के लेखक रेहान खान के पास फिल्म के लिए स्क्रिप्ट तैयार है जिसे उन्होंने 2022 में रिलीज करने की योजना बनाई है। *7 आवर्स टु गो* और *सॉलिड पटेल्स* के निर्देशक सौरभ वर्मा के पास तीन पटकथाएं रखी हैं। *नमस्ते लंदन*, *रेड*, *पिंक*, *बटला हाउस* और *द बिग बुल* के लेखक रितेश शाह गोवा में बैठकर स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। उनकी फिल्म *दसवीं* में अभिषेक बच्चन और यामी गौतम हैं जिसे नए निर्देशक तुषार जलोटा संभाल रहे हैं। शाहरुख खान और हितिक रोशन सरीखे अभिनेताओं ने भी दो-तीन स्क्रिप्ट लॉक कर ली हैं। बड़े प्रोडक्शन हाउस अपनी पारखी नजरें जमाए हुए हैं। धर्मा प्रोडक्शंस ने 14 प्रतिभाशाली निर्देशकों को साथ जोड़ लिया है जो ड्रामा, रोमांस, एडवेंचर, साइकोलॉजिकल थ्रिलर, कॉमेडी जोनर वाले सिनेमा और ओटीटी के लिए कहानियों पर काम कर रहे हैं। इनके नाम देखिए: शाजिया इकबाल, अमृतपाल बिंद्रा, करण सिंह त्यागी, पारस चक्रवर्ती, राज मेहता, अनुभूति कश्यप, कयोजी ईरानी,

शरण शर्मा, कोलिन डा कुन्हा, भानु प्रताप सिंह, आनंद तिवारी, पुष्कर ओझा, सागर आंब्रे, और विवेक सोनी। आलिया भट्ट ने भी प्रोडक्शन कंपनी खोल ली है, जिसकी पहली फिल्म होगी डार्लिंग्स. वासु भगनानी ने *सूर्यपुत्र महावीर कर्ण* के लिए कुमार विश्वास को संवाद, गाने और स्क्रीनप्ले लिखने की जिम्मेदारी सौंप ही दी है।

अतुल मोहन बताते हैं कि "सिनेमाघरों को तो स्टार ही चला सकते हैं। वे ही दर्शक खींचकर लाते हैं। साउथ के स्टारडम की हिंदी सिनेमा से कोई तुलना नहीं। वहां लोग अपने स्टार को पूजते हैं। वहां की ऑडिएंस विजय (*मास्टर* फेम), महेश बाबू, अल्लु अर्जुन वगैरह की दीवानी है। यहां ऐसा नहीं है। साउथ की ऑडिएंस पायरेसी के खिलाफ काम करती है। वहां टिकट भी 120-150 से ज्यादा नहीं होता और आगे की दो कतारें रिकशावालों के लिए होती हैं 10-20 रु. टिकट वाली। हिंदी फिल्मों के लिए 500-1,000 रुपए तक खर्चने पड़ते हैं। हिंदी सिनेमा सिर्फ अमीरों के लिए रह गया है।" कोविड की वजह से करीब 1,000 सिंगल स्क्रीन बंद हुए हैं। कई मल्टीप्लेक्स भी बंद हुए।

हाल में रिलीज हुई फिल्मों को दर्शक नहीं मिले। कुणाल का मानना है कि इससे ऐक्टर की ब्रांडिंग पर असर पड़ता है। हर चीज में ऐक्टर का बहुत कुछ दांव पर होता है। "अक्षय कुमार की फिल्म कम से कम 150-200 करोड़ रु. का बिजनेस करती है। सलमान की *प्रेम रतन धन पायो* के बारे में धारणा बनी कि वह नहीं चली लेकिन बिजनेस 400 करोड़ रुपए का है।" महामारी के दौर में कोई भी बड़ा ऐक्टर अपनी ब्रांडिंग दांव पर लगाने से हिचक रहा है। अतुल की राय है, "थिएटर में पब्लिक आ नहीं रही। वह आएगी तभी जब बड़ा कंटेंट आए. और यह तभी संभव है जब मुंबई-महाराष्ट्र के सिनेमाघरों में सौ फीसद सीटें भरने की गारंटी हो." फिल्म वितरण की बड़ी टेरिटीरी मुंबई में महाराष्ट्र और गुजरात आते हैं और 35-40 फीसद बिजनेस यहीं होता है। प्रोड्यूसर इसीलिए खतरा मोल नहीं उठा रहे।

ऐसे में ओटीटी वाले फिल्म वालों को बड़े ऑफर देकर ललचा रहे हैं। इसी वजह से मल्टीस्टार *सूर्यवंशी* की रिलीज डेट फाइनल नहीं हो पा रही थी। अब इसका सिनेमाघरों में ही रिलीज होना तय हो गया है। बड़े निर्माताओं के पास हर तरह की फिल्में हैं। मसलन टी सीरीज के पास सलमान की *राधे* है तो छोटे ऐक्टर्स की भी फिल्में हैं। वे स्क्रिप्ट पिच कर रहे हैं। इंडस्ट्री के लोग अच्छे दिनों के इंतजार में हैं। ■

सवाल + जवाब

चंचला फिर चमकने को बेताब

एमटीवी *स्प्लिट्सविला* की छह बार की होस्ट **सनी लियोनी** कभी आत्ममुग्ध नहीं होतीं. भारत आ बसने के दशक भर बाद भी उन्हें खुद को मौजूं बनाए रखना आता है

● आप एक बार फिर से *स्प्लिट्सविला* की होस्ट बनी हैं. आपको नहीं लगता कि ओटीटी के दौर में रियलिटी टीवी की अपील कुछ कम हो गई है?

एमटीवी डिजिटल मार्केट को भी बखूबी अपना रहा है. वूट सरीखे उसके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म ने इसमें मदद की है. अब एमटीवी वैसे ही सब कुछ संग, फ्रेश और चुस्त रखता है. मेरे ख्याल से हम अच्छी स्थिति में हैं.

● इंस्टाग्राम पर आप सबसे सक्रिय लोगों में से हैं. सोशल मीडिया को नियमित अपडेट करने का कोई दबाव महसूस करती हैं?

इंस्टाग्राम का मेरा पेज एक टीम संभालती है और हम मिलकर ताजा कंटेंट तैयार करते हैं. सच पूछिए तो सभी को काफी पहले डिजिटल मार्केट में उतरना पड़ना चाहिए था. अच्छा ही था कि नहीं उतरे. तभी तो मेरे लिए इतना कुछ निकल आया, उसके लिए शुक्रिया (हंसते हुए).

● लॉकडाउन में कुछ दिन आप लॉस एंजेलिस में रहीं. आप अमेरिका में ज्यादा सहज महसूस करती हैं या भारत में?

अब मैं अमेरिका में नहीं रहना चाहती. वहां माहौल खासा नकारात्मक हो गया है. कितनी नफरत भर गई है! भारत में नजारा पूरी तरह से अलग है. कितना प्यार और दुलार है यहां के लोगों में! कुछ न कुछ मसले तो हर देश में होते हैं पर मोटे तौर पर भारत में सब कुछ बेहद शानदार है.

● केरल के एक शो आयोजक ने हाल में आप पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया. कितने कठिन रहे हैं पिछले कुछ दिन?

हमारा केस मजबूत है, मुझे यकीन है न्याय की जीत होगी. मैं किसी का बुरा नहीं चाहती पर मुझे पता है कि सच मेरी तरफ है और इतना ही पर्याप्त होगा.

—श्रीवत्स नेवतिया

INDIA
TODAY

BREAKING NEWS

JUST A TAP AWAY



DOWNLOAD THE APP NOW

AVAILABLE ON



IndiaContent

**SEARCH FOR
EDITORIAL IMAGES
ENDS HERE**

